चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

लोकायुक्त सफ़ेद हाथी सीवीसी से क्या उम्मीद करें?

पेज 3

ग़रीब रिक्शेवाले कहां जाएंगे

पेज 5

एड्स की चपेट में मऊ

पेज 7

मैं कौन हूं

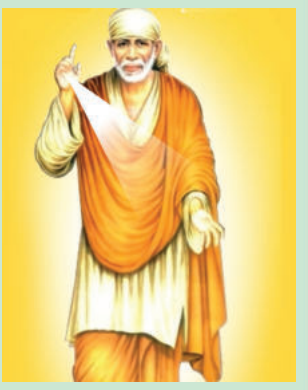

पेज 12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 23 अगस्त–29 अगस्त 2010

कॉमनवेल्थ गेम्स 2010

सबसे बड़ा घोटाला

आज़ाद भारत का सबसे बड़ा खेल समारोह नेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से सबसे बड़े घोटाले में तब्दील हो गया है. कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर हर तरफ़ लूट मची है. ऐसा लग रहा है कि देश में लूट का महोत्सव मनाया जा रहा है. हर मंत्रालय, हर विभाग के अधिकारी, नेता एवं बिचौलिए, जिन्हें जहां मौक़ा मिला, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं. क्या खेल संगठनों में राजनेताओं के शीर्ष पद पर होने की वजह यही है.जनता के पैसे की लूटखसोट के नए-नए तरीक़ों का ख़ुलासा हो रहा है. शक़ की सुई हर तरफ़ उठ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं, आडवाणी चुप हैं.

मनीष कुमार

कॉमनवेल्थ की असल कहानी यह है कि एक साल पहले दिल्ली से इस आयोजन को ख़त्म करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी. सात देशों ने यह मना कर दिया था कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं होने चाहिए. इसमें त्रिनिडाड एंड टुबैगो जैसा छोटा देश भी दिल्ली के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था. इन देशों का यह मानना था कि दिल्ली इस खेल को समय पर कराने में सक्षम नहीं है. सूत्रों के मुताबिक़, इनका मुंह बंद करने के लिए इन देशों के अधिकारियों को चालीस करोड़ रुपये दिए गए. हर अधिकारी को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए. सारे पैसे हवाला के ज़रिए दिए गए. अब देश का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जागा है तो कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर जो पैसे विदेश भेजे गए, उनकी तहक़ीक़ात हो रही है. हर दिन नई कहानी आ रही है और इन ख़ुलासों का सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा. याद रहे कि यह सरकारी अधिकारियों के इस ऐतिहासिक लूट महोत्सव का सबसे गौरवशाली पन्ना है.

एक मज़ेदार कहानी बताता हूं. प्रिंस हैरी रग्बी का मैच देखने दिल्ली आए, साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स के कई अधिकारी भी तैयारी का जायज़ा लेने आए थे. स्टेडियम देखकर सब दंग रह गए. घास वग़ैरह बिल्कुल हरी. स्टेडियम के चारों तरफ़ की सजावट देखकर सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए. खिलाड़ी भी ख़ुश थे कि दिल्ली में इतना शानदार स्टेडियम बन रहा है. विदेश से आए कुछ अधिकारियों को यक़ीन नहीं हुआ, वे सोच में पड़ गए कि ऐसा कायाकल्प कैसे हो सकता है. एक ने सोचा कि चलो दीवारों के पीछे देखते हैं कि आख़िर वहां क्या है. दीवारों के बीच जाकर देखा तो मज़दूर सो रहे थे, सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई थीं, ईंट-पत्थर बिखरे पड़े थे, गंदगी फैली हुई थी, सब कुछ ढंका हुआ था. जो भी कुछ स्टेडियम के अंदर से दिख रहा था, वह सब सिर्फ़ अच्छा दिखने के लिए बनाया गया था. सब दिखावा था. दीवारों के पार सब कुछ खोखला था. रिपोर्ट चली गई कि स्टेडियम खेल के लायक़ नहीं है. आज यही हाल दिल्ली में बन रहे सारे स्टेडियमों का है. कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाएंगे. ढांक-पोतकर स्टेडियमों को ख़ूबसूरत भी बना दिया जाएगा, लेकिन इस आयोजन के तीन महीने बाद कोई यह पूछने भी नहीं जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर जो स्टेडियम बनाए गए, सरकार का ख़ज़ाना जो लूटा गया, उसका क्या हुआ. जिस तरह से ये स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, वे खिलाड़ियों के किसी काम में नहीं आने वाले हैं. यहीं से हम कॉमनवेल्थ के नाम पर हो रही लूट, घपलेबाज़ी, भ्रष्टाचार और धोखे की कहानी शुरू करते हैं.

सबसे पहले बात करते हैं लंदन की कंपनी एएम फ़िल्म्स की, जिसे लेकर टीवी और अख़बारों में हंगामा हो रहा है. इसके बारे में एक अख़बार ने यह ख़ुलासा किया कि इस कार कंपनी को दिए गए पैसे में घपलेबाज़ी हुई है. एक अनजान एवं छोटी कंपनी को ओसी ने छह करोड़ रुपये दिए. हैरानी की बात यह है कि पहले कलमाडी ने सारे आरोपों को ख़ारिज किया. फिर इस मामले में दरबारी को हटाया गया और बाद में यह ख़ुलासा भी हो गया कि ए एम फिल्म्स को पैसे देने का आदेश कलमाडी ने दिया था. इस प्रकरण में आया सच, अर्धसत्य है. पैसे दिए गए, लेकिन असल कहानी कुछ और है. यह मामला क्वींस बैटन रिले की है. कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल की शुरुआत बकिंघम पैलेस से होती है. कलमाडी और अधिकारियों की इस बात के लिए तारीफ़ होनी चाहिए कि इसका बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया. इसमें 4-5 हज़ार लोगों के शामिल होने का अनुमान था, लेकिन 45 हज़ार लोगों ने इस आयोजन में शामिल होकर इसे ऐतिहासिक बना दिया. इसका आयोजन ऐसा हुआ कि जिसे देखकर किसी भी हिंदुस्तानी का सीना फूल जाए. इतने बड़े आयोजन के लिए पैसे भी जमकर ख़र्च किए गए, लेकिन सब कुछ आख़िरी वक़्त पर हुआ है. ग़लती यह हो गई कि कलमाडी एंड कंपनी पैसे को पहुंचा नहीं पाए. हड़बड़ी में इन्होंने अंतिम वक़्त में इस कार कंपनी के ज़रिए इंग्लैंड पैसे भेजे. उन्होंने जितने पैसे भेजे, वे कम पड़ गए. सूत्र बताते हैं कि इस आयोजन में लगे ज़्यादातर पैसे हवाला के ज़रिए लंदन भेजे गए. यह मामला सिर्फ़ छह करोड़ का है. कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर जिस तरह सरकारी ख़ज़ाने की लूट हुई, उसके सामने यह मामला बहुत ही छोटा है.

सोलह सौ करोड़ रुपये कॉमनवेल्थ के आयोजन का बजट है. इसमें पूरे तीन साल पहले मेलबर्न की बैटन रैली से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स के आख़िरी तक का ख़र्च शामिल है, जिसमें स्टेडियम और दिल्ली में बनने वाले ओवरब्रिज एवं सड़कों या इंफ्रास्ट्रक्चर का ख़र्च शामिल नहीं है. इस 1600 करोड़ में स्टेडियम के अंदर की सुविधाओं, ओपनिंग और क्लोजिंग के आयोजन और खेल-खिलाड़ियों के ख़र्च शामिल हैं. ओसी ने यह कहा था कि वह सरकार को यह पैसा लौटा देगी. इसमें तीन सौ करोड़ रुपये खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए दिए गए थे, ताकि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिल सकें. लेकिन इन तीन सौ करोड़ रुपये में अब तक चालीस करोड़ रुपये भी खिलाड़ियों पर ख़र्च नहीं किए गए हैं. अब सवाल यह है कि ये पैसे गए कहां? मीडिया में घोटाले की जो ख़बरें आ रही हैं, वे इन्हीं सोलह सौ करोड़ रुपये से हुए ख़र्च में घपलेबाज़ी का मामला है. इसमें ट्रेड मिल से लेकर इंग्लैंड की कंपनी ए एम फ़िल्म्स को दिए गए पैसे शामिल हैं. चौथी दुनिया की तहक़ीक़ात से पता चला है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो सामान ख़रीदा गया है, उसमें एक बड़ा हिस्सा दिपाली डिज़ाइन एंड एक्जिबिट्स नाम की कंपनी के ज़रिए ख़रीदा जा रहा है. इस कंपनी के पीछे भाजपा के नेता सुधांशु मित्तल का नाम जुड़ा है. इस कंपनी के मालिक सुधांशु मित्तल के क़रीबी रिश्तेदार हैं. इस कंपनी को ओसी ने कुल क़रीब 230 करोड़ रुपये दिए हैं. एक अनुमान के मुताबिक़ इन 230 करोड़ रुपये में जितने भी सामान ख़रीदे गए या किराए पर लिए गए, वे असल में 25 करोड़ रुपये के भी नहीं हैं. इस कंपनी के ज़रिए सारे सामान ख़रीदे नहीं गए हैं, बल्कि ज़्यादातर किराए पर लिए गए हैं. मतलब यह कि आयोजन के बाद हमारे स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है. उदाहरण के तौर पर ट्रेड मिल को ही ले लीजिए. 45 दिनों के किराए के रूप में इस कंपनी को एक ट्रेड मिल के लिए नौ लाख पचहत्तर हज़ार रुपये मिल रहे हैं. पता यह चला है कि यह कंपनी दिल्ली के स्थानीय दुकानों से एक लाख से कम किराया देकर ट्रेड मिल ले रही है और उसी ट्रेड मिल के लिए आयोजन समिति से नौ लाख पचहत्तर हज़ार रुपये ले रही है. मतलब यह कि ओसी एक सामान के लिए नौ गुना ज़्यादा रुपये ख़र्च कर रही है. हैरानी की बात यह है कि इस ट्रेड मिल की क़ीमत ही सिर्फ़ चार लाख रुपये है. यानी एक ट्रेड मिल के पैंतालिस दिनों के किराए से हम दो ट्रेड मिल ख़रीद सकते थे. टीशू पेपर का रोल कैसे ख़रीदा गया है, यह तो सचमुच चौंकाने वाला है. हमारे अधिकारियों ने कॉमनवेल्थ के लिए 3757 रुपये में एक रोल ख़रीदी है. बाज़ार में इसकी क़ीमत 30 रुपये है. इसे एसआर टीशू एंड फ्वाइल्स नाम की कंपनी से ख़रीदा गया. अगर ऐसी मूर्खतापूर्ण डील करनी थी तो आयोजन समिति में इतने पढ़े-लिखे लोगों की ज़रूरत क्या थी? ऐसा कौन सा छाता है, जिसका किराया ही छह हज़ार रुपया है और उसकी क्या ख़ासियत है, यह रहस्य आयोजन समिति के अधिकारियों को ज़रूर उजागर करना चाहिए. जनता के पैसे को किस तरह नाजायज़ ख़र्च किया गया है, इसे समझने के लिए किसी को जासूस बनने की ज़रूरत नहीं है. सब कुछ सामने है. लिए गए सामानों की वास्तविक क़ीमत और उनके लिए अदा की गई क़ीमत अथवा किराए में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ देखकर कोई सामान्य समझ वाला शख़्स ही बेधड़क बता देगा कि यह खुल्लमखुल्ला लूट है.

तीन सौ करोड़ रुपये खिलाड़ियों पर ख़र्च करना था. हैरानी की बात यह है कि हमें यह भी पता नहीं है कि हॉकी का कैंप कहां हो रहा है, बिलियर्ड्स की ट्रेनिंग कहां होगी, एथलेटिक्स की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कहां हो रही है, यह किसी को पता तक नहीं है. शूटिंग का भी वही हाल है, जबकि हमें पता है कि इसमें भारत को मेडल मिल सकता है. असलियत तो यह है कि अभी तक टीम की भी घोषणा नहीं हुई है. एक महीना रह गया है, लेकिन कैंप तक शुरू नहीं हो पाया है. कोई स्टेडियम ठीक से तैयार नहीं है. सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया गया है.

चौथी दुनिया की तहक़ीक़ात से पता चला है कि ओसी के ज़्यादातर अधिकारियों को पता था कि ख़रीददारी और आयोजन में भीषण घपलेबाज़ी हो रही है. यही वजह है कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल खन्ना जो ओसी के खजांची थे, ने इस्तीफ़ा दे दिया. उन्होंने दो महीने से किसी भी चेक पर साइन करना बंद कर दिया था. उन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली में चल रहे 15 निर्माण कार्यों पर उंगली उठाई और ख़राब गुणवत्ता की बात कही. ज़्यादा क़ीमत पर टेंडर दिए जाने की भी बात की. अयोग्य एजेंसियों से काम कराने की भी शिकायतें सामने आईं.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सभी फोटो- प्रभात पाण्डेय

एक बार कोई कैबिनेट सचिव के पद पर पहुंच जाए तो वह चार साल तक इस पर बना रहेगा, जबकि इस बीच कई अन्य अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे.

दिल्ली का बाबू

फ़ैसले के पीछे क्या है?

देश के शीर्ष नौकरशाहों की जमात पहले ही कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर को एक साल के सेवा विस्तार से हैरत में थी, लेकिन कैबिनेट सचिव के लिए चार साल की निश्चित कार्यावधि के केंद्र सरकार के फ़ैसले ने तो मानों उनके पैरों तले की ज़मीन ही खिसका दी है. इस फ़ैसले के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र पार करने के बाद भी कैबिनेट सचिव चार साल तक अपने पद पर बना रहेगा. अधिकांश अधिकारियों का मानना है कि यह फ़ैसला नौकरशाही को हतोत्साहित करने वाला है. उनका तर्क है कि एक बार कोई कैबिनेट सचिव के पद पर पहुंच जाए तो वह चार साल तक इस पर बना रहेगा, जबकि इस बीच कई अन्य अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जो हर तरह से योग्य होने के बावजूद इस शीर्ष पद के लिए दावा भी नहीं कर पाएंगे. चाहे जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि सरकार के इस फ़ैसले से कैबिनेट सचिव का पद राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहेगा. गठबंधन सरकारों के इस दौर में नौकरशाही में स्थायित्व बेहद ज़रूरी है. चंद्रशेखर को सेवा विस्तार दिए जाने से 1972 और 1973 बैच के किसी भी आईएस अधिकारी की कैबिनेट सचिव बनने की लालसा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जून, 2011 में जब चंद्रशेखर अपने पद से हटेंगे, तब तक इन दोनों बैच के सारे अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके होंगे. नौकरशाही के गलियारों में ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं यह फ़ैसला पुलक चटर्जी की ताजपोशी का रास्ता आसान करने के लिए तो नहीं लिया गया है. 1974 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के चटर्जी फ़िलहाल विश्व बैंक के साथ जुड़े हैं और उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ-साथ अन्य सत्ता केंद्रों का भी विश्वास हासिल है.

दिलीप चेरियन

लोगो के लिए मची होड़

रुपये के लिए एक सिंबॉल (संकेत चिन्ह) क्या अपनाया गया, सरकारी विभागों के बीच सिंबॉल के लिए जैसे होड़ सी लग गई है. महालेखाकार एवं नियंत्रक परीक्षक (सीएजी) विनोद राय को लगता है कि भारत के लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को एक नई छवि की ज़रूरत है. सीएजी जहां एक ओर ज़्यादा अधिकार और सरकार में ज़्यादा विस्तृत भूमिका पर ज़ोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके विभागीय अधिकारी अलग से एक लोगो की मांग कर रहे हैं. इस बीच यह ख़बर भी मिल रही है कि भारतीय रेलवे ने भी अपने लिए एक नए लोगो की मांग की है. राय ने सरकार से यह मांग की है कि उनके विभाग को नियामक आयोगों पर निगरानी का अधिकार होना चाहिए. ग़ौरतलब है कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बनी नियामक संस्थाएं किसी भी स्वतंत्र निकाय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं. यदि राय की कोशिशें सफल रहती हैं तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस नियामक आयोग (पीएनजीआरबी) और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) जैसी संस्थाएं सीएजी की निगरानी में आ जाएंगी. इसके साथ नया लोगो मिल जाए तो वह सीएजी के बढ़े अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रतिबिंबित करेगा. लेकिन कहीं यह सरकारी विभागों के बीच लोगो के लिए होड़ की शुरुआत तो नहीं है.

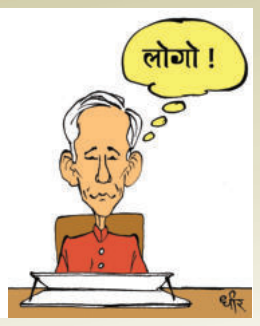

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

अग्रवाल गृह मंत्रालय आ सकते हैं

अविनाश अग्रवाल गृह मंत्रालय में हाल में गठित एनएटीजीआरआईडी का निदेशक पद संभाल सकते हैं. अविनाश 1992 बैच के आईटीएएस अधिकारी हैं.

महाऋषि शीघ्र भारत सरकार में

आईएस मीरा महाऋषि शीघ्र ही भारत सरकार में शामिल होंगी. उन्हें पर्यावरण एवं वन विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है. इस पद पर पहले आईएस अधिकारी आर एच ख्वाजा थे. ख्वाजा को हाल में पर्यटन सचिव नियुक्त किया गया है.

पंजाब एंड सिंध बैंक पहुंचेंगे चन्नी

पंजाब एंड सिंध बैंक में सीएमडी पद पर आईएएस अधिकारी सरवन सिंह चन्नी का नाम लगभग तय है. वह जी एस बेदी की जगह लेंगे, जो जून में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं.

काल्हा पंजाब लौटे

क्या काल्हा पंजाब के नए मुख्य सचिव होंगे? योजना आयोग के सलाहकार दिलशेर सिंह काल्हा के अचानक अपने मूल कैडर लौटने से इसकी संभावना तेज़ हो गई है कि वह पंजाब के मुख्य सचिव एस सी अग्रवाल की जगह ले सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक़, अग्रवाल भारत सरकार में सचिव नियुक्त किए जा सकते हैं.

सेबी से जाएंगे भावे

सेबी के चेयरमैन सी बी भावे के कार्यकाल का विस्तार संभव नहीं दिख रहा है. भावे का कार्यकाल अगले साल जनवरी में पूरा हो रहा है. अगले चेयरमैन पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सीएमडी ओ पी भट्ट की दावेदारी मज़बूत मानी जा रही है.

सबसे बड़ा घोटाला

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

पृष्ठ 1 का शेष

के आयोजन में घपलेबाज़ी हो रही है. इनके जाते ही ए के मट्टू को ओसी में लाया गया. यह एक बड़ी घटना है, क्योंकि इनके आते ही कलमाडी की वही पुरानी टीम जो एथलेटिक्स की टीम थी, ओसी की कर्ताधर्ता बन गई. कलमाडी, ललित भनोट, ए के मट्टू, संजय महेंद्रू और दरबारी ने टीम बनाकर सारे कारनामों को अंजाम दिया. इस टीम के इतिहास के बारे में अगर जानना है तो सरकार को इसके उन कारनामों की तहक़ीक़ात करनी चाहिए, जो इसने देश के एथलेटिक्स के साथ किया है. बहुत सारे ख़ुलासे ख़ुद बख़ुद सामने आ जाएंगे और देश के लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि एथलेटिक्स की हालत क्यों ख़राब है.

सबसे बड़ी घपलेबाज़ी का ख़ुलासा तब होगा, जब ओसी और स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट (एसएमएएम) के बीच हुए सौदे का सच सामने आएगा. इस कंपनी को मार्केटिंग राइट्स दिए गए थे, जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है. इसे इस शर्त पर रखा गया था कि इसे हर डील का 23 फ़ीसदी प्लस सर्विस चार्ज मिलेगा. यानी कि चाहे भारतीय रेल हो या फिर ओएनजीसी, जो भी इस खेल में विज्ञापन देगा, उसमें से लगभग पच्चीस फ़ीसदी रकम इस कंपनी को मिल जाएगी. अब यह सोचने वाली बात है कि दिल्ली में आयोजन होगा, भारत की कंपनी पैसे लगाएगी और आस्ट्रेलिया की कंपनी को बैठे-बैठाए 25 फ़ीसदी पैसे चले जाएंगे. ग़ौर करने वाली बात यह है कि यह वही कंपनी है, जिसे कलमाडी ने पुणे गेम्स 2008 में मार्केटिंग राइट्स दिए थे. इस कंपनी के तार मॉरीशस की उस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिसका नाम आईपीएल घोटाले में आया है. इस कंपनी को ललित मोदी ने फैसिलिटेशन फीस के तौर पर 380 करोड़ रुपये दिए थे. अफ़सोस की बात यह है कि इसके बावजूद यह कंपनी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए प्रायोजक नहीं ला सकी. यही वजह है कि भारतीय रेल और ओएनजीसी ने अपनी 100-100 करोड़ रुपये की स्पांसरशिप वापस ले ली. इनका कहना यह है कि अगर इसमें 25 फ़ीसदी आस्ट्रेलिया की कंपनी को जाना है तो पैसे लगाने का कोई तुक ही नहीं है. अब हालात यह हैं कि कलमाडी और ओसी को भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हीरो होंडा के अलावा कोई बड़ा कॉरपोरेट स्पांसर नहीं मिला है. जो भी कंपनियां हैं, वे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पैसे बचाकर रख रही हैं. दूसरी समस्या यह है कि यह कंपनी अब ओसी के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है. आस्ट्रेलिया सरकार के मंत्री भी बयान दे रहे हैं कि इस तरह से किसी कंपनी को बर्ख़ास्त नहीं किया जा सकता है. इसका खेल पर इस तरह से असर पड़ने वाला है कि कई बड़े-बड़े खिलाड़ी दिल्ली नहीं आएंगे. कनाडा ने भी अपने बड़े-बड़े खिलाड़ियों को दिल्ली भेजने से मना कर दिया है.

अभी यह शुरुआत हुई है. माना यह जा रहा है कि आस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद और भी देश अपने अच्छे खिलाड़ियों को दिल्ली आने से मना कर सकते हैं. जब अच्छे खिलाड़ी हिस्सा ही नहीं लेंगे तो दर्शक किसे देखने के लिए स्टेडियम जाएंगे या टीवी देखेंगे. कॉमनवेल्थ गेम्स को एक और झटका लगा है. यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब इसकी तैयारी हुई थी तो यह अनुमान लगाया गया था कि क़रीब 4 लाख विदेशी दिल्ली आएंगे. हक़ीक़त यह है कि आज यह संख्या घटकर 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं है. इस घपलेबाज़ी का दूसरा ख़ामियाज़ा यह है कि भारत ने एशियन गेम्स के लिए बिड करना छोड़ दिया है. कोई भी मंत्रालय अब कलमाडी के साथ हाथ मिलाने से कतरा रहा है. इस घपलेबाज़ी का एक और नुक़सान यह है कि खेलों में आने वाला विदेशी निवेश रुक जाएगा.

कलमाडी से यह सवाल भी पूछना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट क्यों नहीं है. चाहे वह आस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश हो, ये सब क्रिकेट खेलने वाले देश कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं. 2004 में ही यह तय हो चुका था कि दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट भी शामिल होगा, लेकिन बीसीसीआई ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया. असलियत यह है कि महाराष्ट्र के दो नेताओं शरद पवार और कलमाडी की लड़ाई की वजह से देश को सबसे बड़ा नुक़सान होने वाला है. अगर क्रिकेट को शामिल कर लिया गया होता तो 900 से 1000 करोड़ रुपये सिर्फ़ क्रिकेट से मिल गए होते. आज हालत यह है कि सुरेश कलमाडी को दूरदर्शन ने भी छोड़ दिया है. अब दूरदर्शन ने यह कह दिया है 75000 सेकेंड के लिए जो स्पांसर्स लाने हैं, वे ओसी ही लेकर आए. अब समस्या यह है कि स्पांसर्स कहां से आएंगे. एक अनुमान के हिसाब से कॉमनवेल्थ गेम्स से ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ 400 करोड़ रुपये ही आ सकते हैं. सवाल यह है कि अब कलमाडी 1600 करोड़ रुपये सरकार को कहां से वापस करेंगे. अब सरकार को यह फ़ैसला करना है कि अगर यह पैसा वापस नहीं होता है तो क्या इस लूट का ख़ामियाज़ा देश की जनता भुगतेगी?

35,000 करोड़ रुपये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए हैं, उसमें भी भीषण घपलेबाज़ी हुई है. सरकार को यह तहक़ीक़ात करनी चाहिए कि 32 खेलों के लिए जितने भी स्टेडियम बने हैं, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट आदि बने हैं, उनकी डिज़ाइन और आर्किटेक्चर किस कंपनी ने तैयार किए. इन कंपनियों के पीछे कौन-कौन लोग हैं. इस तहकीक़ात की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि ये कंपनियां और एजेंसियां ओसी के अधिकारियों की फ्रंट कंपनी हैं. मतलब यह कि पैसे कैसे ख़र्च होंगे, स्टेडियम कैसा बनेगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, ये सारे फ़ैसले ओसी को ही लेने थे. यानी इन सब लोगों ने देश की जनता के 35 हज़ार करोड़ रुपयों को निजी संपत्ति मानकर लूटखसोट की. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को ले लीजिए. इसके जीर्णोद्धार के लिए 900 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए हैं. यह विशाल स्टेडियम पहले से बना था. अब देखना यह है कि 900 करोड़ किस चीज पर ख़र्च किए जा रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इस ख़र्च में खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी मशीनें और सुविधाएं शामिल नहीं हैं. पैसे की बरबादी का यह अनोखा नमूना है. उदाहरण के तौर पर पुणे के बालेवाडी स्टेडियम को ले लीजिए, जो एक बेहतरीन स्टेडियम है. यह 82 करोड़ रुपये में बना था. यहां वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, अल्ट्रा माडर्न जिम है. मतलब यह कि अगर 200 या 300 करोड़ भी ख़र्च किए जाएं तो एक नया स्टेडियम बन सकता है, वह भी वर्ल्ड क्लास का. स्वीमिंग पूल का बजट 300 करोड़ का है, जबकि अच्छा से अच्छा स्वीमिंग पूल 5 करोड़ में तैयार हो जाता है. पैसे की बरबादी के साथ-साथ इन कामों में जिस तरह से नियम -क़ानून की अनदेखी की गई है, उसका नतीजा यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े काम पूरे नहीं हो पाए. इस काम में लगे ठेकेदार और कंपनियां अधिकारियों की सारी घपलेबाज़ी को जानते हैं. जब उन्हें कोई टेंडर नहीं मिलता है तो वे आरटीआई डाल देते हैं. मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और काम रुक जाता है. अदालत में अब तक क़रीब 30 आरटीआई आवेदन डाले जा चुके हैं. आरटीआई डालने वाले समाजसेवक नहीं हैं. इनमें से ज़्यादातर लोग इन ठेकेदारों और कंपनियों के इशारे पर काम कर रहे हैं.

कॉमनवेल्थ गेम्स सही मायने में काजल की काली कोठरी है. इसमें जो भी शामिल हैं, उनका बेदाग़ निकलना मुश्किल है. कुछ दिनों पहले तक कलमाडी जब भी दिखते, इटालियन सूट और विदेशी रंगीन चश्मे में नज़र आते थे. जबसे कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले की ख़बर आई है, वह पहले शर्ट और पैंट में नज़र आए और अब सफ़ेद खादी कुर्ते में दिखते हैं. सफेद खादी की ताक़त वह जानते हैं. साथ ही वह यह भी जानते हैं कि भारत की जनता भोली भाली है, बेहतरीन शुभारंभ समारोह और ज़बरदस्त आतिशबाज़ी के बीच सब कुछ भूल जाएगी. यही वजह है कि समारोह के लिए पचास करोड़ रुपये रखे गए हैं. जमकर आतिशबाज़ी होगी, जिसकी चमक और दमक के बीच भ्रष्टाचार के सारे मामले दब जाएंगे. फिर अलग-अलग एजेंसियों को जांच में लगाया जाएगा. यह दिखाया जाएगा कि सरकार गुनहगारों को सज़ा दिलाएगी, लेकिन गुनहगार फिर भी बच जाएंगे. वैसे भी हमारे देश में यह एक परंपरा बन चुकी है कि यहां शक्तिशाली घोटालेबाज़ों को सज़ा नहीं मिलती है. मीडिया ख़ुलासे करता रहेगा, संसद में हंगामा होता रहेगा और अपराधी इन सब पर मुस्कराते रहेंगे. अब तो बस एक ही सवाल बच गया है, जिन्हें नाज़ है हिंद पर, वो कहां हैं?

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार
वर्ष 2 अंक 24
दिल्ली, 23 अगस्त-29 अगस्त 2010
संपादक
संतोष भारतीय
मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित
संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301
फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9899815169
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

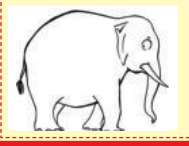

आरटीआई के तहत मिली सूचना से साफ होता है कि इन राज्यों में लोकायुक्त का कार्यालय एक सफ़ेद हाथी बन चुका है.

लोकायुक्त सफ़ेद हाथी सीवीसी से क्या उम्मीद करें?

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिगुल बजाना यानी जान से हाथ धोना. सत्येंद्र दूबे, मंजूनाथ से लेकर जेठवा तक एक लंबी फ़ेहरिस्त. सरकार कुछ नहीं कर सकती, सिवाय क़ानून बनाने के. इसलिए एक और नया क़ानून. व्हिसल ब्लोअर बिल 2010. सीवीसी को दीवानी अदालत जैसी शक्तियां मिलेंगी. लेकिन सिर्फ़ अधिकार मिलने से क्या होगा? लोकायुक्त जैसा पद पहले ही बेमानी हो चुका है, जिसके पास पर्याप्त अधिकार हैं. सवाल उस मंशा का है, जिसे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है. क्या सीवीसी से उम्मीद की जा सकती है?

शशिशेखर

आज से सात साल पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक इंजीनियर सत्येंद्र दूबे को बिहार के गया सर्किट हाउस में गोली मार दी गई थी. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सीधे पत्र लिखकर एनएचएआई में भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी दी थी, लेकिन पीएमओ ने उनकी शिक़ायत पर कोई कार्रवाई नहीं की. उल्टे यह ख़बर भी आई थी कि पीएमओ से ही इस शिक़ायत की जानकारी लीक की गई थी. इसी तरह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार सामने लाने वाले आईओसी के अधिकारी मंजूनाथ की भी हत्या कर दी गई. मंजू आईआईएम लखनऊ के पूर्व छात्र थे. चाहते तो आराम से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करके ऐश की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन देश प्रेम की भावना ने उन्हें सरकारी कंपनी का मुलाजिम बना दिया. ईमानदारी दिखाई तो जान से हाथ धोना पड़ा. 2010 के पहले सात महीने में ही आठ आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई. जुलाई में गुजरात के आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या इसलिए कर दी गई, क्योंकि उन्होंने ग़ैरक़ानूनी खनन के मामले में गुजरात के एक भाजपा सांसद का पर्दाफाश किया था. हत्या के इन सभी मामलों में एक संदेश भी था. संदेश यह कि जो भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा.

बहरहाल, इन तमाम हत्याओं के बाद सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी है. उसने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसे मामले में आवाज़ उठाने वालों की पहचान गुप्त रखने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एक क़ानून बनाने की मंजूरी दे दी है. इस विधेयक का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट डिसक्लोज़र एंड प्रोटेक्शन फॉर पर्सन्स मेकिंग डिसक्लोज़र बिल 2010. यानी संक्षेप में कहें तो व्हिसल ब्लोअर बिल 2010. व्हिसल ब्लोअर बिल 2010 में सरकारी धन के दुरुपयोग और सरकारी संस्थाओं में हो रहे घोटालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को व्हिसल ब्लोअर माना जाएगा. यानी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिगुल बजाने वाला. इस बिल में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को अतिरिक्त अधिकार दिए जाने की बात है. सीवीसी को दीवानी अदालत जैसी शक्तियां भी देने की बात है. सीवीसी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रोक सकेगी. भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखने की ज़िम्मेदारी सीवीसी की होगी. अगर पहचान उजागर होती है तो ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ शिक़ायत भी की जा सकेगी. इस विधेयक के दायरे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल होंगे. बहरहाल, इस विधेयक में सीवीसी को जितनी ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है, क्या सीवीसी उसे पूरा कर पाने में सक्षम होगा. क्या सीवीसी की सांगठनिक संरचना इतनी बड़ी है जिससे वह भारत जैसे बड़े देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या से लड़ पाए. यहां तो भ्रष्टाचार की जड़ें ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई हैं. किस-किस की शिक़ायतों पर सीवीसी ठोस कार्रवाई कर पाएगा? राज्यों, ज़िलों और पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार से कैसे निबटेगा सीवीसी? इस विधेयक की संरचना और गंभीरता से जुड़े इन चंद सवालों पर सरकार को सोचना होगा. सरकार को सोचना चाहिए कि आरटीआई क़ानून के लिए तो केंद्रीय सूचना आयोग के साथ राज्य सूचना आयोग भी हैं. उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए तो ज़िला स्तर तक आयोग गठित किए गए हैं. फिर भ्रष्टाचार जैसी संवेदनशील समस्या से निपटने के लिए सिर्फ़ सीवीसी ही क्यों? वह भी सिर्फ़ केंद्रीय स्तर पर?

पिछले कई सालों से पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से यह मांग करते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिगुल बजाने वाले लोगों को क़ानूनी सुरक्षा मुहैया कराई जाए. एक ऐसा क़ानून बनाया जाए, जिससे इस तरह के लोगों की पहचान गुप्त रखी जा सके. साथ ही उन्हें सरकारी सुरक्षा भी मिल सके. जुलाई के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में सैकड़ों आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और आम नागरिक एकत्र हुए. इसमें मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह भी शामिल हुए थे. चर्चा इस बात पर थी कि आख़िर ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है? काफी विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकला कि सरकार को जल्द से जल्द लोकपाल विधेयक पारित करना चाहिए. लोकायुक्त को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए. इन संस्थाओं को इतना मज़बूत बनाया जाए, जिससे कि ये इस तरह के मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर सकें.

लेकिन सवाल यह है कि लोकायुक्त या सीवीसी जैसी संस्था क्या और कितना काम कर सकती है? कितना निष्पक्ष और ईमानदार रह सकती है? बहरहाल, चौथी दुनिया ने दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लोकायुक्त कार्यालय का पूरा जायज़ा लिया है. आरटीआई के तहत मिली सूचना से साफ होता है कि इन राज्यों में लोकायुक्त का कार्यालय एक सफेद हाथी बन चुका है. तमाम अधिकारों के बाद भी इन राज्यों में यह संस्था कोई नजीर पेश नहीं कर सकी. बावजूद इसके हर साल करोड़ों रुपये इस कार्यालय पर ख़र्च हो रहे हैं. बिहार जैसे राज्य में तो आम आदमी को यह भी मालूम नहीं है कि लोकायुक्त जैसा कोई पद भी होता है, जहां वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. जहां तक सीवीसी की बात है तो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करने का दायित्व इस संस्था पर है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत दुनिया के भ्रष्टतम राष्ट्रों में से एक है. ऐसे में यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीवीसी के काम का दायरा कितना बड़ा हो जाता है. फिर भी सीवीसी अपने तीन सदस्यों के बूते कितना बोझ ढो पाएगा, देखना होगा. व्हिसल ब्लोअर बिल 2010 में जितने दायित्व आयोग को दिए जा रहे हैं, उन्हें निभा पाना तीन सदस्यीय सतर्कता आयोग के लिए किसी समस्या से कम नहीं होगा.

shashishekhar@chauthiduniya.com

ऐसे लोकायुक्त पद का क्या फ़ायदा?

लोकायुक्त पद का गठन राज्यों के लिए हुआ था. इस विचार के साथ कि वह राज्य सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों के संबंध में आई शिक़ायतों पर सुनवाई करने का काम करेगा. हालांकि लोकायुक्त राज्य के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के ख़िलाफ़ जांच नहीं कर सकते. सबसे पहले उड़ीसा में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी. बाद में और भी कई राज्यों में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, लेकिन सवाल है कि क्या लोकायुक्त का पद अपने मक़सद में कामयाब रहा? चौथी दुनिया ने इस बारे में जो सूचना एकत्र की है, उससे तो यही लगता है कि लोकायुक्त का पद अब एक सफेद हाथी बन चुका है. उत्तर प्रदेश और बिहार से मिली सूचना के मुताबिक़, इनके कार्यालयों पर हर साल करोड़ों का ख़र्च हो रहा है. 2002 से 2007 के बीच उत्तर प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय पर 5 करोड़ 20 लाख रुपये से ज़्यादा ख़र्च हो गए. और काम कितना किया इस कार्यालय ने? इन पांच सालों में इस कार्यालय के पास 20 हजार 2 सौ 24 मामले आए. 4191 मामलों में जांच शुरू की गई, 125 मामलों में कार्यवाही शुरू हुई और सिर्फ़ 4918 मामलों में लोकायुक्त द्वारा अंतिम रूप से कार्यवाही की गई. बिहार लोकायुक्त कार्यालय का मामला भी इससे कुछ अलग नहीं है. 2002 से 2007 के बीच बिहार लोकायुक्त कार्यालय पर 5 करोड़ 12 लाख रुपये से ज़्यादा ख़र्च हो गए. इन पांच सालों में इस कार्यालय के पास 8 हज़ार 7 सौ 43 शिक़ायतें आईं. 7043 मामलों में जांच शुरू की गई, 131 नौकरशाहों एवं राजनेताओं के ख़िलाफ़ शिक़ायतें आईं. इन सभी मामलों में अंतिम कार्रवाई क्या हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई है. नौकरशाहों और राजनेताओं के ख़िलाफ़ क्या हुआ, इसकी ख़बर कम से कम मीडिया में आज तक नहीं आई है.

यह हाल सिर्फ़ इन्हीं दो राज्यों का नहीं है. और भी जिन राज्यों में लोकायुक्त हैं, वहां की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है. कर्नाटक का मामला तो अभी का है. भ्रष्टाचार और खनन माफ़ियाओं के ख़िलाफ़ अपने सख्त रवैये की वजह से यहां के लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने इस्तीफ़ा दे दिया था. उनका कहना था कि कर्नाटक की भाजपा सरकार लोकायुक्त के प्रति उपेक्षित रवैया अपना रही है. ऐसा एक भी उदाहरण सामने नहीं आया है, जिसमें लोकायुक्त ने किसी राजनेता के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की हो. दरअसल सूचना आयोग की तरह ही लोकायुक्त का पद भी राजनीतिक स्वार्थपूर्ति का एक ज़रिया बन गया है. यही वजह है कि हर राज्य सरकार अपने चहेते को इस पद पर बैठा देती है. ज़ाहिर है, ऐसे लोकायुक्त से भला जनता क्या उम्मीद कर सकती है? इसके अलावा लोकपाल की चर्चा भी जब-तब चलती रहती है. दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में लोकपाल पद सृजित करने की सिफ़ारिश की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक़, लोकपाल केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रियों एवं अधिकारियों से जुड़े मामलों की जांच करेगा. लोकपाल विधेयक की चर्चा पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने गंभीरता से विचार नहीं किया. इस बात पर ज़रूर चर्चा हुई कि इसके दायरे से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बाहर कर देना चाहिए. ख़ैर, लोकपाल विधेयक अगर पारित भी हो जाता है तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि इसका हश्र भी लोकायुक्त या सूचना आयुक्त के पद की तरह नहीं होगा.

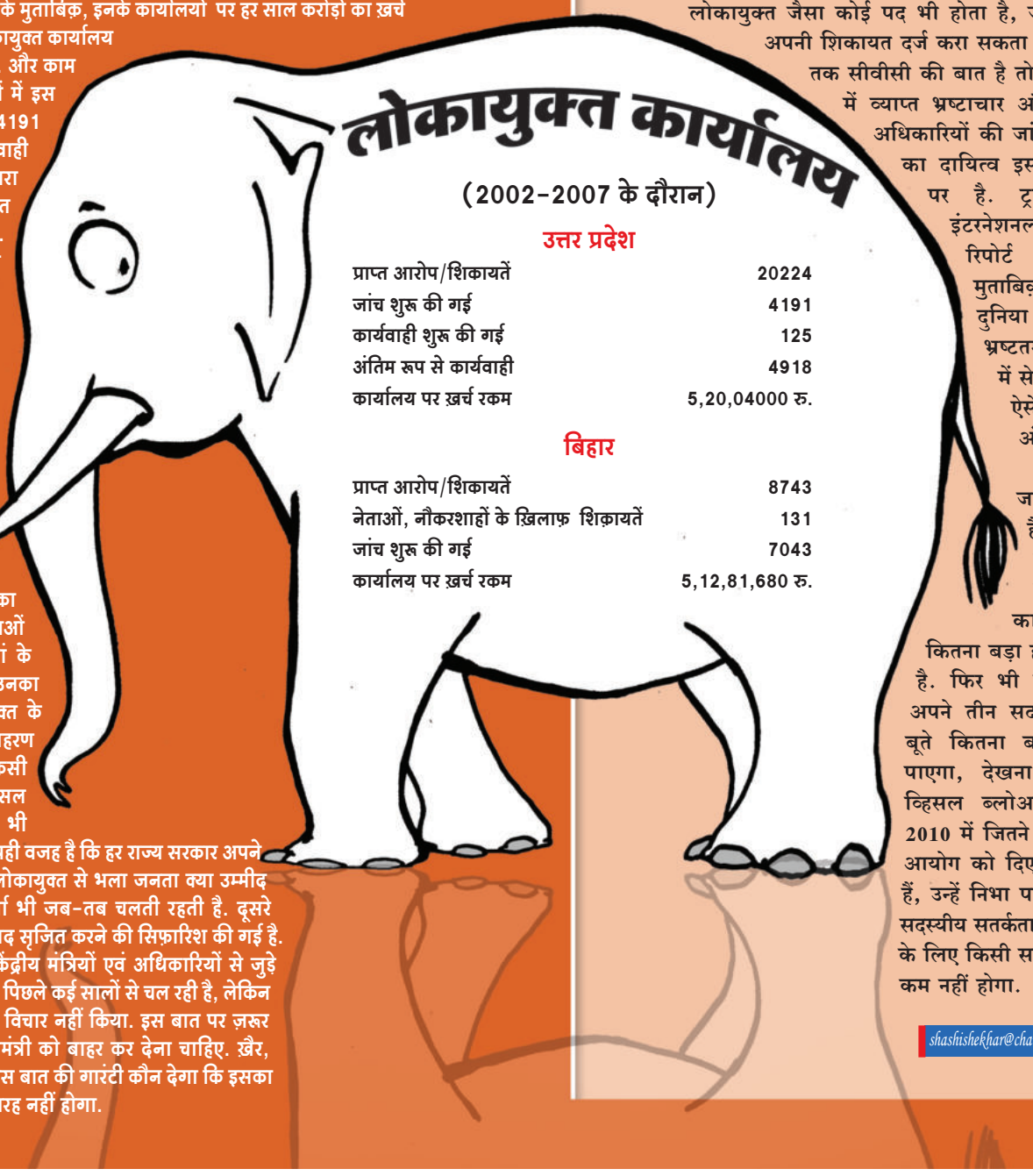

राजनीतिक अनिश्चितता के मामले में कीर्तिमान बनाने वाले इस राज्य के 56 प्रतिशत गांवों में सड़क नाम की चीज़ नहीं है.

चौथी दुनिया

भ्रष्टाचार के अंधेरे से मुक्ति कब मिलेगी?

प्रशांत कुमार झा

जिस तरह तकनीकों के देश जापान में सर्वाधिक भूचाल आता है, उसी प्रकार खनिजों के राज्य झारखंड में सर्वाधिक राजनीतिक जलजला आता है. इसीलिए यह सूबा निरंतर सियासी अस्थिरता का दंश झेल रहा है. राज्य गठन के 10 साल के अंदर यह तीसरा राष्ट्रपति शासन है. हालांकि राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र का समुचित विकल्प नहीं है, परंतु जिस तरह यहां की चुनी हुई सरकारें लूटखसोट का नंगानाच करती रही हैं, उससे तो यही लगता है कि राष्ट्रपति शासन झारखंड के लिए किसी निर्वाचित सरकार से बेहतर है. वर्तमान समय में सूबे में राष्ट्रपति शासन सार्थक, कारगर और प्रभावी दिख रहा है. भ्रष्टाचारियों की काली करतूतों की पोल खुल रही है. जनता के पैसे को निजी संपत्ति समझ कर उसका दुरुपयोग करने वालों पर नकेल कसी जा रही है. इसे और तेज़ करने की ज़रूरत है. साथ ही साथ विकास के पहिए को भी गति देनी है.

15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया. जनता के मन में आशा का संचार हुआ कि अब क्षेत्र का विकास होगा, उसके सपनों को पंख लगेंगे, मगर उसकी सभी उम्मीदों पर यहां की फरेबी राजनीति ने पानी फेर दिया. राजनीतिक अस्थिरता के कारण झारखंड में विकास कार्य नहीं हो पाते और जो होते हैं, उनकी मंथर गति से कछुआ भी शरमा जाए. राज्य गठन के बाद यहां विभिन्न सरकारों का आना-जाना लगा रहा. बीते दस वर्षों में आठ सरकारें आईं. जो भी सरकार आती है, विभिन्न विभागों के अधिकारियों का अपनी सुविधा के अनुसार फेरबदल करती है. बीते दस वर्षों में दस मुख्य सचिव बदले गए, दस विकास आयुक्त और छह पुलिस महानिरीक्षक एवं चार महाधिवक्ता भी. विभागीय सचिव तो ताश के पत्तों की तरह फेटे जाते रहे. डीसी, एसपी, बीडीओ एवं सीओ की तो पूछिए मत, कब कौन तबादला उद्योग का शिकार हो जाएगा, किसी को पता नहीं. परिणामस्वरूप झारखंड एक असफल प्रदेश बनकर रह गया. यहां कोई भी विकास कार्य शुरू होने से पहले और बाद में अड़चनों की भरमार रहती है, नतीजतन योजनाओं की लागत राशि लगातार बढ़ती रहती है. होटवार जेल बननी थी 20 करोड़ रुपये में, राशि बढ़कर 25 करोड़ हो गई. रांची के नए सर्किट हाउस के निर्माण की योजना राशि एक करोड़ रुपये थी, बनते-बनते यह राशि 2 करोड़ से ऊपर चली गई. मैथन जलापूर्ति योजना थी 200 करोड़ की, अभी काम पूरा नहीं हुआ और राशि पहुंच गई 300 करोड़ के पार. इसी तरह गढ़वा ज़िले में कनहर सिंचाई एवं विद्युत परियोजना पर 19 करोड़ रुपये ख़र्च हो गए हैं, लेकिन अभी तक देखने लायक़ कुछ भी नहीं हुआ है. उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का सपना एकीकृत बिहार के समय आज से 38 साल पहले 1972 में देखा गया था. राज्य गठन के साढ़े नौ वर्षों में विकास की कई योजनाएं अधूरी रह गईं. लोहारदगा-टोरी, हज़ारीबाग-कोडरमा एवं देवघर-दुमका रेल लाइन का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका. उक्त परियोजनाओं को आज से दस वर्ष पहले शुरू किया गया था. इन्हें पूरा करने में किसी सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. 14 साल पहले टंडवा में 2000 मेगावाट के पॉवर प्लांट का शिलान्यास किया गया था. एनटीपीसी की यह परियोजना इतने बड़े अंतराल के बाद भी यथावत है. तिलैया में शुरू होने वाली 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना और कोडरमा में 1000 मेगावाट की डीवीसी परियोजना के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं. विकास के मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे है. वर्ष 2002-03 से 2008-09 तक विभिन्न विकास योजनाओं पर 20832 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए, पर किसी भी क्षेत्र मसलन शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य एवं पेयजल में झारखंड राष्ट्रीय औसत के समकक्ष भी नहीं हो सका.

राजनीतिक अनिश्चितता के मामले में कीर्तिमान बनाने वाले इस राज्य के 56 प्रतिशत गांवों में सड़क नाम की चीज़ नहीं है. बिजली के अभाव में 68 प्रतिशत गांववासी अंधेरे में रहने के लिए विवश है. शिक्षा का हाल यह है कि सूबे के 24 ज़िलों में से 12 में साक्षरता दर 50 प्रतिशत से भी कम है. अब तक जितनी सरकारें आईं, सभी ने ग़रीबी उन्मूलन हेतु हरसंभव कोशिश करने की घोषणा तो की, लेकिन राज्य में 54 प्रतिशत आबादी अभी भी ग़रीबी रेखा से नीचे है.

कृषि क्षेत्र में देखें तो राज्य की महज़ 8.9 प्रतिशत खेती योग्य भूमि में ही सिंचाई की सुविधा है. कुल मिलाकर विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, मगर सवाल है कि कैसे? वित्तीय कुप्रबंधन और घोटालों के चलते झारखंड की अर्थव्यवस्था एक दशक से कराह रही है. बिहार से अलग होने के बाद यह सूबा आर्थिक लुटेरों का चारागाह बन गया. मंत्रियों एवं विधायकों पर करोड़ों रुपये वेतन, भत्तों एवं अन्य सुख-सुविधाओं के रूप में ख़र्च हो गए, लेकिन जनसामान्य की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो सकीं. आज़ादी के बाद सबसे बड़े घोटाले के नायक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री कमलेश सिंह, एनोस एक्का और हरिनारायण राय आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद हैं. राज्य में घोटालों की सूची बहुत लंबी है. 300 करोड़ का बिजली बोर्ड घोटाला, 103 करोड़ का दवा घोटाला, 100 करोड़ का अलकतरा घोटाला, 37 करोड़ का मेडिकल उपकरण घोटाला, 25 करोड़ का नमक घोटाला एवं 10 करोड़ का खाद-बीज घोटाला आदि काफ़ी चर्चित रहे हैं. राज्य गठन के बाद कोड़ा प्रकरण समेत 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी हो चुकी है. राज्य की जनता का दुर्भाग्य देखिए, जनप्रतिनिधियों के वेतन और सुविधाओं में 6 बार बढ़ोत्तरी की गई, वहीं विकास मद की 7 हज़ार करोड़ से भी अधिक राशि सरेंडर हो गई. राज्य गठन के वक़्त झारखंड में प्रति व्यक्ति क़र्ज़ का बोझ जहां 2000 रुपये था, वह बढ़कर 7000 रुपये हो गया है. सूबे में शायद ही ऐसा कोई सांसद या विधायक होगा, जिसकी करोड़ों की हैसियत न बन गई हो. अपरिपक्व विधायिका एवं नौकरशाहों की अदूरदर्शिता के चलते वित्तीय प्रबंधन में संतुलन नहीं हो सका. एक तरफ़ सरकार वित्तीय घाटे को कम करने के लिए क़र्ज़ लेती है, वहीं दूसरी ओर विकास मद के करोड़ों रुपये सरेंडर हो जाते हैं. राज्य गठन के समय सरकार का क़र्ज़ लगभग 6.5 हज़ार करोड़ रुपये था, जो अब 22 हज़ार करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है. झारखंड में नेताओं एवं नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के किस्सों और मामलों की फ़ेहरिस्त काफ़ी लंबी है. झारखंड उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री और कई पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं आय से अधिक संपत्ति के मामले लंबित हैं. सीबीआई अदालत में पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के ओएसडी अविनाश कुमार, आईएएस डॉ. प्रदीप कुमार और करोड़ों रुपये के दवा घोटाले के आरोपी डॉ. विजय नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है. विभिन्न एजेंसियां इन घोटालों की जांच में लगी हुई हैं, लेकिन आशंका इस बात की है कि चुनाव होने के बाद निर्वाचित सरकार आने से कहीं इन जांचों पर पानी न फिर जाए. सीमित संसाधन होने के बावजूद पड़ोसी राज्य बिहार के विकास की चर्चा पूरे देश में हो रही है. झारखंड के पास विकास के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं, बस ज़रूरत है एक सशक्त नेतृत्व की. नेपोलियन ने कहा था, कोई भी सेना कमज़ोर नहीं होती है, कमज़ोर उसका नायक होता है.

विकास कार्य	राष्ट्रीय औसत	झारखंड का औसत
सड़क की लंबाई (प्रति 1000 वर्ग किमी)	768	414
सभी मौसम में सड़कों से गांवों का जुड़ाव	57%	36%
कुपोषण के शिकार बच्चे	47%	54%
एक पीएचसी पर गांवों की संख्या	27.6%	58.1%
स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता	78%	42.7%
घरों में बिजली	67.9%	40.2 %

feedback@chauthiduniya.com

जनता का क्या कसूर है

आर के यादव

बसपा के टिकट पर जेल से ही मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंचे आनंद सेन मंत्री तो बन गए, लेकिन यही लालबत्ती उनके लिए अभिशाप साबित हो गई. चंद दिनों बाद उन्हें साकेत महाविद्यालय की विधि छात्रा शशि के अपहरण और हत्या के आरोप में दोबारा जेल की राह देखनी पड़ी. इलाकाई जनता विधायक की ग़ैर मौजूदगी के चलते परेशान है और सारे विकास कार्य भी ठप्प पड़े हैं. उधर लंबी और उबाऊ न्यायिक प्रक्रिया के चलते न तो उनकी ज़मानत हो पा रही है और न मुक़दमे का निष्पादन. न पार्टी से निष्कासन, न विधानसभा की बैठकों में पहुंचने का मौक़ा और न सदस्यता से त्यागपत्र.

बात जब आनंद सेन के साथ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की हो, तब कुछ भी कहने से पहले मित्रसेन यादव की चर्चा अपरिहार्य है. जनपद के ज़मीनी नेता एवं राजनीतिक महारथी मित्रसेन यादव को आपातकाल के दौरान बरेली केंद्रीय कारागार में नज़रबंद किया गया था. जेल से छूटने के बाद सीपीआई के टिकट पर उन्हें 1977 में पहली बार मिल्कीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौक़ा मिला. पूर्व विधायक धर्मचंद्र मिश्रा को हराकर वह विधानसभा पहुंचने में सफल रहे. संपूर्ण भारत में जनता पार्टी की लहर के बावजूद मित्रसेन ने उसके प्रत्याशी को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. ढाई साल बाद जब मोरार जी देसाई की सरकार गिर गई तो विधायक रहते हुए मित्रसेन ने लोकसभा के चुनाव में भी क़िस्मत आज़माई और फ़ैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए. उनकी यह जीत भी ऐतिहासिक थी. पूरे भारत में कांग्रेस की वापसी की ज़बरदस्त लहर थी और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद भी चरम पर था. इसके बावजूद मित्रसेन ने भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त दी. इसके साथ ही मिल्कीपुर क्षेत्र में सामंत बनाम सर्वहारा, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता एवं जातिवादी राजनीति के साथ संघर्षों का ऐसा दौर शुरू हुआ, जो मित्रसेन यादव पर आपराधिक मुक़दमों का भी एक अलग इतिहास रचता गया. कृष्ण कुमार तिवारी हत्याकांड, भवानीफेर हत्याकांड, दारोगा मोहन राय हत्याकांड एवं पालपुर कांड जैसे गंभीर मुक़दमे राजनीतिक यात्रा के समानांतर उन्हें जेल की भी राह दिखाते रहे, लेकिन मिल्कीपुर पर मित्रसेन की राजनीतिक पकड़ में कोई कमी नहीं आई. उन्होंने अपने राजनीतिक शिष्य रामचंद्र यादव एवं पुत्र आनंद सेन को भी विधानसभा तक पहुंचाया. पुत्रवधू इंदु सेन को हैरिंटनगंज क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया. बसपा में शामिल होकर अपने सहयोगी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह की पुत्रवधू मालती सिंह को ज़िला पंचायत की कुर्सी पर क़ाबिज़ किया.

साइकिल के बल पर पहली बार विधायक का चुनाव जीते मित्रसेन ने जब चंदे की धनराशि से मोटरसाइकिल पर पांव रखा तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज हालत यह है कि मिल्कीपुर की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शख़्सियत के रूप में वह मायावती एवं मुलायम सिंह दोनों के लिए अहम बने बैठे हैं. मित्रसेन ख़ुद मुलायम सिंह के साथ सपा में हैं तो बेटा आनंद सेन बसपा में रहते हुए जेल में बंद है.

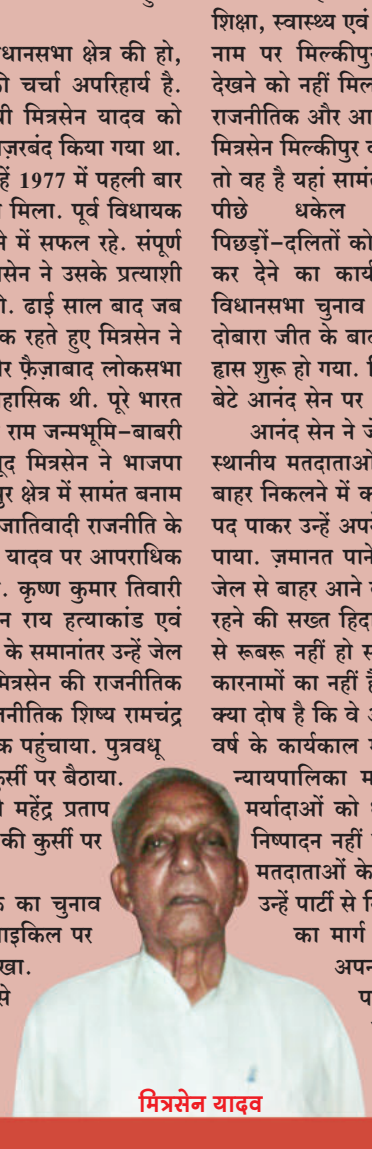

विधि छात्रा शशि

आनंद सेन

एक ओर मित्रसेन यादव तमाम संघर्षों, मुक़दमों, सामाजिक-राजनीतिक एवं प्रशासनिक झंझावातों को झेलते हुए नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचते रहे तो दूसरी ओर मिल्कीपुर आज भी वहीं है, जहां कुछ दशक पहले था. विकास के नाम पर कुछ उबड़-खाबड़ एवं पैबंद लगी सड़कों को छोड़ दिया जाए तो इनायत नगर मुख्यालय पर स्थापित तहसील के सिवा यहां और कुछ नहीं है. शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्योग आदि के नाम पर मिल्कीपुर में कुछ भी देखने को नहीं मिलता. व्यक्तिगत राजनीतिक और आर्थिक लाभ के सिवा मित्रसेन मिल्कीपुर को यदि कुछ दे सके तो वह है यहां सामंतों को एक हद तक पीछे धकेल कर सर्वहारा पिछड़ों-दलितों को आगे लाकर खड़ा कर देने का कार्य. लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आनंद सेन की दोबारा जीत के बाद उनकी राजनीति का ह्रास शुरू हो गया. पिता मित्रसेन से शुरू हुआ यह सिलसिला अब उनके बेटे आनंद सेन पर आकर टिक गया है.

आनंद सेन ने जेल में रहते हुए बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा तो स्थानीय मतदाताओं ने उन्हें इस आशा में वोट दिया कि वह जेल से बाहर निकलने में कामयाब होंगे, मगर जेल से बाहर आकर, फिर मंत्री पद पाकर उन्हें अपने मतदाताओं के बीच रहने का समय कम ही मिल पाया. ज़मानत पाने की नाकाम कोशिशों के बाद एक बार जब उन्हें जेल से बाहर आने का मौक़ा भी मिला तो प्रशासन द्वारा ज़िले से बाहर रहने की सख्त हिदायत दे दी गई. वह एक बार भी अपने मतदाताओं से रूबरू नहीं हो सके. यहां सवाल आनंद सेन या उनके आपराधिक कारनामों का नहीं है. प्रश्न यह है कि यहां के मतदाताओं का आख़िर क्या दोष है कि वे अपने निर्वाचित विधायक से मिले बिना संपूर्ण पांच वर्ष के कार्यकाल में विकास की एक किरण से भी वंचित रहे. यदि न्यायपालिका मानवीय मूल्यों, मानवाधिकारों एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर आनंद सेन के मुक़दमे का त्वरित निष्पादन नहीं कर सकती तो पैरोल पर छूटने के बाद उन्हें अपने मतदाताओं के बीच जाने से रोकने का औचित्य क्या है? बसपा उन्हें पार्टी से निष्कासित करके या उनसे त्यागपत्र मांगकर उपचुनाव का मार्ग क्यों नहीं प्रशस्त करती, ताकि क्षेत्र के मतदाता अपना नया प्रतिनिधि चुनकर अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें और मिल्कीपुर के विकास का रास्ता खुल सके. क्या मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के इस दर्द की दवा हो सकेगी?

मित्रसेन यादव

feedback@chauthiduniya.com

राज्य सरकार और एमसीडी बड़ी गाड़ियों की संख्या को सीमित करने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि कमज़ोर और विकल्पहीन रिक्शाचालकों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं.

ग़रीब रिक्शेवाले कहां जाएंगे

सभी फोटो– प्रशांत पाण्डेय

आदित्य पूजन

मानव श्रम के दोहन के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है सड़कों पर चलने वाला रिक्शा. और यह रोजी-रोटी कमाने के सबसे पुराने तरीक़ों में से भी एक है. न जाने कब से इस सवारी के घूमते तीन चक्कों के साथ न जाने कितनी ज़िंदगियों की क़िस्मत घूमती रही है. अशिक्षा और भूमिहीनता के चलते भुखमरी झेलने को अभिशप्त समाज के सबसे निचले और कमज़ोर तबके के लिए रिक्शा पेट पालने का अभिन्न और अक्सर एकमात्र साधन रहा है. सदियों से रिक्शेवालों का यह तबका दूसरे भारत या दूसरे हिंदुस्तान का आईना भी रहा है. लेकिन दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का वश चले तो वे राजधानी की सड़कों पर रिक्शों का चलना ही बंद कर दें. तभी तो अदालतों से बार-बार मनाही के बावजूद एमसीडी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शों की संख्या 99 हज़ार तक सीमित करना चाहता है. एक अनुमान के मुताबिक़, दिल्ली में पांच लाख से ज़्यादा रिक्शे सड़कों पर दौड़ते हैं और क़रीब चालीस लाख लोगों की दो जून की रोटी इन रिक्शों पर आश्रित है. एमसीडी की मानें तो रिक्शा सड़कों पर यातायात के लिए सबसे बड़ी रुकावट है और वह इसी वजह से इनकी संख्या कम करना चाहता है. टाटा और फोर्ड जैसी कंपनियों द्वारा निर्मित नए जमाने की तेज़ रफ्तार कारों के लिए मानव चालित रिक्शे की कछुआ चाल अवरोध का कारण तो है ही, उससे ज़्यादा यह समाज के समृद्ध तबके की आंखों की किरकिरी है. यह समाज का वह हिस्सा है, जिसे ध्यान में रखकर तमाम आर्थिक नीतियां आज देश में बनती हैं. तभी तो कारों, मोटरसाइकिलों एवं मोबाइलों की क़ीमतें हर साल कम होती हैं, लेकिन चावल-दाल की क़ीमत कभी कम नहीं होती. एमसीडी इसी तबके की पसंद का खयाल रखते हुए रिक्शों को राजधानी की सड़कों से ओझल करना चाहता है. उसे न तो चार लाख बेरोज़गारों और पैंतीस लाख ज़िंदगियों के भविष्य की चिंता है, न ही लगातार प्रदूषण से बेहाल होती दिल्ली के पर्यावरण की.

दरअसल, एमसीडी ने एक क़ानून के तहत राजधानी में रिक्शों के लिए लाइसेंसों की संख्या 99 हज़ार तक सीमित कर दी थी. एक एनजीओ ने इसके ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस साल 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने अपने एक फ़ैसले के द्वारा इस क़ानून को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने एमसीडी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सड़कों पर लाखों की संख्या में दौड़ रही कारों और मोटरसाइकिलों को कम करने के लिए नीति पहले बनानी चाहिए, क्योंकि ये राजधानी के पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हैं. लेकिन एमसीडी ने हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. बीते 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस अपील को ख़ारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि रिक्शा चलाना हर इंसान को संविधान से मिली रोज़गार की स्वतंत्रता के दायरे में आता है और इसे छीनने का कोई हक एमसीडी के पास नहीं है. निगम को नसीहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाना ज़्यादा ज़रूरी है. अदालत के इस फ़ैसले से रिक्शाचालकों को फ़िलहाल राहत भले मिल गई हो, लेकिन एमसीडी और सरकार के रवैये को देखते हुए इसकी कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में फिर ऐसे किसी क़ानून की मदद से उनके सिर पर तलवार नहीं लटकेगी.

दिल्ली सरकार और एमसीडी राजधानी की सड़कों पर मानव चालित रिक्शों की संख्या को केवल सीमित ही नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें धीरे-धीरे पूरी तरह ख़त्म करने की सोच रहे हैं. नगर निगम इसकी जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने की योजना बना रहा है. निगम का तर्क है कि तेज़ गति से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे दिल्ली को यातायात जाम से निजात दिलाने में मददगार होंगे. *चौथी दुनिया* ने इस संबंध में दिल्ली के मेयर पृथ्वीराज चौहान से बात की तो उन्होंने यह तो नहीं माना कि निगम राजधानी की सड़कों से रिक्शों को पूरी तरह हटाना चाहता है, लेकिन यह ज़रूर कहा कि रिक्शा यातायात की चाल को धीमा करता है. शायद चौहान को यह नहीं पता कि दिल्ली के कई हिस्सों में रिक्शों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, फिर भी इन इलाक़ों में यातायात जाम की बात आम है. एमसीडी की इस मुहिम में दिल्ली सरकार भी पीछे नहीं है. अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले राजधानी की यातायात व्यवस्था को ईको फ्रेंडली बनाने की तैयारी है. इसके लिए बैटरी से चलने वाले रिक्शा ई-रिक को लांच किया गया है. क्या सरकार यह नहीं जानती कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव चालित रिक्शों का कोई योगदान नहीं, बल्कि इसके लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ज़िम्मेदार हैं? सरकार और एमसीडी मुद्दे से जुड़े मानवीय पहलुओं की भी अनदेखी कर रहे हैं. राजधानी या देश के किसी भी हिस्से में रिक्शा चलाने वाले अधिकांश लोग निरक्षर और अप्रशिक्षित होते हैं. कहीं नौकरी नहीं मिली, भुखमरी की नौबत आ गई तो भाड़े पर रिक्शा चलाने लगे. यदि उनसे रोज़गार का यह साधन भी छीन लिया गया तो उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा. इस मुद्दे का एक आर्थिक पहलू भी है. सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे की क़ीमत 30 से 40 हज़ार के क़रीब है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-रिक की क़ीमत एक लाख 50 हज़ार रुपये है, जबकि मानव चालित रिक्शे की क़ीमत केवल 10-12 हज़ार रुपये होती है. ग़रीब रिक्शा चालकों के पास इलेक्ट्रिक रिक्शा ख़रीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे, यह भी एक बड़ी समस्या है. सरकार या एमसीडी के पास इसके लिए कोई योजना नहीं है. निजी या सरकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की योजना बनी भी तो ब्याज के बोझ तले इनका जीवन नर्क होकर रह जाएगा. दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस इलाक़े में दिन और रात का फ़र्क़ करना मुश्किल है. सूरज की रोशनी कम होते ही पब-रेस्तराओं एवं सजी हुई दुकानों से निकलते बहुरंगे प्रकाश के साथ सड़क के दोनों किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स यह एहसास ही नहीं होने देती कि दिन कब गुज़र गया, लेकिन इस इलाक़े से कुछ ही दूर स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास रिक्शा चलाने वाला उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का रहमत अली दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी रात को ठीक से सो नहीं पाता. दिल्ली में अकेले रह रहे रहमत अली के ऊपर पत्नी और पांच बच्चों के अलावा बूढ़े मां-बाप की भी ज़िम्मेदारी है. वह सुबह सात बजे से लेकर शाम के सात बजे तक सवारियों को यहां से वहां ले जाता है और औसतन 150-200 रुपये की कमाई कर लेता है, लेकिन अपना रिक्शा न होने की वजह से उसे रोजाना 50 रुपये इसके मालिक को देने पड़ते हैं. बाक़ी पैसों में वह ख़ुद क्या खाए और घरवालों को क्या भेजे, यही सोच-सोचकर उसकी रात बीत जाती है. वह रात को भी रिक्शा चलाना चाहता है, लेकिन रिक्शे का मालिक ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि उसने नाइट शिफ्ट के लिए किसी दूसरे शख्स को रिक्शा किराए पर दे रखा है.

बिहार के पूर्णिया ज़िले से आए 60 साल के नवल कामत का किस्सा तो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है. गांव में मज़दूरी करके जीवनयापन कर रहे नवल की पत्नी की चार साल पहले मौत हो गई. पत्नी की मौत के बाद उसकी सारी उम्मीदें दो जवान बेटों पर टिकी थीं, लेकिन बेटों ने ऐसा रंग बदला कि उसे घर से भागने को मजबूर होना पड़ा. घरवालों से निराश वह किसी तरह दिल्ली पहुंचा. काम की तलाश में दो-तीन दिनों तक यहां-वहां घूमता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला. भूख से बेहाल उसने रिक्शा चलाने की सोची, क्योंकि वह पढ़ने-लिखने की बात तो दूर, ढंग से हिंदी बोल भी नहीं सकता था. वह ढाई साल से रिक्शा चलाकर किसी तरह ज़िंदा है, बढ़ती उम्र में दूसरे इंसानों का बोझ ढोते-ढोते वह कई बीमारियों का शिकार भी हो चुका है, लेकिन चाहे भी तो काम छोड़ नहीं सकता. उसके पास रोज़गार का और कोई साधन नहीं है और अपने गांव वापस जा नहीं सकता. कमोबेश यही हाल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों से आने वाले हर रिक्शाचालक का है. लेकिन एमसीडी को इनकी कोई चिंता नहीं है. उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले के बदरी ओरांव को एमसीडी के इस क़ानून के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बताए जाने पर वह यही कहता है कि यदि ऐसा हुआ तो उसके पास दो ही विकल्प बचेंगे, छोटे-मोटे अपराध कर अपने और अपने परिवार का पेट पाले या फिर उन्हें मारकर ख़ुद भी मौत के हवाले हो जाए.

एमसीडी के इस क़ानून में वैसे भी कई अड़चनें हैं. रिक्शों की संख्या 99 हज़ार तक सीमित करने के बाद भी लाखों रिक्शे सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों का भ्रष्ट रवैया और राजधानी में सक्रिय रिक्शा माफ़िया ज़िम्मेदार हैं. दिल्ली में कुछेक हज़ार रिक्शाचालकों के पास ही अपना रिक्शा है. अधिकतर लोग किराए पर लेकर रिक्शा चलाते हैं, जिसका मालिकाना हक इन्हीं माफ़िया तत्वों के हाथों में होता है. अधिकारियों की मिलीभगत से एक-एक आदमी हज़ारों रिक्शे चलवाता है और ग़रीब रिक्शाचालकों के ख़ून की क़ीमत पर करोड़ों की कमाई करता है. पृथ्वीराज चौहान भी यह स्वीकार करते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले अधिकांश रिक्शों के पास लाइसेंस नहीं है. वह बताते हैं कि 99 हज़ार की सीलिंग से संबंधित क़ानून को अदालत ने मान लिया होता तो इस पर लगाम कसी जा सकती थी. मतलब यह कि एमसीडी अपने भ्रष्ट अधिकारियों को काबू में नहीं कर सकता, लेकिन ग़रीब रिक्शाचालकों के पेट पर लात मारने के लिए आमादा है. मानो इस देश में सारे क़ानून ग़रीबों के लिए ही बनाए जाते हैं.

सवाल केवल एमसीडी के इस क़ानून का ही नहीं है, सवाल निगम के आकाओं के नज़रिए का भी है. लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बीजिंग जैसे शहरों में आज बड़ी गाड़ियों के मुक़ाबले रिक्शों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसकी वजह यह है कि इसमें ईंधन की खपत नहीं होती और प्रदूषण पैदा नहीं होता. पर्यावरण विशेषज्ञों की राय में प्रदूषण का बढ़ता स्तर मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है. दिल्ली को पहले ही दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरों में गिना जाता है. इसके बावजूद राज्य सरकार और एमसीडी बड़ी गाड़ियों की संख्या को सीमित करने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि कमज़ोर और विकल्पहीन रिक्शाचालकों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं. सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अक्सर वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, ऐसे तत्वों से घिर जाते हैं, जो उन्हें ज़मीनी हक़ीक़त से रूबरू नहीं कराते, बल्कि हवा-हवाई बातें करके अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं. दिल्ली सरकार और एमसीडी में भी आज ऐसे ही अधिकारियों का बोलबाला है, जिन्हें पेट्रोल और डीजल की गंध से उबकाई नहीं आती, लेकिन इंसानों के पसीने की बदबू से उनका जी मितलाने लगता है.

aditya@chauthiduniya.com

बंगाल सरकार भी इस चाल को समझ रही है. लेकिन एक तो प्रस्ताव पर पूर्ण सहमति नहीं बनी है और दूसरे राज्य के राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि वह अभी विरोध के तेवर अख्तियार नहीं कर सकती.

गोरखालैंड का प्रस्तावित नक्शा

क्या स्वायत्तता के झुनझुने से ख़ुश हो जाएंगे गोरखा?

बिमल राय

तेलंगाना राज्य के गठन की मांग पर इमोशनल अत्याचार या ब्लैकमेलिंग के जख्म से कराहती कांग्रेस दार्जिलिंग में गोरखालैंड आंदोलन का हल तलाशने में कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी दिखा रही है. तेलंगाना आंदोलन में आत्महत्याओं से देश हिल गया था, वहीं लगातार बंद बुलाकर और प्रशासन को अपने इशारे पर नचाने के मामले में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मुखिया विमल गुरुंग ने एक दुर्लभ रिकार्ड क़ायम किया है. इसके बावजूद गोरखाओं के लिए गोरखालैंड स्वायत्त प्राधिकरण का प्रस्ताव रखकर कांग्रेस सरकार ने दार्जिलिंग से कोलकाता तक का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. विमल गुरुंग भले ही अपने गोरखालैंड आंदोलन को गांधीवादी आंदोलन कहते रहे हों, पर स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार और यहां तक कि केंद्र सरकार को भी वह अपनी लाठी के आगे झुकाते रहे हैं. हाल-फ़िलहाल गुरुंग ने धमकी दी थी कि अगर 23 जुलाई को दिल्ली में छठे दौर की त्रिपक्षीय वार्ता न आयोजित की गई तो वह 4 अगस्त से दार्जिलिंग में 40 दिन का बंद बुलाएंगे. यह सुनना था कि चिदंबरम बेचैन हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को अपना कोई प्रतिनिधि भेजने के लिए मनाया. गुरुंग को गोरखाओं का एकमात्र प्रतिनिधि मानने से इंकार करते रहे शहरी विकास मंत्री अशोक भट्टाचार्य इस बैठक में नहीं गए. किसी तरह स्वास्थ्य मंत्री को भेजकर खानापूर्ति की गई. गुरंग राजमार्ग संख्या 31 को बंद करने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नोटिस लेने से भी इंकार कर चुके हैं. मालूम हो कि यही राजमार्ग सिक्किम को देश के साथ जोड़ता है. गुरुंग के आंदोलन से सिक्किम गेहूं के साथ घुन की तरह पिसता आ रहा है. यही नहीं, दिनदहाड़े गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तामांग की हत्या कर दी गई और विमल गुरुंग ने कहा कि अगर उनकी पार्टी के किसी भी काडर को गिरफ़्तार किया गया तो पहाड़ पर आग लगा दी जाएगी. यही वजह है कि प्राथमिकी में 34 लोगों के नाम होने के बावजूद अभी तक एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा जा सका है. गोरखा लीग के काडर इसके लिए क्रमिक अनशन पर थे. सरकार की लाचारी देखिए कि डेढ़ महीने बाद उसने 3 अगस्त को आरोपियों को गिरफ़्तार करने का आश्वासन दिया और मदन की विधवा भारती तामांग ने अनशन तुड़वाया.

हालांकि दार्जिलिंग मामले में कांग्रेस के उत्साह के पीछे उसकी अपनी राजनीतिक चाल भी है. अलग राज्य बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित होना ज़रूरी है, पर स्वायत्त परिषद के गठन में केंद्र को थोड़ी ज़्यादा आज़ादी है. यही वजह है कि प्राधिकरण के वर्तमान ढांचे में इतनी रियायतें हैं, जो अलग राज्य के काफी क़रीब हैं. बंगाल सरकार भी इस चाल को समझ रही है. लेकिन एक तो प्रस्ताव पर पूर्ण सहमति नहीं बनी है और दूसरे राज्य के राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि वह अभी विरोध के तेवर अख्तियार नहीं कर सकती. इसका सूत्र माकपा की अंदरूनी राजनीति में छिपा है. बुद्धदेव भट्टाचार्य कांग्रेस के प्रति नरम रुख़ अपनाने के पक्ष में हैं, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह तृणमूल से खटपट कराकर चुनावी फ़ायदा हासिल किया जा सके. इसी वजह से दार्जिलिंग आंदोलन जैसे मामले पर राज्य सरकार केंद्र से टकराव नहीं मोल लेना चाहती. वैसे 3 अगस्त को राज्य सरकार ने भी विमल गुरुंग की पार्टी को छोड़कर पहाड़ के लगभग सभी दलों के प्रतिनिधियों की जो बैठक बुलाई, उसका संदेश यही था कि गोजमुमो के अलावा जो पार्टियां हैं, उन्हें भी पूरी अहमियत दी जानी चाहिए. वैसे इस बैठक में प्रस्तावित प्राधिकरण के बारे में दलों की राय जाननी थी. बैठक में अखिल भारतीय गोरखा लीग की अगुवाई वाले डेमोक्रेटिक फ्रंट, जीएनएलएफ (सी) और गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो हिस्सा लिया, पर माकपा से अलग हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट (सीपीआरएम), भाजपा एवं तृणमूल के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए. बैठक में प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावित प्राधिकरण का प्रारूप भी बांटा गया. राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र के साथ जो त्रिपक्षीय वार्ता हो रही है, उसमें पहाड़ की प्रतिनिधि पार्टी के रूप में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ही शामिल है, जबकि इन सभी दलों की राय भी सुनी जानी चाहिए. हालांकि बैठक में शामिल ज़्यादातर प्रतिनिधियों का मानना था कि सरकार प्राधिकरण का गठन करके एक तरह से पेन किलर दे रही है, जबकि रोग का पूरा निदान गोरखालैंड के गठन से ही होगा. इन दलों ने सुझाव दिया कि पहाड़ पर पहले लोकतंत्र बहाल किया जाना चाहिए और फिर तब इस तरह की कवायद हो. कुछ प्रतिनिधियों ने सीधे गोरखालैंड राज्य की मांग की, जिसे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे दो मंत्रियों ने तत्काल नामंजूर कर दिया. कांग्रेस के उत्साह का एक मतलब यह निकाला जा सकता है कि संभव है, वह तेलंगाना और विदर्भ राज्यों का हल भी इसी फ़ार्मूले से तलाशने की कोशिश करे.

मालूम हो कि पिछले साल 21 दिसंबर को केंद्र ने गोरखालैंड स्वायत्त प्राधिकरण का प्रस्ताव किया था, जिसे गोजमुमो ने नामंजूर कर दिया. इसके बदले 18 मार्च को उसने केंद्र को अपना प्रस्ताव दिया, जिसमें अन्य अधिकारों के अलावा न्यायिक अधिकार भी शामिल हैं. 24 जुलाई को नई दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में केंद्र ने दो सप्ताह के भीतर गोजमुमो एवं राज्य सरकार से अपनी-अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा. राज्य सरकार बाक़ी दलों को भी विश्वास में लेना चाहती थी, इसलिए 3 अगस्त की बैठक बुलाई गई. गोरखालैंड मामले के हल के लिए आमराय बनाने के मक़सद से केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने चार अगस्त को गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष सुभाष घीसिंग से भी दिल्ली में बात की. हालांकि विमल गुरुंग इससे नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि घीसिंग पहाड़ पर एक चुकी हुई ताक़त हैं, इसलिए उनसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है. ख़ैर, दूध का जला मट्ठा फूंक कर पीता है. इस बार केंद्र और राज्य सरकारें नहीं चाहतीं कि कोई भी एकतरफा फ़ैसला लिया जाए, जैसा कि दार्जिलिंग गोरखा स्वायत्त परिषद के गठन के समय हुआ था. 3 अगस्त की बैठक की राय को भी शामिल करके राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी. प्रस्तावित प्राधिकरण की मंजूरी के बारे में पूछे जाने पर गोजमुमो महासचिव रोशन गिरि ने बताया कि अभी हमने इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है.

वैसे गोजमुमो का अड़ियल रुख़ अभी भी बाधक बना हुआ है. सूत्रों के मुताबिक़, मामला अधिकारों पर नहीं, इलाक़ों पर अटक गया है. विमल गुरुंग प्राधिकरण में तराई और डुआर्स के उन इलाक़ों को भी शामिल करना चाहते हैं, जहां आदिवासियों के साथ गोरखा समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं. प्राधिकरण में वे ही क्षेत्र (दार्जिलिंग, कर्सियांग और कालिंपोंग अनुमंडल) शामिल हैं, जो पहले की पर्वतीय परिषद में थे. शायद विमल गुरुंग मानते हैं कि वह अगर कुछ और क्षेत्र शामिल कराने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें पहाड़ के लोगों को ख़ुश करने का मौक़ा मिल जाएगा. हालांकि आमरा बंगाली और दूसरे कई संगठन दायरा बढ़ाने के सख्त ख़िलाफ़ हैं. विमल गुरुंग ने आदिवासी विकास परिषद से अलग हुए गुट आदिवासी पीपुल्स पार्टी को भी मना लिया है, ताकि तराई-डुआर्स के कुछ इलाक़े को प्राधिकरण में शामिल करने की मांग दमदार हो. पर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर प्राधिकरण के गठन से दार्जिलिंग की जनता ख़ुश हो सकती है तो पर्वतीय परिषद ही क्या बुरी थी. केंद्र या राज्य से कोष न मिलने या देर से मिलने की शिक़ायत पर्वतीय परिषद के समय में भी नहीं थी, पर सुभाष घीसिंग के अलोकतांत्रिक और भ्रष्टाचारी रवैये ने उसे इतना रोगग्रस्त बना दिया कि अंततः वह लाश बन गई. इसके साथ ही एक तरह से घीसिंग की राजनीतिक मौत भी हो गई. अब पहाड़ पर एक नया सूरज उगता दिख रहा है. क्या सिर्फ़ यही काफी है कि इसमें गोरखालैंड शब्द जोड़ दिया गया है? आशंका है कि कहीं स्वायत्त परिषद एक लाल झुनझुना न बन जाए, जिसे कभी घीसिंग झुनझुनाते थे और अब विमल गुरुंग की बारी है.

feedback@chauthiduniya.com

कैसा होगा गोरखालैंड स्वायत्त प्राधिकरण

गोरखालैंड ऑटोनोमस अथॉरिटी (गोरखालैंड स्वायत्त प्राधिकरण) नामक स्वायत्त निकाय का गठन राज्य सरकार करेगी. यह अंतरिम अथॉरिटी 31 दिसंबर 2011 तक वैध रहेगी और समझौते में शामिल पार्टियां सहमत हों तो इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है. अथॉरिटी के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों के चुनाव छह माह के भीतर करा लिए जाएंगे. इसमें 20 सदस्य होंगे, जिसमें से 15 सदस्य ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों से चुनकर आने वाले राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अनुपात में मनोनीत किए जाएंगे. अन्य पांच सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल प्राधिकरण के प्रतिनिधित्वविहीन समुदायों से करेंगे. प्राधिकरण के कामकाज शुरू करने के 12 महीनों के भीतर इसके चुनाव कराए जाएंगे और कार्यकाल पांच साल का होगा. इस प्राधिकरण का क्षेत्र भी वही होगा, जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का था. नए प्राधिकरण को हिल काउंसिल से ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव है, पर यह गोरखा जन मुक्ति मोर्चा की उम्मीदों से कम है. सूत्रों के मुताबिक़ प्राधिकरण के पास होने वाले कुल 54 क्षेत्रों के संबंध में क़ानून बनाने के लिए विधानसभा तक उसकी पहुंच नहीं होगी. वह इनसे संबंधित क़ानून ख़ुद बनाएगा और राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजेगा. इस तरह उन 54 क्षेत्रों में प्राधिकरण के पास विधायी शक्तियां होंगी. इन क्षेत्रों में सड़क, वन, कृषि, शिक्षा और उच्च शिक्षा (इनमें राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान शामिल नहीं होंगे), सिल्क उत्पादन एवं फूल उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन पुलिस और ज़िला प्रशासन शामिल नहीं हैं. उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी इसके दायरे से बाहर रहेंगे. प्राधिकरण को कार्यपालिका, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए गए हैं. उसे कर्मचारियों पर नियंत्रण और उनके स्थानांतरण का अधिकार होगा. इसके अलावा राज्यपाल प्राधिकरण के कामकाज के बारे में रिपोर्ट मांग सकते हैं और अपनी सिफ़ारिशों के साथ इसे विधानसभा में पेश करने को कह सकते हैं. इसके अलावा गोरखालैंड के सुरक्षा दस्तों के सदस्यों को पुलिस, सेना और अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती किया जाएगा.

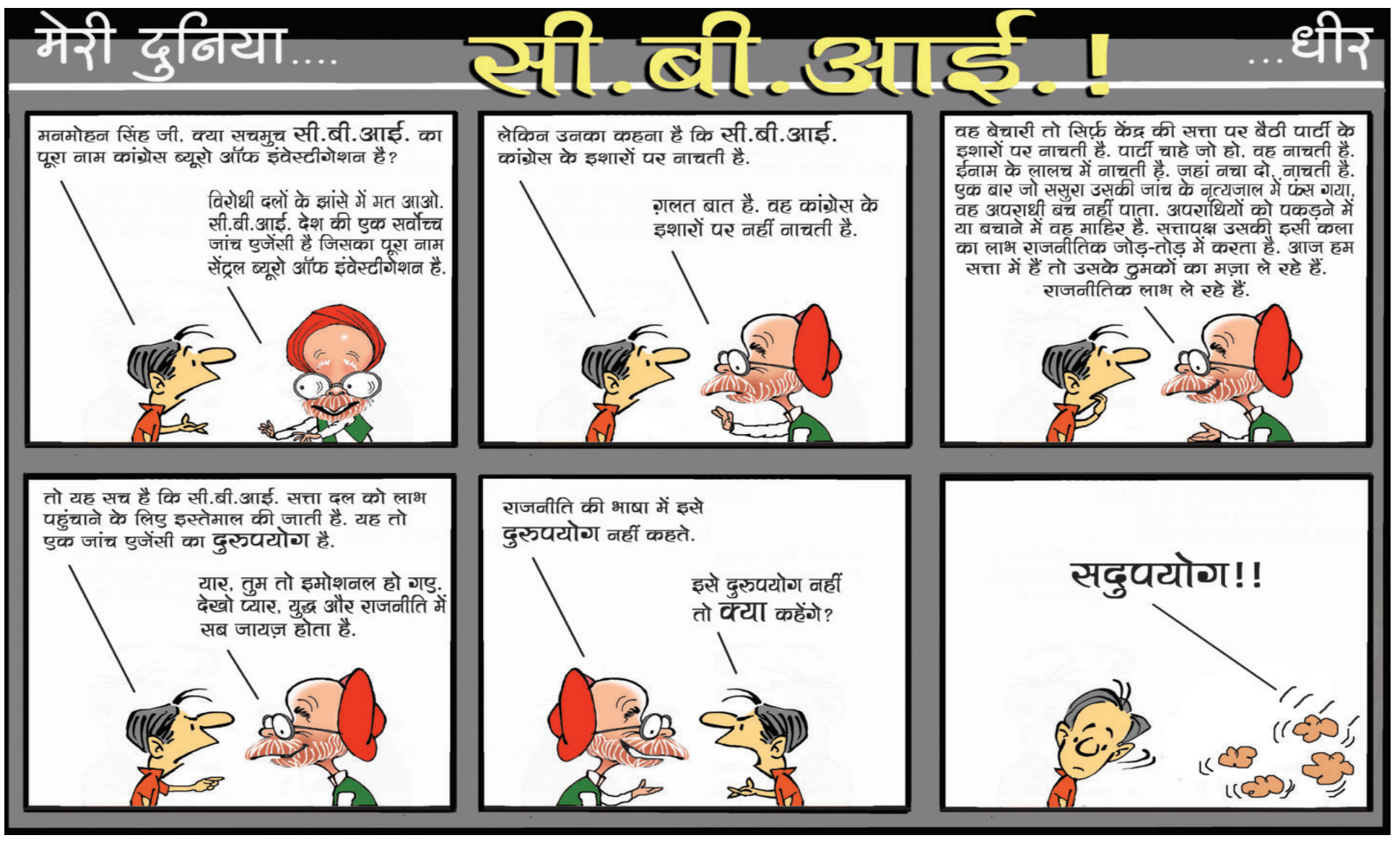

एटा ज़िले में एक दंपत्ति और उनके तीन बच्चों को महज़ इसलिए गांव से निकाल दिया गया, क्योंकि वे एड्स से पीड़ित हैं.

एड्स की चपेट में मऊ

सुरेंद्र अग्निहोत्री

पूर्वांचल का मऊ जनपद एड्स का गढ़ बनता जा रहा है. यहां एचआईवी पॉज़ीटिव लोगों की संख्या 523 हो गई है. इनमें 28 मरीज ऐसे हैं, जो लम्हा-लम्हा मौत की ओर बढ़ रहे हैं. जांच कराने वालों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात बराबर है. बताया यह जा रहा है कि बहुत से पीड़ित तो दीगर जनपदों में अपना इलाज करा रहे हैं. राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी को वर्ष 2005 में यहां एचआईवी पाज़ीटिव 14 लोग मिले थे. अगले ही वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 53 पहुंच गई. 2007 में यह संख्या 163 हो गई. 2008 में 145 नए मामले सामने आए. 2009 में 115 मरीज और बढ़ गए और कुल संख्या हो गई 423. इस वर्ष अब तक 100 नए पीड़ित सामने आ चुके हैं. पीड़ित लोगों में 283 पुरुष एवं 240 महिलाएं हैं और सभी 20-40 वर्ष आयु वर्ग के हैं. ज़िला चिकित्सालय में गुप्त एवं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. ए के रंजन बताते हैं कि इनमें 20-30 वर्ष आयु वर्ग के 28 मरीज ऐसे हैं, जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सीडी-4 गणना 200 से भी नीचे आ गई है. यानी वे अब ख़तरनाक स्टेज में हैं. उनका नियमित इलाज चल रहा है.

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के ज़िलों में एड्स पीड़ितों की बढ़ती संख्या के कारण हालात ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं. संत कबीर नगर में एड्स पीड़ित एक युवा दंपत्ति ने तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. पति सूरत में काम करता था, उसे एड्स था और पत्नी भी प्रभावित हो गई थी. फ़ैज़ाबाद के मया इलाक़े में आधा दर्जन लोग पीड़ित हैं. बीकापुर में बीते साल एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें ज़्यादातर लोग बाहर से यह बीमारी लेकर यहां पहुंचे. प्रदेश में बीते तीन वर्षों में एड्स के चलते 267 लोगों की मौत हो चुकी है. सरकार ने निर्णय लिया है कि वह जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसमें ग्राम प्रधानों की मदद ली जाएगी. यह अभियान प्रदेश भर में चलेगा, लेकिन पूर्वांचल के गोरखपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, कुशीनगर एवं महाराजगंज ज़िलों पर सरकार की विशेष नज़र है. एड्स नियंत्रण सोसाइटी की सर्वे रिपोर्ट में उक्त ज़िले एचआईवी संक्रमण के लिहाज़ से काफी संवेदनशील हैं. यहां एड्स पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है. ताजा आंकड़ों पर ग़ौर करें तो सिर्फ़ संत कबीर नगर में एड्स पीड़ितों की संख्या चार सौ के आसपास है. जागरूकता अभियान के लिए ग्राम प्रधानों को प्रचार सामग्री दी जाएगी, जिसमें इस बीमारी के लक्षणों, कारणों एवं बचाव की जानकारी दी गई है. ग्राम प्रधानों से अनुरोध किया गया है कि प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण उनका दायित्व है कि वे इलाकाई लोगों को जागरूक करें.

फ़ैज़ाबाद में 46, अंबेडकरनगर में 41, आजमगढ़ में 133, जौनपुर में 188, गाजीपुर में 98, बलिया में 93, इलाहाबाद में 192, बस्ती में 46, देवरिया में 100, लखनऊ में 387, कानपुर में 260, रायबरेली में 42, कुशीनगर में 169, सुल्तानपुर में 55, उन्नाव में 36, सोनभद्र में 30, सिद्धार्थनगर में 38, श्रावस्ती में 3, सीतापुर में 9, शाहजहांपुर में 10, संत रविदासनगर में 66, प्रतापगढ़ में 70, बलरामपुर में 25, बाराबंकी में 25, चंदौली में 39, इटावा में 59, फतेहपुर में 37, फिरोज़ाबाद में 40, गोंडा में 49, गोरखपुर में 63, कौशांबी में 28, मिर्ज़ापुर में 62 एवं रामपुर में 21 लोग जांच में एचआईवी पॉज़ीटिव पाए गए हैं.

प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री अनंत कुमार मिश्र के अनुसार, जनवरी 2004 से 31 जुलाई 2007 तक 267 लोग इस बीमारी के चलते मौत के शिकार हो चुके हैं. इस पर रोकथाम के लिए कंडोम प्रोत्साहन, रक्त सुरक्षा एवं लो कॉस्ट कम्युनिटी केयर जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं. केजीएमसी लखनऊ, मेडिकल कॉलेज मेरठ, बीएचयू वाराणसी, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ एवं मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में छह एंटी ट्रिवायरल थेरेपी केंद्रों की स्थापना की गई है. पीलीभीत में बीते पांच सालों में 40 लोग एड्स के शिकार हो चुके हैं, इनमें एक बच्चा भी शामिल है. ज़िले में इस साल अब तक नौ एड्स रोगी मिल चुके हैं. क़रीब 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एड्स दस्तक दे चुका है. मुज़फ़्फ़रनगर में इस वर्ष एड्स रोगियों की संख्या दोगुनी हो गई. क़रीब 33 लोग इस बीमारी की चपेट में हैं. शामली में भी इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नगर में एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है. सात माह के अंदर एड्स के 10 नए मामले सामने आए हैं.

उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक एस पी गोयल दावा करते हैं कि इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं. जनसामान्य में एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. रोगियों की देखभाल के लिए सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग का वातावरण तैयार करने पर बल दिया जा रहा है. उनके निवास के निकट आधुनिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 27 जनपदों में लिंक एआरटी सेंटर स्थापित किए गए हैं. वर्ष 2008 में प्रदेश में कुल 11,053 लोग एचआईवी पॉज़ीटिव एवं 3369 एड्स रोगी पाए गए.

गोयल ने बताया कि वर्ष 2008-09 में 210 एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्र (आईसीटीसी) स्थापित किए गए, इनमें से 28 नए केंद्र हैं. इनके माध्यम से मरीज़ों को चिकित्सा सुविधाएं और उनके परिवारजनों को परामर्श की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं. क़रीब 2,40,034 लोगों की जांच की गई, जिनमें 10,914 एचआईवी पॉज़ीटिव पाए गए. उनके उपचार के लिए 79 एसटीडी क्लीनिक खोले गए हैं. वर्ष 2008 में 9,72,949 रोगियों का उपचार किया गया. स्वयंसेवी संस्थाओं की उपेक्षा के कारण प्रदेश में जागरूकता अभियान कारगर नहीं हो पा रहे हैं. प्रोजेक्ट चलाने वाली संस्थाओं के चयन से लेकर कार्यक्रम के संचालन तक में दिक्कतें पैदा की जा रही हैं. प्रदेश सरकार राज्य एड्स सोसायटी को एक पूर्णकालिक परियोजना निदेशक तक नहीं दे पा रही है. सूत्रों का कहना है कि वचित्तर सिंह के बाद कोई भी परियोजना निदेशक पूर्णकालिक नहीं आया है. सोसायटी के लोग मनमानी करते रहते हैं. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. जे वी घोष कहते हैं कि एड्स की चुनौती से लड़ने के लिए जागरूकता अभियान ग्रामीणों, ख़ासकर अशिक्षित वर्ग के बीच चलाना ज़रूरी है, लेकिन सरकारी अमला राजधानी और उसके आसपास ही इस कार्य को अंजाम दे रहा है.

एटा ज़िले में एक दंपत्ति और उनके तीन बच्चों को महज़ इसलिए गांव से निकाल दिया गया, क्योंकि वे एड्स से पीड़ित हैं. डर है कि यह जानलेवा बीमारी घरवालों और अन्य लोगों को हो जाएगी. एटा के अलीगंज कस्बे में रहने वाले इंतज़ार हुसैन पिछले कई सालों से मुंबई में रहकर जूता-चप्पल का कारखाना चलाते थे. 2003 में उनकी पत्नी शाकिरा को एक बेटी शिफा पैदा हुई. उस वक़्त शाकिरा को ख़ून की ज़रूरत पड़ी तो इंतज़ार हुसैन ने ब्लड बैंक से ख़ून लाकर चढ़वा दिया. 2004 से दोनों की तबियत ख़राब रहने लगी तो उन्होंने जांच कराई, जिसमें दोनों को एड्स से पीड़ित बताया गया. दोनों ने मुंबई में काफी इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ. इलाज कराते-कराते कारखाना तक बिक गया और एक दिन वह बीवी शाकिरा और अपनी दो बेटियों मुस्कान एवं शिफा के साथ सड़क पर आ गए. आर्थिक हालत नाज़ुक हो गई और वह जून 2006 में परिवार के साथ वापस एटा आकर अलीगंज कस्बे में मां-बाप और भाइयों के साथ रहने लगे. घरवालों को जैसे ही पता चला कि दोनों एचआईवी पीड़ित हैं, उन्होंने इंतज़ार, उसकी बीवी और बच्चों को मारपीट कर घर से निकाल दिया. लेकिन एक स्थानीय ग़ैर सरकारी संस्था ने उनके जीवन में ख़ुशियां वापस लाने का बीड़ा उठाया है. संस्था के प्रमुख डॉ. सौरभ पालीवाल के अनुसार, सहभागिता बढ़ाकर सामाजिक उपेक्षा को दूर किया जा सकता है. समाज में एचआईवी को लेकर विभिन्न प्रकार के भ्रम व्याप्त हैं, जिससे पीड़ितों को कई प्रकार की सामाजिक-मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

feedback@chauthiduniya.com

बचाव ही बेहतर इलाज

गुप्त एवं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. ए के रंजन कहते हैं कि सुरक्षा एवं सावधानी बरत कर एचआईवी से बचा जा सकता है. बचाव ही इसका सबसे बेहतर इलाज है. कभी भी असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं. कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करें. विवाह के पूर्व कुंडली मिलान के साथ एचआईवी टेस्ट भी ज़रूर कराएं. बीमार पड़ने पर रक्त का आदान-प्रदान बिना एचआईवी परीक्षण के न करें.

एचआईवी जांच में रोड़े

उत्तर प्रदेश सरकार एड्स जागरूकता के लिए जहां नाको से मिलकर अनेक परियोजनाएं चला रही है, वहीं राजधानी में इस बीमारी की जांच के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हैं. बलरामपुर अस्पताल में यह जांच बीते छह माह से नहीं हो पा रही है. यहां प्रयोगशाला तो है, लेकिन लैब टेक्नीशियन के न होने से जांच कार्य बाधित है. लिहाज़ा यहां एचआईवी की जांच के लिए आने वाले लोगों को डफरिन अस्पताल और चिकित्सा विश्वविद्यालय भेज दिया जाता है.

उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक एस पी गोयल दावा करते हैं कि इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं. जनसमाव्य में एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. रोगियों की देखभाल के लिए सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग का वातावरण तैयार करने पर बल दिया जा रहा है.

इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन फ़र्ज़ी मुठभेड़ कांड की जांच सीबीआई को सौंपते हुए कहा था कि वह इस मामले की जांच नए सिरे से शुरू करे और उसे अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर सौंपे.

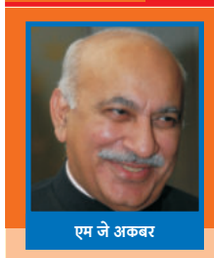

एम जे अकबर

क्रोध और इतिहास की आग में जलता कश्मीर

जनरल अशफाक कयानी को अगस्त, 1971 में पाकिस्तानी सेना में प्रवेश मिला था. सेना में उनके समतुल्य दूसरे फोर स्टार जनरल तारिक़ मजीद हैं, जो सात अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ख़ालिद शमीम वाईं अगले साल 8 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और कयानी से कुछ महीने ही जूनियर हैं. आर्मी स्ट्रेटजिक फोर्सेज की कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अबसार हुसैन 1971 में क्वेटा स्थित कमांड एवं स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे थे और 1972 में विधिवत रूप से सेना में शामिल हुए थे. आईएसआई के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा उम्र में कयानी के बराबर हैं और उन्हीं की तरह सेवा विस्तार हासिल कर चुके हैं. क्वेटा स्थित दक्षिणी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जावेद जिया, 1 कॉर्प्स की कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद मुस्तफा ख़ान और वी कॉर्प्स के मुखिया शाहिद इक़बाल जैसे अधिकारी भी इसी साल या अगले साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं. पाकिस्तानी सेना के शीर्ष पदों पर क़ाबिज़ इन अधिकारियों के बीच क्या समानता है? ये सभी उस पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं, जो मानसिक सदमे में रही है. ये अधिकारी उस सेना में शामिल हुए थे, जिसे 1971 की लड़ाई में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. इस युद्ध में पाक सेना के 90 हजार से भी ज़्यादा जवानों को भारतीय सेना के एक जनरल के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. इतना ही नहीं, इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा और बांग्लादेश का उदय हुआ था. हाल के सालों में देश में व्याप्त गृहयुद्ध जैसे हालात से मुक़ाबला करने को छोड़ दें तो अपने पूरे करियर में कयानी बस इसी एक युद्ध में शरीक़ रहे हैं, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया. कयानी की पीढ़ी के इन अधिकारियों के दिलों के ज़ख्म कभी पूरी तरह भर नहीं पाए और वे इस पराजय की आग में हमेशा जलते रहे हैं. इस पीढ़ी की बस एक ही तमन्ना रही है, कश्मीर के रास्ते बांग्लादेश का बदला. वह चाहती है कि यह बदला उनके करियर के दौरान ही पूरा हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो उनके जीवनकाल में तो हो ही जाना चाहिए. इस कट्टरपंथी पीढ़ी का गुस्सा कभी इसलिए कम नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सोच में जिहाद पर निकली मुसलमानों की एक सेना को हिंदू सेना से पराजित होना पड़ा था. यदि अगले पांच सालों में कश्मीर की हैसियत में कुछ बदलाव आता है तो इस पीढ़ी के धार्मिक-राष्ट्रवादी सपने हक़ीक़त में तब्दील हो जाएंगे. बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के नज़रिए पूरी तरह अलग हैं. हमारा मानना है कि 1971 में भारतीय सेना की दखलंदाज़ी एक अयोग्य राष्ट्रपति याहया ख़ान और अहंकार के उन्माद में डूबे एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ जुल्फिकार अली भुट्टो के आत्मघाती कदमों का एक नतीजा था. 5 दिसंबर की रात को पाकिस्तानी वायु सेना के हमलों के बाद इसका कोई विकल्प नहीं बचा था. भारत यह भी मानता है कि नस्लीय आधार पर कई ग़लत फ़ैसले लेने के बाद

पाकिस्तानी नेतृत्व ने जब शेख मुजीबुर्रहमान को सरकार बनाने का मौक़ा देने से मना कर दिया तो ऐसा होना ही था. ऐसा तब हुआ, जबकि शेख मुजीब आम चुनावों में बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे थे.

1971 की लड़ाई के चार दशक बाद पाकिस्तान आज यह उम्मीद कर रहा है कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर के याहया ख़ान बन जाएंगे और वह घटनाओं को कुछ ऐसा रंग देने की कोशिश कर रहा है, जिससे एक छोटी सी ग़लती भी गंभीर समस्या में तब्दील हो जाए. दिल्ली में सत्ता के अलंबरदारों को यह कोरी कल्पना भले लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि कश्मीर के ताज़ा घटनाक्रम से इस्लामाबाद में उम्मीद का माहौल है. पाकिस्तान के साथ कश्मीर के विलय की पक्षधर जमाते इस्लामी कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही है. राज्य के हर गली-मोहल्ले में यह नारा बुलंद किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उमर अब्दुल्ला भले क़ाबिज़ हों, लेकिन सत्ता तो सैयद अली शाह गिलानी के हाथों में ही है. सीमा के दूसरी ओर से पाकिस्तान समर्थित हिजबुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन अपने भाषणों में लोगों से सड़कों पर निकलने की अपील कर रहे हैं. लाउडस्पीकरों में बज रहे उनके भाषणों में लोगों को संघर्ष और तेज़ करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि जीत उनके क़रीब आ चुकी है. कश्मीर में हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे, इसका पहले से कोई अंदाज़ा नहीं था. पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव इतने शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए कि हर कोई इसे अपनी कामयाबी मान आत्मविभोर होने लगा. शांति के इस वातावरण से पहले आत्मीय संतोष पैदा हुआ, जो जल्द ही अति आत्मविश्वास में तब्दील हो गया. 11 जून को एक आदमी की मौत हुई, जिसे केवल एक साधारण घटना मान लिया गया. दिल्ली की सत्ता को नींद से जगने में दो महीने लग गए. इसके बाद भी घाव पर मरहम लगाने के लिए उसके पास घिसे-पिटे बयानों के अलावा और कुछ नहीं था. प्रशासन ने देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आप पूरी भीड़, पूरे शहर को गोली नहीं मार सकते.

एक अनुमान के मुताबिक़, जून से लेकर अगस्त के पहले सप्ताह तक कश्मीर में लगभग 40 लोगों की मौत हो चुकी है. उधर कराची में अपने शिया नेता सैयद रजा हैदर की हत्या से उग्र हुए मुहाजिरों ने 80 से ज़्यादा पश्तूनों की हत्या कर दी और सैकड़ों घायल हैं. यह कोई हिंदू-मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि मुसलमानों के बीच का आपसी फसाद था. मुहाजिर वे लोग हैं, जो 1947 में विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से अपने सपनों के देश में पहुंचे थे. छह दशक बाद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए निजी सेना का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहां के मूल वाशिंदे पठान उन्हें देखना नहीं चाहते.

इतिहास का यह कैसा शर्मनाक पल है, जिसमें दो देशों की हालत की तुलना मरने वालों की संख्या के आधार पर किया जाता है. एक तथ्य हमारे सामने है, साल 1947 ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों को असंतुलित कर दिया. समाज में मिलजुल कर रहने वाला यह समुदाय बेवजह के डर, हिंसक क्रोध और कभी पूरे न होने वाले सपनों में इस कदर उलझा कि राजनीतिक और मानसिक रूप से टुकड़ों में बंट गया. कश्मीर के मुसलमानों को यदि यह लगता है कि वे स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं तो वे ग़फ़लत में हैं. उन्हें न तो भारत की समझ है, न ही पाकिस्तान की.

सेना के अधिकारी अस्थायी होते हैं, एक निश्चित समय सीमा के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है. पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी लाशों की गिनती नहीं करते, क्योंकि उनकी नज़र में मौतें तो किसी लड़ाई में आंकड़ा भर हैं. लोकतंत्र किसी एक पीढ़ी की दुर्भावनाओं से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है. यह ऐसी शासन व्यवस्था की मांग करता है, जो किसी समूह विशेष की इच्छाओं पर निर्भर न हो. भारत इन आंकड़ों की अनदेखी नहीं कर सकता, न ही पाकिस्तानी नज़रिए को अपना सकता है. कश्मीर की गलियों में रोज़ हो रही मौतों ने राज्य सरकार की योग्यता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि आम जनता का मूड नहीं बदला तो सरकार को ही बदलना होगा.

feedback@chauthiduniya.com

सोहराबुद्दीन प्रकरण : मिटते नहीं निशां लहू के

ज़ाहिद ख़ान

सोहराबुद्दीन फ़र्ज़ी मुठभेड़ कांड मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनकर रह गया है. राज्य के पुलिस महकमे और सीआईडी के अफसरों की गिरफ़्तारी के बाद गुजरात के गृहमंत्री अमित शाह भी आख़िरकार क़ानून के शिकंजे में फंस ही गए. सोहराबुद्दीन फ़र्ज़ी मुठभेड़ कांड और उसकी बीवी कौसर बी एवं दोस्त तुलसी प्रजापति की हत्या की साजिश में सीबीआई ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है. सीबीआई की चार्जशीट में अमित शाह पर हत्या, हत्या की साजिश, आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, ज़बरन वसूली, बंधक बनाने और सबूत नष्ट करने जैसे कई संगीन इल्ज़ाम हैं. कुल मिलाकर सीबीआई की चार्जशीट में 15 आरोपी हैं, जिनमें मुख्य आरोपी के तौर पर अमित शाह का नाम है. सीबीआई ने अब तक की अपनी तहक़ीक़ात में शाह के ख़िलाफ़ ढेर सारे सबूत जुटाए हैं. इस मामले में गुजरात पुलिस कई आईपीएस अफसरों को पहले ही गिरफ़्तार कर चुकी थी, लिहाज़ा सीबीआई को सबूत जुटाने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई. पुलिस अफसरों से पूछताछ और मोबाइल फोन रिकॉर्ड की बिना पर सीबीआई ने पाया कि फ़र्ज़ी मुठभेड़ में शामिल पुलिस अफसर घटना के दौरान, घटना के पहले और उसके फ़ौरन बाद भी शाह से लगातार संपर्क बनाए हुए थे. सीबीआई का मानना है कि उक्त फ़र्ज़ी मुठभेड़ उन्हीं के इशारे पर अंजाम दी गई.

एक गृह राज्यमंत्री जिस पर सूबे की क़ानून व्यवस्था संभालने और अवाम के हक़ों की हिफ़ाज़त करने की अहम ज़िम्मेदारी होती है, उस पर और उसके पुलिस महकमे पर इस तरह के इल्ज़ाम यह साबित करते हैं कि गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. चमकते-दमकते गुजरात के चेहरे के पीछे एक चेहरा और भी है, जो बेगुनाहों के ख़ून से रंगा है. ग़ौरतलब है कि इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन फ़र्ज़ी मुठभेड़ कांड की जांच सीबीआई को सौंपते हुए कहा था कि वह इस मामले की जांच नए सिरे से शुरू करे और उसे अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर सौंपे. जैसा कि जांच के पहले अंदेशा था, ठीक वैसा ही हुआ. इस मामले में गुजरात पुलिस के साथ-साथ अमित शाह भी दोषी निकले. सीबीआई के पास ऐसे कई सबूत हैं, जो शाह की इस मामले में साफ़-साफ़ संलिप्तता बतलाते हैं. सीबीआई की तीन हज़ार पन्नों की लंबी चार्जशीट के मुताबिक़, अमित शाह ने सोहराबुद्दीन को मारने का काम बंजारा, पांडियन और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के तत्कालीन

प्रमुख अभय चूडास्मा को सौंपा था. गवाहों के बयानों में अमित शाह के शामिल होने की बात कई बार निकल कर आई है. हालांकि अमित शाह ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से ही गवाहों को धमकाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाए. कोर्ट में दाख़िल अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने शाह पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अपने क़रीबी अजय पटेल और यशपाल चूडास्मा को यह काम ख़ास तौर पर सौंपा था. फ़िलवक़्त पटेल और चूडास्मा दोनों ही फरार हैं.

सीबीआई की जांच से 3 साल पहले यानी साल 2007 में गुजरात सीआईडी ने भी अपनी जांच में सोहराबुद्दीन से हुई मुठभेड़ को फ़र्ज़ी पाया था और उसके बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीकी पुलिस अफसर उप महानिरीक्षक (सीमा क्षेत्र) डी जी बंजारा, ख़ुफ़िया विभाग के पुलिस अधीक्षक राजकुमार पांडियन एवं राजस्थान के पुलिस अफसर एम एन दिनेश समेत कई पुलिस वालों को गिरफ़्तार किया था. गुजरात सरकार की इस कार्रवाई के बाद भी सोहराबुद्दीन शेख का परिवार संतुष्ट नहीं हुआ. उसने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, लेकिन मोदी सरकार सीबीआई जांच से कतराती रही और उसने अपनी तरफ़ से मामले की जांच की संस्तुति नहीं की. मजबूरन फरियादी को इंसाफ़ के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. फैसला फरियादी के पक्ष में हुआ. दरअसल गुजरात पुलिस की रिपोर्टों में ऐसे कई सवाल थे, जो अभी तक अनसुलझे थे और इन्हीं सवालों का जवाब सोहराबुद्दीन शेख का परिवार चाहता था. इस मामले में केवल पुलिस अफसरों को मोहरा बनाकर गुजरात सरकार का बेदाग बने रहना किसी के भी गले नहीं उतर रहा था. यह कैसे मुमकिन है कि सूबे में कोई बड़ा एनकाउंटर हो और सरकार, उसके गृहमंत्री पूरी तरह से अंजान रहें. राज्य सरकार यदि वाकई निर्दोष थी तो वह इस मामले की जांच सीबीआई से कराने से क्यों बचती रही. सच तो यह है कि मोदी सरकार ने पहले तो फ़र्ज़ी मुठभेड़ की असलियत को ही नकारा. जब उस पर सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा, तब जाकर उसने यह जांच शुरू कराई. जांच में जब पुलिस अफसरों की संलिप्तता के साथ-साथ सूबे के वरिष्ठ नेताओं के नाम भी आते दिखे तो पहले उसने इस मामले की जांच अधिकारी गीता जौहरी पर अपनी रिपोर्ट रोकने और फिर बदलने का दबाव डाला. अमित शाह ने दागी पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ मुक़दमे दर्ज न करने का हुक्म भी दिया. गीता जौहरी द्वारा इंकार करने पर उन्हें इस मामले से अलग कर दिया गया और मामला दूसरे अधिकारी को सौंप दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही गुजरात सरकार ने गीता जौहरी को दोबारा जांच सौंपी. तब जाकर फ़र्ज़ी मुठभेड़ की सच्चाई दुनिया के सामने आई.

अब जबकि सीबीआई की तहक़ीक़ात एक तर्कसंगत मुक़ाम पर पहुंचने को है और रोज नए राज खुल रहे हैं तो भाजपा इसे सियासी रंग देकर अमित शाह को बचाने में लग गई है. वह यह राग अलाप रही है कि कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग कर अमित शाह को फंसाया है. सोहराबुद्दीन और उसकी बीवी कौसर बी एवं दोस्त तुलसी प्रजापति की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश केंद्र सरकार ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. इस मामले से संबंधित अपनी सारी कार्रवाई के लिए सीबीआई केंद्र सरकार के प्रति नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है. यानी अभी तक की सारी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है. यदि अमित शाह बेगुनाह हैं तो वह इतने दिनों से सीबीआई की पूछताछ से क्यों बचते फिर रहे थे. दरअसल सीबीआई को पहले से ही यह अच्छी तरह मालूम था कि उसकी जांच पर इस तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं. लिहाज़ा उसने अपनी 5-6 माह की जांच में पहले पुख्ता सबूत जुटाए, तब जाकर अमित शाह पर हाथ डाला.

अमित शाह एवं गुजरात सरकार को बचाने के लिए भाजपा एवं नरेंद्र मोदी मुल्क के सामने एक और दलील पेश कर रहे हैं कि सोहराबुद्दीन एक अपराधी था, लिहाज़ा उसकी हत्या सही है. लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने सोहराबुद्दीन को आतंकवादी करार देकर उसे मार गिराने के लिए अपने पुलिस महकमे की हौसला अफजाई की थी. जांच में फ़र्ज़ी मुठभेड़ साबित होने के बाद भी उन्होंने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देकर पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. भाजपा और नरेंद्र मोदी की इस मुहिम में उस वक़्त उनका मातृ संगठन आरएसएस भी शामिल था. पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देते हुए उसने कहा था कि मोदी आलोचना के नहीं, बल्कि सलाम के हक़दार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जबसे इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, तबसे ही भाजपा और उसके नेता इस जांच पर सवाल उठाकर इसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. यह कोई पहली बार नहीं है, जब भाजपा नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रही है. गुजरात दंगों के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को जब फटकार लगाई थी, तब भी कमोबेश भाजपा का उनके प्रति यही रवैया था. उसका ताजा रवैया एक बार फिर बताता है कि अदालत और क़ानूनों का वह कितना सम्मान करती है. एक मंत्री जिस पर हत्या, हत्या की साजिश, अपहरण और जबरन धन उगाही के संगीन मामले दर्ज हुए हों, उसे बचाना कहीं न कहीं उसके किरदार की भी निशानदेही करता है. अलग चाल, चरित्र और चेहरे का दावा करने वाली भाजपा का असली चेहरा वास्तव में क्या है?

feedback@chauthiduniya.com

स्त्री को सम्मान दें

साहित्य पेज पर छपा आलेख-नागपाश में स्त्री बिल्कुल सही तस्वीर दर्शाता है. हमारे समाज में औरत को एक मशीन माना जाता है. इस पर आधारित किताब की जानकारी भी मिली, जिसमें साहित्य के अलावा अन्य क्षेत्रों की महिलाओं के भी लेख हैं.

-रीना राठौर, *दरभंगा, बिहार.*

हादसों से कैसे निपटेगी सरकार?

आवरण कथा-एक बम दिल्ली ख़त्म पढ़ी और चौंक गया कि क्या ऐसा हो सकता है? सच तो यह है कि जिस देश की सरकार हर साल बाढ़ आने से होने वाले नुक़सान को रोकने के उपाय आज तक नहीं कर पाई, वह ऐसे किसी हादसे को रोकने के उपाय कैसे करेगी.

-सलीम अख्तर सिद्दीकी, *मेरठ, उत्तर प्रदेश.*

नरसिंह का अद्‌भुत रूप

भगवान नरसिंह के शांत और लोक कल्याणकारी रूप के बारे में पहली बार जानकारी मिली कि वहां आज भी अखंड ज्योति जलती है, जो श्रद्धालुओं के कष्टों को दूर करती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस पावन स्थल के दर्शन मात्र से एक कल्प यज्ञ का फल प्राप्त होता है.

-सरिता सिंह, *जबलपुर, मध्य प्रदेश.*

महिलाएं हर क्षेत्र में अव्वल

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख माओवादियों के ख़िलाफ़ लालगढ़ की महिलाएं ने महिलाओं की भागीदारी का एक अद्‌भुत नमूना पेश किया है. वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और न्याय के लिए लड़ भी सकती हैं. पहले माओवादियों के ख़िलाफ़ आगे आने को कोई तैयार नहीं होता था, लेकिन महिलाओं के इस कदम ने एक नई क्रांति छेड़ दी है.

-किशोर कुमार, *मिदनापुर, पश्चिम बंगाल.*

श्रावणी मेले का हाल

विश्व के सबसे बड़े श्रावणी मेले की हालत को चौथी दुनिया ने बखूबी उजागर किया है. सच है कि यहां जलार्पण की व्यवस्था लचर होने के साथ-साथ सुल्तानगंज से देवघर तक सभी सरकारी व्यवस्थाएं सिर्फ नाममात्र हैं. सरकार को जल चढ़ाने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए.

-शंकर शर्मा, *बेगूसराय, बिहार.*

बधाई

चौथी दुनिया को बुक स्टॉल पर देख सुखद अनुभव हुआ. अपने तेवर कायम रखते हुए सबसे अलग खबर देने के लिए आपको बधाई. अखबार में संपादकीय और एम जे अकबर का आलेख अपनी अनूठी शैली के लिए अलग ही रंग जमाता है.

-संदीप कुमार, *स्टेशन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

नक्सलवाद ग़रीबी की उपज

नक्सलवाद मसले पर मीडिया में वास्तविक कारणों का उल्लेख न करके सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर सुधार का सुझाव देकर सरकारी नीतियों के समर्थन वाले आलेख ही प्रकाशित हो रहे हैं. मेरा मानना है कि गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमताओं की वजह से ही नक्सलवाद का जन्म हुआ है.

-नित्यानंद सिंह, *धनबाद, झारखंड.*

खाद्य प्रसंस्करण की पहल

9-15 अगस्त के अंक में छपा लेख अंडमान में खाद्य प्रसंस्करण की पहल क़ाबिलेतारीफ़ है. इस पहल से वहां के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी. प्रशासन की ओर से प्रसंस्कृत उत्पादों की मार्केटिंग का भी भरोसा दिलाया गया है, लेकिन कितना वक्त लगेगा, इसका पता नहीं.

-अमर सिंह, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

कमाल का कार्टून

9-15 अगस्त के अंक में मेरी दुनिया पेज पर प्रकाशित कार्टून सीबीआई और नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया लगा. मैं आपके अखबार का नियमित पाठक हूं और मुझे यह कॉलम पढ़ना रोचक लगता है.

-सुनील कुमार, *हरदोई, उत्तर प्रदेश.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

अब सुप्रीम कोर्ट से ही आशा है

न्याय का मूल सिद्धांत बदल रहा है, उसे बदल भी देना चाहिए. जब हमारे मन में उसके लिए कोई न इज़्ज़त हो, और न कोई जज़्बा, तो यही करना उचित है. मूल सिद्धांत है चाहे सौ अपराधी छूट जाएं, पर किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. अब अलिखित सिद्धांत में पुलिस का भरोसा है कि एक अपराधी को बचाने के लिए सौ निर्दोषों को सज़ा देनी चाहिए. सोहराबुद्दीन और इशरत जहां इसके उदाहरण हैं, ये इसलिए उदाहरण नहीं हैं, क्योंकि ये मुसलमान हैं, बल्कि ग़ैर मुसलमानों में यह प्रतिशत बहुत ज़्यादा है. ये दोनों उदाहरण भी अचानक, कुछ लोगों के न्याय के लिए लड़ने के पागलपन की वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और फिर सीबीआई ने इनकी जांच की. उस जांच ने कुछ ऐसे तथ्य खोले, जिन पर अगर आज ध्यान नहीं दिया गया तो कल भाजपा हो या कांग्रेस, या कोई और राजनीतिक दल, या तो शिकार बनेगा या शिकार बनाएगा.

क्या अमित शाह अवैध वसूली का धंधा चलाते थे, और सोहराबुद्दीन उनके इस धंधे का एक पुर्जा था? अगर था भी, तो यह तो साबित हो गया कि उसे ज़िंदा पकड़ा गया और फिर मारकर मुठभेड़ में मरा दिखा दिया गया. उसकी पत्नी कौसर बी ने जब अपने पति के साथ जाने की ज़िद की तो गुजरात एटीएस के अधिकारियों ने पहले तो उसे भगाना चाहा, फिर अपने साथ ले गए. उसके साथ दो दिन और दो रातों में क्या हुआ, सीबीआई इस पर ख़ामोश है, पर हमारी जांच कहती है कि उन दो दिन और दो रातों तक उसका बलात्कार हुआ, बाद में उसे ज़हर का इंजेक्शन दे मार दिया गया.

इससे पहले इशरत जहां केस में भी यही हुआ. पटना की रहने वाली ग़रीब घर की लड़की अपने मित्र के साथ पकड़ ली जाती है और नरेंद्र मोदी को मारने आई आत्मघाती दस्ते की सदस्य बताकर उसे मार दिया जाता है. उस फार्म हाउस के मालिक ने, जहां कौसर बी को रखा गया था, बयान दिया कि इसके पहले इशरत जहां को भी यहां रखा गया था तथा उसके साथ भी बलात्कार हुआ था, बाद में मार दिया गया. इसीलिए गुजरात उच्च न्यायालय ने दो हज़ार चार में पुलिस की मुठभेड़ थ्योरी को ग़लत मानते हुए इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम को सौंप दी है. इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच मजिस्ट्रेट तमांग ने की थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सात सितंबर, 2004 की मुठभेड़ फ़र्ज़ी है और इसे पुलिस अधिकारियों ने अपने निजी हितों के लिए अंजाम दिया था.

अगर ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट कहे कि अपने साथ हुई ज़्यादतियों का ब्यौरा देने वालों को जान माल का संरक्षण क़ानून देगा तो क्या मुसलमान और क्या हिंदू या क्या ईसाई और क्या जैन, हज़ारों की लाइन लग जाएगी, जो बताएगी कैसे उनके साथ पुलिस ने ज़्यादतियां कीं, बलात्कार किए और उनके घर वालों को स्वार्थ पूर्ति के लिए मार दिया. ऐसे केस सामने आ गए हैं, जिनमें साबित हुआ है कि पुलिस वाले ही एनकाउंटर में मारने की सुपारी लेते हैं और मार देते हैं.

अफ़सोस की बात है कि ऐसे केस सामने भी आते हैं, थोड़ी देर शोर भी मचता है और फिर कुछ नहीं होता. हमारी न्याय प्रक्रिया अपराधियों को बचा देती है, परिणामस्वरूप अपराध रोकने वालों के बीच अपराधी गिरोह बनने का सिलसिला चलता रहता है. सरकार और विपक्ष को बिना राजनैतिक हितों को ध्यान में रख उस पर सोचना चाहिए. लेकिन हमें पता है कि न सरकार सोचेगी और न विपक्ष सोचेगा.

इसे न सोचने का परिणाम अब सामने आ रहा है. पुलिस आम जनता के निशाने पर आ गई है. देश में जहां भी पुलिस के लोग आंदोलित लोगों के सामने आते हैं, उनके गुस्से का शिकार हो जाते हैं. नक्सलवादी इलाक़ों में तो हालत बहुत ख़राब है, वहां पुलिस जंगल में या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती. बहुत सी जगहों पर तो जहां उसकी चौकियां हैं, वहां अपने हथियार और अपनी जान बचाने के लिए वह नक्सलवादियों को हफ्ता देती है. यह भी विडंबना है कि हफ्ता वसूलने का आरोप झेलने वाली पुलिस अब स्वयं हफ्ता दे रही है. जहां स्थिति ख़राब होती है, वहां पुलिस असफल साबित होती है और अर्धसैनिक बलों की मांग आनी शुरू हो जाती है. चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, दंगा हो या नक्सलवादी समस्या हो, या तो अर्धसैनिक बलों को बुलाया जाता है या सेना को.

कई कमीशन बने कि पुलिस को ज़िम्मेदार बनाने, सक्षम बनाने और नागरिकों की सहायता योग्य बनाने के लिए उसकी पूरी ट्रेनिंग शिक्षा को आमूल बदला जाए, जिसकी सिफ़ारिशें उन्होंने कीं. पता नहीं कहां हैं सिफारिशें, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया. सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन पुलिस की गुणवत्ता दिनोंदिन घटती जा रही है.

इसलिए जब इशरत जहां और सोहराबुद्दीन जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो आम मान ली गई हैं. कौन इस स्थिति को सुधारेगा, कौन पुलिस को ज़िम्मेदार बनाएगा, पता नहीं, पर आशा अच्छे की करनी चाहिए. इतना ज़रूर है कि अगर आशा संसद से नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आशा नहीं टूटी है. सुप्रीम कोर्ट को इस देश की पूरी पुलिस व्यवस्था को तत्काल सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. यह मामला अनाज सड़ने और अनाज को ग़रीबों में बांटना चाहिए जैसी सलाह से थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान न दिया तो पुलिस व्यवस्था पूरी तरह सड़ जाएगी और देश को क़ानून व्यवस्था के तूफ़ान में झोंक देगी.

क्या अमित शाह अवैध वसूली का धंधा चलाते थे, और सोहराबुद्दीन उनके इस धंधे का एक पुर्जा था? अगर था भी, तो यह तो साबित हो गया कि उसे ज़िंदा पकड़ा गया और फिर मारकर मुठभेड़ में मरा दिखा दिया गया. उसकी पत्नी कौसर बी ने जब अपने पति के साथ जाने की ज़िद की तो गुजरात एटीएस के अधिकारियों ने पहले तो उसे भगाना चाहा, फिर अपने साथ ले गए. उसके साथ दो दिन और दो रातों में क्या हुआ, सीबीआई इस पर ख़ामोश है, पर हमारी जांच कहती है कि उन दो दिन और दो रातों तक उसका बलात्कार हुआ, बाद में उसे ज़हर का इंजेक्शन दे मार दिया गया.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

पॉस्को परियोजना : घपलेबाज़ी की अंतहीन कहानी

कांची कोहली

उड़ीसा में 54000 करोड़ के निवेश से स्टील प्लांट लगाने को प्रयासरत पॉस्को कंपनी की अनैतिक कार्रवाइयों की लिस्ट काफ़ी लंबी है. प्लांट के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस में घपलेबाज़ी की बात अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि एक और मामला सामने आ गया. स्थानीय लोगों के प्रतिरोध का समर्थन कर रहे सिविल सोसायटी समूहों ने यह ख़ुलासा किया कि पॉस्को ने खनन कार्य के लिए क्लियरेंस नहीं लिया है. खनन का यह क्षेत्र उड़ीसा के सुंदरगढ़ ज़िले में खांदाधार की पहाड़ियों में स्थित है. हालांकि पारिस्थितिकीय रूप से कमज़ोर इस इलाके के लोग अपने जीवन और जीविका के लिए इन्हीं जंगलों पर पूरी तरह आश्रित हैं, लेकिन खनन कार्यों के लिए इस पर कई लोगों की नज़र टिकी हुई है. पॉस्को की योजना में देरी इसलिए हुई, क्योंकि इस इलाके को पहले कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड के लिए सुरक्षित रखा गया था. सेंट्रल इम्पॉवर्ड कमेटी (सीईसी) ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया और अलग-अलग परियोजनाओं के लिए इस वन क्षेत्र को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने की नीति की आलोचना की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की रिपोर्ट के एक हिस्से पर ही ध्यान दिया और 8 अगस्त, 2008 को एक कमेटी के गठन का आदेश दिया. अदालत ने फॉरेस्ट क्लियरेंस से इंकार नहीं किया और यह व्यवस्था दी थी कि कमेटी की जांच-पड़ताल के बाद ही इस पर कोई फ़ैसला लिया जाएगा.

फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का उल्लंघन

क्लियरेंस की प्रक्रिया लंबी खिंचती रही तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों का प्रतिरोध भी जारी रहा. इसका परिणाम यह हुआ कि पॉस्को प्रस्तावित स्थल पर परियोजना से संबंधित किसी काम को अंजाम देने में सफल नहीं रही. आख़िरकार दिसंबर, 2009 में कंपनी को फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया गया, लेकिन क्या यह वैध है? यदि हम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनवासियों के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 (एफआरए) के प्रावधानों पर नज़र दौड़ाएं तो इसकी वैधानिकता पर सवाल खड़े हो जाते हैं. इस क़ानून के अंतर्गत 13 दिसंबर, 2005 से पहले किसी ख़ास वन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जंगलों के इस्तेमाल के अधिकार का ध्यान रखना ज़रूरी है. इस क़ानून के प्रावधानों को जनवरी, 2008 में सार्वजनिक किया गया था. स्पष्ट है कि स्थानीय निवासियों के जंगल पर अधिकार संबंधी दावों का निष्पादन किए बग़ैर कंपनी को यह फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिया जा सकता था. यह इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि धिनकिया गांव की पल्ली सभा ने पहले ही इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया था. प्रस्ताव में यह भी उल्लिखित था कि स्थानीय लोग वन क्षेत्र के किसी अन्य इस्तेमाल को राजी नहीं हैं. ग़ौरतलब है कि इस प्रस्ताव के पारित किए जाने तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी. 30 जुलाई, 2010 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस बाबत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें न केवल पॉस्को, बल्कि इस तरह की हर परियोजना को फॉरेस्ट क्लियरेंस देने से पहले स्थानीय समुदायों के जंगल पर अधिकार से संबंधित दावों का निपटारा जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद पांच महीनों के अंदर पॉस्को को फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया गया, जबकि एफआरए के प्रावधानों की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी. हालांकि इसमें यह उल्लेख ज़रूर किया गया था कि क्लियरेंस का यह निर्णय तभी प्रभाव में आएगा, जब एफआरए की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. एफआरए के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े मामलों को जब वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के ध्यान में लाया गया तो मंत्रालय ने 8 जनवरी, 2010 को एक नोट जारी करके फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यक शर्तों को दोबारा स्पष्ट किया. इसमें यह लिखा है कि ऐसे किसी भी क्लियरेंस से पहले स्थानीय जनजातियों के जंगल पर अधिकारों की सुरक्षा ज़रूरी है. लेकिन यहां सवाल यह है कि मंत्रालय ने पॉस्को को दिए गए फॉरेस्ट क्लियरेंस को रद्द क्यों नहीं किया, जबकि यह फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रावधानों और ख़ुद वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप नहीं था.

समय सीमा न बढ़ाने की शर्त

22 जून, 2010 को राज्य सरकार और पॉस्को के बीच हुए करारनामे की अवधि समाप्त हो गई. संभव है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा हो. यह भी हो सकता है कि राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसके लिए सहमति भी दे दी हो. लेकिन एमओयू की एक शर्त के मुताबिक समय सीमा बढ़ाने पर पाबंदी है. शर्त के मुताबिक़, यदि पांच साल के अंदर कंपनी प्रस्तावित स्थल पर निर्माण और निवेश के क्षेत्र में संतोषजनक काम नहीं करती है तो राज्य सरकार समय सीमा बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी. एमओयू के मुताबिक़, परियोजना के पहले चरण में 6 मेगा टन स्टील के उत्पादन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. परियोजना स्थल पर कोई काम नहीं हुआ है और इस वजह से करारनामे की अवधि का विस्तार संभव नहीं है. लेकिन अब इस मामले में राज्य सरकार क्या रुख़ अपनाती है, यह देखना रोचक होगा. कहीं सरकार पॉस्को के साथ नए एमओयू की तैयारी तो नहीं कर रही? यदि ऐसा हुआ तो क्या कानून के मुताबिक उसे क्लियरेंस के लिए दोबारा उसी प्रक्रिया से गुज़रना होगा? चाहे जो भी हो, लेकिन स्थानीय लोगों को इन क़ानूनी उलझनों से ख़ास लेना-देना नहीं है. अहम बात यह है कि परियोजना के विरोध को लेकर वे अब भी एकमत हैं. यह भी स्पष्ट है कि क़ानूनी अड़चनों और लोगों के विरोध के चलते पॉस्को पिछले पांच सालों में प्रस्तावित स्थल पर कोई काम नहीं कर पाई है और इसके लिए स्थानीय निवसियों को बधाई देनी चाहिए.

पर्यावरण मंत्रालय ने लगाई रोक

लगातार विवादों में घिरे पॉस्को प्रोजेक्ट को एक और झटका लगा, जब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले 8 अगस्त को प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम कामों पर रोक लगा दी. राज्य सरकार को भेजे एक निर्देश में मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के सबूत मिले हैं और इससे जुड़े सभी कार्यों को तत्काल रोक दिया जाए. केंद्र सरकार का यह फ़ैसला एन सी सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट के आलोक में लिया गया है. सक्सेना कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस देने के मामले में जगतसिंहपुर ज़िला प्रशासन ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का उल्लंघन किया है. कमेटी के एक सदस्य आशीष कोठारी के मुताबिक़, राज्य सरकार का यह दावा भी ग़लत है कि यह इलाका जनजातियों एवं अन्य वनवासियों का परंपरागत निवास स्थल नहीं है. कोठारी का मानना है कि राज्य सरकार के इस दावे में कोई दम नहीं है और इसके पक्के सबूत उपलब्ध हैं.

feedback@chauthiduniya.com

डीआरडीओ ने इस तकनीक के अधिकार इस साल जनवरी में फिक्की के समर्थन से फार्मा कंपनी ज्योति लेबोरेटरीज को दे दिए हैं.

जब मिले ग़लत, भ्रामक या अधूरी सूचना

सूचना का अधिकार — जानने का अधिकार जीने का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

पिछले अंकों में हमने आपको द्वितीय अपील के बारे में बताया था. द्वितीय अपील तब करते हैं, जब प्रथम अपील के बाद भी आपको संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है. राज्य सरकार से जुड़े मामलों में यह अपील राज्य सूचना आयोग और केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में यह अपील केंद्रीय सूचना आयोग में की जाती है. हमने आपकी सुविधा के लिए द्वितीय अपील का एक प्रारूप भी प्रकाशित किया था. हमें उम्मीद है कि आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर किया होगा. इससे निश्चय ही फ़ायदा होगा. इस अंक में हम सूचना का अधिकार क़ानून 2005 की धारा 18 के बारे में बात कर रहे हैं. धारा 18 के तहत शिक़ायत दर्ज कराने की व्यवस्था है. एक आवेदक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि किन–किन परिस्थितियों में शिक़ायत दर्ज कराई जा सकती है. लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इंकार करता है अथवा परेशान करता है तो इसकी शिक़ायत सीधे आयोग में की जा सकती है. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने, भ्रामक या ग़लत सूचना देने के ख़िलाफ़ भी शिक़ायत दर्ज कराई जा सकती है. सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के ख़िलाफ़ भी आवेदक आयोग में सीधे शिक़ायत दर्ज करा सकता है. उपरोक्त में से कोई भी स्थिति सामने आने पर आवेदक को प्रथम अपील करने की ज़रूरत नहीं होती. आवेदक चाहे तो सीधे सूचना आयोग में अपनी शिक़ायत दर्ज करा सकता है. शिक़ायत का एक प्रारूप भी हम इसी अंक में प्रकाशित कर रहे हैं. आशा है, ज़रूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे. आप आरटीआई से जुड़ी अपनी किसी भी समस्या या सुझाव के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

शिकायत का प्रारूप

सेवा में,
केंद्रीय/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
पता.....

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत शिकायत

क्रमांक	वांछित सूचनाएं	आवेदक द्वारा भरा जाए
1	आवेदक का नाम और पता	
2	(क) लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता, जिसके विरुद्ध शिकायत है. (ख) आवेदन की तिथि. (ग) लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब की तिथि.	
3	(क) प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता. (ख) प्रथम अपील जमा करने की तिथि. (ग) प्राप्त जवाब की तिथि.	
4	जिन आदेशों के विरुद्ध शिकायत की जानी है, उसका विवरण.	
5	शिकायत का संक्षिप्त विवरण.	
6	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नामंजूर किए जाने की दशा में आवेदन की तिथि और विषय वस्तु का विवरण.	
7	आयोग से निवेदन या राहत.	लोक सूचना अधिकारी को मेरे आवेदन में मांगी गई सूचना बिना किसी शुल्क के तुरंत सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दें. साथ ही लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध धारा 20 (1) के तहत जुर्माना लगाएं और धारा 20 (2) के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश भी करें. आयोग से निवेदन है कि मैं इस मामले की सुनवाई में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहता हूं. अत: मुझे सुनवाई की अग्रिम सूचना अवश्य दें.
8	अन्य कोई सूचना, जो शिकायत निष्पादित करने के लिए आवश्यक हो.	

मैं.....उपरोक्त शिकायत को दिनांक..... को सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त मामले की सुनवाई किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं की गई है अथवा विचाराधीन नहीं है. इस शिकायत में प्रदान की गई सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं.

संलग्नक सूची
1. आवेदन की प्रति.
2. शुल्क भुगतान की रसीद की प्रति.
3. आवेदन पत्र को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद की प्रति.
4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की प्रति.
5. प्रथम अपील की प्रति.
6. प्रथम अपील को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद की प्रति.
7. प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की प्रति.
8. शिकायत की एक प्रति लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को भेजे जाने का प्रमाण.

नाम.....
पता.....
स्थान.....
तिथि.....

नोट : शिकायत को डबल स्पेसिंग लाइन में बनाएं, यानी लाइनों के बीच दोगुनी जगह छोड़ें. शिकायत की एक–एक प्रति लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को भेजें. शिकायत की दो प्रतियां सूचना आयोग में भेजें. साथ ही एक प्रति अपने पास रखें.

ज़रा हट के

दुनिया का सबसे पुराना शहर गुजरात में!

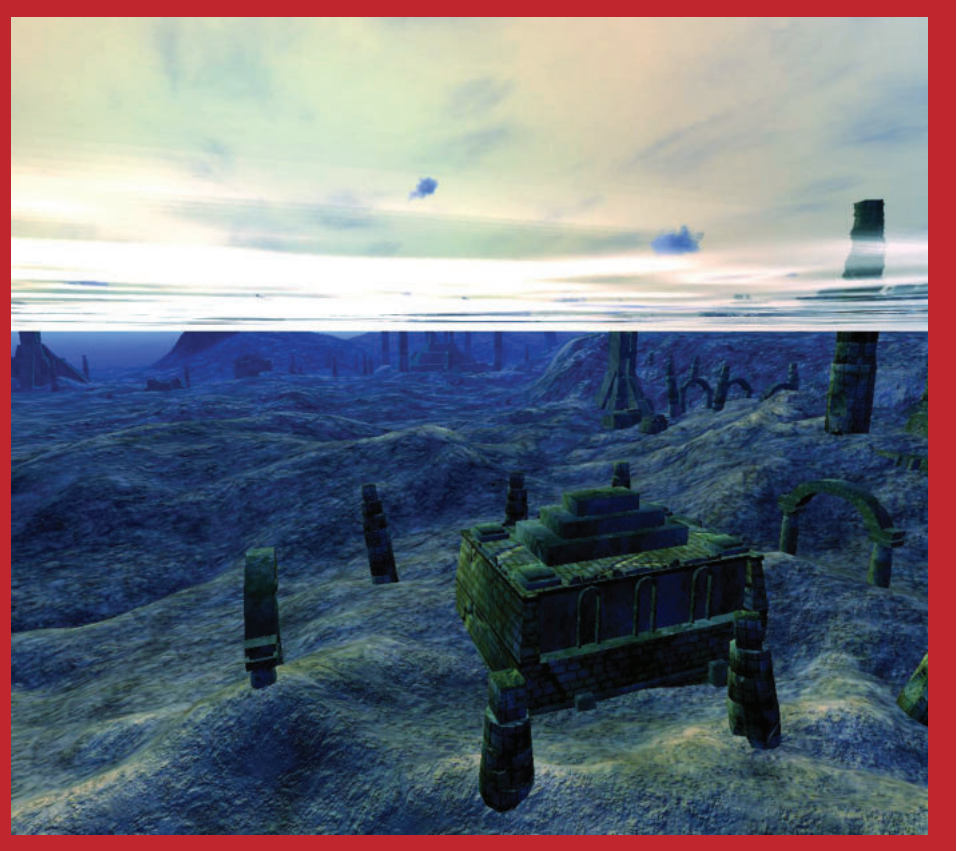

गुजरात के खंभात की खाड़ी में कुछ ऐसे शहरों का पता चला है, जो आठ हज़ार साल पुराने हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक़, वहां नौ हज़ार साल पुरानी चीजें मिली हैं. वैसे समुद्र के नीचे शहरों की कहानी अक्सर सुनाई पड़ती रहती है और उनके साथ शहरी सभ्यता के इतिहास के बारे में नए सिद्धांत भी उभरते हैं. इसी तरह गुजरात में खंभात की खाड़ी में भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों को समुद्र तल से 120 फीट नीचे कुछ संरचनाएं मिली थीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पुरातात्विक अवशेष हैं. उक्त शहर लगभग पांच मील की लंबाई और दो मील की चौड़ाई में फैला हुआ था. कार्बन डेटिंग से पता चला है कि मिट्टी के बर्तनों के अलावा मूर्तियां एवं हड्डियां लगभग साढ़े नौ हज़ार साल पुरानी हैं. अगर वाकई ऐसा है तो यह दुनिया में इंसान और सभ्यताओं की कहानी बदल देगा. अब तक प्राप्त सुमेरी सभ्यता के नगर पांच हज़ार साल पुराने माने जाते हैं.

यह शहर कभी समुद्र के किनारे हुआ करता था. साढ़े चार हज़ार साल पहले आई एक भयानक बाढ़ में यह इलाक़ा समुद्र के नीचे डूब गया. दूसरी ओर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्राकृतिक बनावट है. वे इसकी खोज के लिए अब तक इस्तेमाल की गई सोनार इमेज तकनीक को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं. इन समुद्री भूतत्वविदों का कहना है कि समुद्र की गहराई में वास्तविक खोज के ज़रिए ही इस सिलसिले में कोई ठोस व्याख्या संभव है.

टिश्यू पेपर से मच्छर ग़ायब

मच्छर से हर कोई परेशान है. इस परेशानी से बचने के लिए लोग कई तरह के तरीक़े अपनाते हैं, जैसे मॉस्क्यूटो क्वाइल जलाते हैं और मच्छरदानी का उपयोग करते हैं, फिर भी मच्छर बाज नहीं आते. लेकिन अब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीआरडीओ द्वारा खोजी गई एक रामबाण दवा बाज़ार में आ गई है. यह टिश्यू पेपर की तरह दिखती है. इसे एक बार शरीर पर लगा लेने से मच्छर आपके क़रीब नहीं फटकेंगे.

इस टिश्यू पेपर की क़ीमत केवल तीन रुपये है. मच्छरों से मुक्ति का यह उपाय रक्षा शोध एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने खोजा है. सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना पिछले छह सालों से इसका उपयोग कर रही है. सेना ने इस दवा के निर्माण के लिए दवाओं का मूल स्रोत यानी एक नया मॉलेक्यूल तैयार किया है, जिसका नाम डेथिल पेनिल एसिटामाइड (डीईपीए) रखा गया है. यह मॉलेक्यूल टॉक्सिक यानी जहरीला नहीं होता और इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में भी किया जा सकता है. ग्वालियर स्थित डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस मॉलेक्यूल का विकास किया है. डीआरडीओ ने इस तकनीक के अधिकार इस साल जनवरी में फिक्की के समर्थन से फार्मा कंपनी ज्योति लेबोरेटरीज को दे दिए हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 23 अगस्त–29 अगस्त 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
दिल की बीमारियों के शिकार लोगों के लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद समय अनुकूल रहेगा. पुराने संबंधों की वजह से नए संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है. पारिवारिक–सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी से ख़र्चे बढ़ेंगे. आप मकान या नए वाहन आदि की ख़रीददारी भी कर सकते हैं.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
लंबी दूरी की यात्राओं से परहेज करें, दुर्घटना हो सकती है. खानपान और वाहन चलाते समय सावधानी अपेक्षित है. भाई–बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकता है. किसी ख़ास परिजन से अर्से बाद मुलाकात की संभावना है. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
विद्यार्थियों को अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखने के लिए ज़्यादा प्रयास करने होंगे. इस दौरान होने वाली परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. मित्रों–परिजनों को रकम उधार देनी पड़ सकती है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
नए कार्यों में प्रगति होगी, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है. नौकरीपेशा वर्ग के लिए कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार अपेक्षित है, अन्यथा अनावश्यक परेशानी में पड़ सकते हैं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
भागीदार अथवा अधीनस्थ के साथ बेवजह विवाद हो सकता है. अपने उच्चाधिकारी से भी मत उलझें. अपने एवं परिजनों के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें और चिंता से बचें. अध्यापन, लेखन एवं बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
व्यापारियों के लिए यह समय आगे की योजना बनाने के लिए उचित है. पिता से चल रहा मनमुटाव ख़त्म होगा. किसी योजना में निवेश करने की इच्छा हावी हो सकती है. नए रिश्ते बनेंगे और फ़ायदेमंद भी होंगे. कोई विशेष कार्य संपूर्ण करने में अधिकतर समय व्यतीत होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
लंबी यात्राओं से दूर रहना बेहतर होगा. पति–पत्नी के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद या अलगाव समाप्त होगा. किसी महत्वपूर्ण सौदे में रुकावट आ सकती है. नए रिश्ते बनाने में कामयाबी मिलेगी और किसी पुराने मित्र या दूर के रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
लंबे समय से लटका भवन निर्माण का काम पूरा होगा. निवेश से होने वाली आमदनी आपकी उम्मीदों से कम हो सकती है और लाभ में भी कमी आ सकती है. कार्य स्थान में छोटी–छोटी उलझनों, काम के बढ़ते बोझ और सहकर्मियों के असहयोग से मुश्किलें आ सकती हैं.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा और सामाजिक समारोहों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. सप्ताह के अंत में बुखार, जुकाम और पेट संबंधी बीमारियां सिर उठा सकती हैं. घरेलू एवं अन्य साझीदारी में व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो आप ग़लती कर बैठेंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
वक़्त के साथ आप कई दिक्कतों से बाहर निकल आएंगे. व्यवसायिक यात्राएं मनोनुकूल कही जा सकती है. मानसिक शांति मिलेगी. छोटे से छोटे कार्य के लिए धन का अपव्यय होगा. छोटा–बड़ा कार्य आसानी से निपटाने में सफल होंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
क़ीमती सामान की सुरक्षा पर ध्यान दें, नुक़सान संभव है. कार्यक्षेत्र में नई पहचान के साथ बेहतर उपलब्धि मिलेगी. अपने खाने का खास ख्याल रखें, नहीं तो पेट से जुड़ी किसी दिक्कत से गुजर सकते हैं. व्यापार में अनुकूलता बनी रहेगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
समाज में सम्मान होगा. पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा. पूंजी निवेश सावधानी से करें, अन्यथा हानि हो सकती है. शत्रु पक्ष बदनाम करने की साजिश रच सकता है, सूझबूझ से चलें. आवेश में ऐसा निर्णय न लें, जो परेशानी का कारण बने.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ज़रदारी अमेरिका की इच्छाओं से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं. आतंकियों के ख़िलाफ़ चल रही लड़ाई को समर्थन देकर उन्होंने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है,

ज़रदारी के लिए रास्ता आसान नहीं है

आसिफ अली ज़रदारी

डी आर आहूजा

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी इन दिनों अपने विरोधियों के निशाने पर हैं, जो उन्हें किसी तरह सत्ता से बाहर करने की साज़िश रच रहे हैं. देर से ही सही, मगर सत्ता पर अपनी पकड़ को मज़बूत करने के लिए ज़रदारी भी तमाम कोशिशें कर रहे हैं. उन्हें अब यह एहसास हो चुका है कि वह ज़मीनी हक़ीक़त से दूर हो गए हैं. इसलिए आजकल वह हर वह काम कर रहे हैं, जो एक राष्ट्रपति को करना चाहिए, मसलन देश भर में यात्राएं, सभाएं, आम लोगों से मिलना-जुलना आदि. सार्वजनिक तौर पर स्वयं को देश का मुखिया जताने के लिए वह हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, जब यही ज़रदारी सिवाय विदेश यात्राओं के महीनों तक राष्ट्रपति भवन से बाहर नहीं निकलते थे.

हालांकि ताज़ा संकेतों से ऐसा लग रहा है कि ज़रदारी सत्ता में तो बने रहेंगे, लेकिन सत्ता पर उनकी पकड़ मज़बूत नहीं होगी. आम जनता में उनकी लोकप्रियता इतनी कम हो चुकी है कि देश के सामने मौजूद समस्याओं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा और सबसे बढ़कर आतंकवाद का मुद्दा प्रमुख है, से उन्हें दूर रहना होगा. उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं मिलेगी. सत्ता के शीर्ष पर कमज़ोरी का यह मुद्दा अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान में चल रहे संघर्ष के मद्देनज़र नई रणनीतियां बनाने के लिए वह पाकिस्तान की मदद पर निर्भर है. पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में स्थित पहाड़ी क्षेत्र आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुका है. ओबामा प्रशासन इस क्षेत्र से आतंकवादियों को भगाने के लिए पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाता रहा है. इसी सिलसिले में अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स हाल के दिनों में पाकिस्तान की यात्रा पर आ चुके हैं. अमेरिकी अधिकारी पाकिस्तान के शक्तिशाली सैन्य तंत्र पर काफी भरोसा करते हैं. अपने भारत दौरे के दौरान गेट्स ने इस बात की ओर इशारा किया था कि 26/11 जैसी घटना दोबारा हुई तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि अलक़ायदा और लश्करे तैयबा जैसे आतंकी संगठन भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन गेट्स ने यह खुलासा नहीं किया कि जिहादी संगठन ऐसा क्यों चाहते हैं या कहीं कोई दूसरी ताक़त उन्हें ऐसा करने के लिए उकसा तो नहीं रही है.

ज़रदारी अमेरिका की इच्छाओं से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं. आतंकियों के ख़िलाफ़ चल रही लड़ाई को समर्थन देकर उन्होंने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है, लेकिन समस्या यह है कि वह ख़ुद इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि चाहकर भी अमेरिकी हितों की रक्षा नहीं कर सकते. ज़रदारी ने आम लोगों से मिलने के अपने अभियान की शुरुआत पिछले साल दिसंबर के आख़िरी दिनों में की थी. वह सबसे पहले सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एवं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के दौरे पर गए. इस अभियान की मदद से वह अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, ताकि अपनी खोई राजनीतिक ज़मीन हासिल कर सकें. इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ है और ज़रदारी से जुड़ी ख़बरें अख़बारों की सुर्ख़ियां बनने लगी हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ज़रदारी सेना और न्यायपालिका से भी डरे हुए हैं. उन्हें लगता है कि देश की उक्त दो प्रमुख संस्थाएं उन्हें उनके पद से कभी भी बेदख़ल कर सकती हैं. लेकिन जनसंपर्क कार्यक्रम से मिली ताक़त के सहारे वह फिर से संघर्ष के लिए कमर कस रहे हैं. देश की सेना, जो पाकिस्तान के 62 साल के इतिहास में क़रीब-क़रीब आधे समय तक सत्ता पर क़ाबिज़ रही है, के साथ ज़रदारी के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं.

सितंबर, 2008 में जब ज़रदारी ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने भारत के साथ दोस्ताना रिश्तों पर जोर दिया था. सेना को उनका यह रुख़ पसंद नहीं आया, क्योंकि वह परंपरागत रूप से भारत के ख़िलाफ़ रही है. ख़ुफ़िया विभाग को सरकार के नियंत्रण में लाने की बात कहकर उन्होंने सेना के गुस्से को और तेज़ कर दिया. हालांकि इसके बाद उन्होंने अपना रवैया बदल लिया और कई बार खुले तौर पर सेना की प्रशंसा भी कर चुके हैं. आण्विक हथियारों को प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी के नियंत्रण में देकर भी उन्होंने सेना के संदेह को दूर करने की कोशिश की. सेना ज़रदारी के मुक़ाबले गिलानी को ज़्यादा पसंद करती है, उसे गिलानी पर ज़्यादा भरोसा है. सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी की सेवानिवृत्ति का मुद्दा ऐसा था, जिस पर सेना के साथ उनका टकराव हो सकता था, क्योंकि इस पर फ़ैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में ही था, लेकिन कयानी को तीन साल का सेवा विस्तार मिलने के बाद वह इससे भी बच निकलने में कामयाब रहे. विश्लेषकों की राय में मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी निकट भविष्य में ज़रदारी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं. मानवाधिकारों और भ्रष्टाचार के मामलों को उठाकर चौधरी देश में काफी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं. आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में ज़रदारी और चौधरी आमने-सामने हो सकते हैं. पाकिस्तान का इतिहास सैन्य तख्तापलट की घटनाओं से भरा पड़ा है. सरकार के धुर विरोधी भी आज यही दुआएं कर रहे हैं कि इस इतिहास को दोहराया न जाए.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

ज़रदारी पर जूता

अपने देश में विरोध झेल रहे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी को विरोधियों ने विदेश में भी नहीं बख्शा. अगस्त के पहले सप्ताह में ब्रिटेन के दौरे पर गए ज़रदारी 7 अगस्त को बर्मिंघम में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने दोनों जूते उनकी ओर फेंक दिए. हालांकि जूते ज़रदारी तक नहीं पहुंचे, लेकिन इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह कितने अलोकप्रिय हो चुके हैं. ग़ौरतलब है कि ज़रदारी जब ब्रिटेन के दौरे पर गए थे तो पाकिस्तान के कई हिस्से भीषण बाढ़ की चपेट में थे. 22 जुलाई को शुरू हुई बाढ़ की इस विभीषिका ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों के बाद पंजाब और सिंध को भी अपनी चपेट में ले लिया. बाढ़ की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे पिछले कुछ सालों की सबसे भीषण मानवीय त्रासदी घोषित कर दिया. इसी बीच ज़रदारी विदेश यात्रा पर निकल गए. पहले से ही अलोकप्रिय ज़रदारी के इस क़दम की देश-विदेश में काफी आलोचना हुई. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जूता फेंकने की यह घटना भी इसी से प्रेरित थी. हालांकि विरोधियों के जूतों का शिकार होने वाले ज़रदारी पहले राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं. इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भी ऐसी घटना के शिकार हो चुके हैं.

e देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार-राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

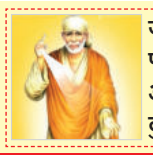

जीवन कई ख़ुशियों से वंचित है. पैसा है, शोहरत है तो परिवार नहीं, सेहत नहीं. जीवन का कोई न कोई आयाम तो खाली है, अधूरा है और इस एक कमी का दुःख इतना है कि जो खुशियां हैं, वे भी पूरी नहीं पड़तीं.

जीवन के सुखों को कैसे प्राप्त करें

आपके जीवन का एक सच और समानांतर पक्ष देते हैं. सोचें आपने अपने बच्चे को कंप्यूटर दिया, इससे काम लेने को आपने सिखाया कि कंप्यूटर से काम कैसे लेना है, फिर आप विदेश चले गए. बच्चा कंप्यूटर से खेलता रहा, धीरे धीरे हर बात के लिए कंप्यूटर पर निर्भर हो गया और धीरे धीरे कंप्यूटर इस पर हावी हो गया अब कंप्यूटर ही इसका सच हो गया.

आज के दौर में सुखी किसे कहेंगे? वह, जो जीवन के सारे सुख भोग रहा है? जीवन के सुख में क्या शामिल है? अच्छी नौकरी, सुखी परिवार, अपना घर, अच्छी गाड़ी, बैंक में पैसा, समाज में प्रतिष्ठा. यह सब कुछ होने के बाद भी क्या हम सुखी हो पाते हैं? नहीं, क्योंकि मन अशांत है और सबसे बड़ी बात आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में यह सब एक सपना बनकर रह गया है. जीवन कई ख़ुशियों से वंचित है. पैसा है, शोहरत है तो परिवार नहीं, सेहत नहीं. जीवन का कोई न कोई आयाम तो खाली है, अधूरा है और इस एक कमी का दुःख इतना है कि जो खुशियां हैं, वे भी पूरी नहीं पड़तीं. तो फिर क्या करें, कैसे ख़ुश रहें, कहां तलाशें ख़ुशी? यही हमारी ग़लती है. ज़रा किसी ख़ुश व्यक्ति को देखें. खुश तो आज कोई है ही नहीं. चलिए, संतुष्ट व्यक्ति को देखें. अब संतुष्टि का मतलब यह नहीं कि हालात से समझौता किया व्यक्ति. संतुष्टता का मतलब अपनी स्थिति को स्वीकारते हुए अपने आप में संतुष्ट व्यक्ति, शिक़ायतों से भरा नहीं. इस संतुष्ट व्यक्ति को देखें, वह हर हाल में खुश होगा.

बिना शिक़ायत के व्यक्ति कहीं अंदर अपने आप से जुड़ा होगा, प्रेम से भरा होगा. जो संतुष्ट होगा, वह देने में नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि उसे लेने की आवश्यकता नहीं है. पर कभी सोचा कि ऐसा कैसे संभव है? आपके जीवन का एक सच और समानांतर पक्ष देते हैं. सोचें, आपने अपने बच्चे को कंप्यूटर दिया, उसे सिखाया कि कंप्यूटर से काम कैसे लेना है. फिर आप विदेश चले गए. बच्चा कंप्यूटर से खेलता रहा, धीरे-धीरे वह हर बात के लिए कंप्यूटर पर निर्भर हो गया और कंप्यूटर उस पर हावी हो गया. अब कंप्यूटर ही उसका सच हो गया. समझें, कंप्यूटर एक मशीन है, जो अक्लमंद है, बहुत तेज़ी से काम करती है, लेकिन यह चैतन्य नहीं है, यह सोच नहीं सकती. लेकिन बच्चे ने सिर्फ़ कंप्यूटर को सच मान उससे काम लेना बंद कर दिया और वह उसका कहा मानने लगा तो क्या हुआ. ऐसे ही हमारे साथ हुआ. परमात्मा के हम बच्चे, हमारे पिता ने सर्वशक्तियों से भरपूर हमारे इशारों पर नाचती यह प्रकृति तोहफे के रूप में दी. समझें, कंप्यूटर की ही तरह प्रकृति ऊर्जामय है, परिवर्तनशील है, नियमों की पाबंद है, लेकिन चैतन्य नहीं, सोच-समझ नहीं सकती. जब तक प्रकृति हमारे अधीन थी, तब तक वह हर विचार को पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगाती थी, लेकिन जब हमने उसके सिस्टम के नियमों का उल्लंघन करना शुरू किया, तभी से उसने काम करना बंद कर दिया. जब कंप्यूटर सिस्टम पर ज्यादा भार डाला, उसकी प्रणाली में छेड़छाड़ की तो वह कुछ परिणाम देने लगा. इसी तरह प्रकृति ने भी अपने तंत्र में आती इन ख़राबियों को दर्शाना शुरू कर दिया है.

ज़रूरत इस बात की है कि पहले अपने आप को समझें और यह जानें कि इससे हमारी प्राप्ति क्या है. कोई इच्छा करके दुःखी होने और इंतज़ार करने में कि यह कब होगा, ख़ुशी नहीं मिलेगी. बल्कि ख़ुशी इस एहसास में है कि हम किसकी संतान हैं, कौन हमें फिर से हमारी शक्ति याद दिलाने आया है. फिर अपनी शक्ति-ऊर्जा के प्रति चैतन्य होकर मांगो, जो चाहिए. यह प्रकृति आपको देने के लिए ही है. ज़रूरत है इसके मिलने का वक़्त तय करें. आप पाएंगे कि अगर संपूर्ण विश्वास यानी श्रद्धा है तो फिर सब कुछ आपके सामने होगा, मसलन अच्छा जीवनसाथी, अच्छी नौकरी, गाड़ी, बंगला, शोहरत, पावर और पैसा. कुछ भी मांग लो, अथाह समंदर है. इसके बाद पूर्ण विश्वास के साथ जिएं. एक भी विचार शंका का न आए. जब समय मिले, देखें अपने आपको जिस रूप में देखना चाहें. न इंतज़ार करें, न घबराएं, न परेशान हों, बल्कि प्रेम से जीवन जिएं. यह याद रहे कि जो आपको चाहिए, वह मिलता ही है. आप पाएंगे एक दिन, वह चाहत पूरी होगी, सारे सपने पूरे होंगे. बस श्रद्धा और सबूरी का पाठ याद रखें. मालिक का हाथ सिर पर है. फिर लें वह हर सुख, जिसका अधिकार परमात्मा ने आपको दिया है.

ओम् साई राम...

अगर आप फाउंडेशन से संपर्क करना चाहते है तो 9999313918 पर एसएमएस करें.

ऑसिम खेत्रपाल
feedback@chauthiduniya.com

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj
Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

AUM Infrastructure & Developers
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

मैं कौन हूं

जब भी अपने बारे में सोचा तो ख़ुद को किसी न किसी किरदार में देखा. किसी ने पूछा - आप कौन हो? जवाब में कई पहचानें थीं. मेरा नाम, रुतबा, मेरा रिश्ता या मेरा लिंग- स्त्री या पुरुष. कभी मैं पिता हूं, कभी मैं किसी कंपनी का चेयरमैन हूं. कभी बेटा हूं तो कभी सिर्फ़ नाम. इनके अलावा तो कोई और पहचान है ही नहीं. इतनी सारी पहचानों में मेरी असली पहचान क्या है? कौन हूं मैं? स्वयं के नज़दीक आकर सोचूं तो मेरा तो सिर्फ़ शरीर है, लेकिन इसे मेरा कहने वाला कौन है? जैसे मेरा घर, परिवार, कपड़े, कुर्सी, फोन वैसे ही मेरा शरीर. यह सब मेरा है लेकिन मैं कौन हूं? मेरा कहने वाला कौन है और कहां है. इस शरीर के अंदर या बाहर. कई सारे सवाल, जवाब कोई नहीं. जब भी गुरुओं से पूछा, किताबों को पढ़ा, लगा कि इस मैं को पहचानना बहुत कठिन है, लेकिन जब जाना कि इस पूरे शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं मैं, चेतन्यता हूं, वो जागृत ऊर्जा हूं, तो समझा की मेरी असली पहचान क्या है. मैं वो ऊर्जा हूं जो तीन रूप में काम करती है- मन, बुद्धि और संस्कार. मैं मन हूं. नए विचार उत्पन्न करता हूं. बुद्धि हूं, तौलता हूं कि क्या सही है और क्या ग़लत. फिर निश्चय करता हूं कि क्या करूं. फिर अपने स्थूल दिमाग़ को कर्म करने का संदेश देता हूं. दिमाग़ शरीर के इस भाग को संदेश देगा कि कर्म करो और वह अपना कर्म करेगा. इस कर्म की याद मुझमें हमेशा रहेगी लेकिन मेरे दिमाग़ में नहीं बल्कि मेरे अंदर यानी मुझ में. ये यादें जो धीरे धीरे आदत बनती हैं मेरे संस्कार बनते जाते हैं. इसके वश में आकर मैं कई विचारों को उत्पन्न करता हूं. मेरे द्वारा किया गया हर कर्म संस्कारों और स्वभाव के रुप में मेरे अंदर संरक्षित रहता है.

इस तरह से मैं अगर स्वयं के अंदर झांकू तो देखता हूं कि मेरी असली पहचान तो वो शाश्वत चैतन्य ऊर्जा और आत्मा है. जो न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है बल्कि मन-बुद्धि-संस्कार के रूप में सदा जागृत है. आज तक मैंने जितने भी जन्म लिए, उसकी हर याद चेतन और अचेतन अवस्था में हमारे साथ है. लेकिन यह सब यादें अंदर दबी हुई हैं, तभी तो जैसे ही मन शांत होता है जन्मों की बहुत सी बीती बातें याद आ जाती हैं. चाहें तो पिछली जन्म की भी बातें याद कर लें. जब सम्मोहन विधा के द्वारा अवचेतन दिमाग को जागृत किया जाता है.

अब आते हैं आत्मा पर जो हमेशा अलग-अलग किरदारों में दिखाई देती है. अगर ख़ुद को देखूं तो पिता के रूप में मैं ही मन, बुद्धि, संस्कार यानी विचार, निर्णय और यादों के दम पर ही इस किरदार को निभाता हूं. अब तक की हर पहचान मैं यानी आत्मा है. सिर्फ़ मैं इसके प्रति अनभिज्ञ हूं. इसीलिए इन किरदारों को ही सच मान दर्द या ख़ुशी का अनुभव करता हूं. अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो हर वक़्त विचार उत्पन्न होते हैं. अगर अपका बॉस आपसे कुछ आकर कह देता है तो मन में विचार आएगा कि इसने मेरी बेइज़्ज़ती की, वो होते कौन हैं ऐसा कहने वाले, क्या मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं, मैं कब तक यह सब बर्दाश्त करूंगा, मैं इस जगह नहीं रह सकता. अगर विचारों का यह सिलसिला अधिक दिनों तक चला तो आवेश में या इन विचारों के बोझ तले दबकर नौकरी छोड़ने का निर्णय लेंगे और फिर इस्तीफ़ा देने का काम करेंगे और इसकी याद संस्कार रूप में मेरी आत्मा में रहेगी. नतीजतन आप को दूसरी नौकरी तलाशनी होगी. कुछ निराशा भी होगी, मनमाफिक नौकरी मिलने में वक़्त लग सकता है, दूसरी तरफ़ नौकरी छोड़ने के मेरे इस निर्णय से घर परिवार में भी हलचल और परेशानी हो सकती है. नई नौकरी में एडजस्ट करने में समय लगेगा और अनुभव बताता है कि ख़ुदा न ख़ास्ता यहां भी अगर बॉस से अनबन रही तो वही सिलसिला फिर चलेगा. जैसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए, लगेगा फिर वही हो रहा है. चूंकि इस्तीफ़े की याद ताज़ा है. संस्कार बन रहा है, यहां भी इस्तीफ़ा देने में हिचकिचाएंगे नहीं, संस्कार गहरा हो जाएगा. यहीं पर अगर नौकरी को एक रोल समझें तो पाएंगे कि यह डांट इस रोल को पड़ रही थी मुझे नहीं. हो सकता है बॉस का मूड ख़राब हो या शायद इस रोल को मैं सही से निभा नहीं पा रहा हूं. जब ग़लती मेरी यानी शाश्वत चैतन्य शक्ति की नहीं बल्कि इस रोल की होगी तो दर्द उत्पन्न नहीं होगा. दर्द कम होगा तो नाराज़गी भी कम होगी. फिर हम सही तरह से सोच पाएंगे. फिर शायद नौकरी छूटे ना और धीरे धीरे न सिर्फ़ बॉस बल्कि हर एक को संभालना आ जाएगा. सिर्फ़ एक चैतन्यता अपनी पहचान की और एक अलग भाग्य. निर्णय हमें लेना है. ओम साईं राम

feedback@chauthiduniya.com

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रुप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाज़ा, सन्तनगर, ईस्ट अफ़ कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली-110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

पहली बार
शिरडी साई
बाबा फीचर
फिल्म
अब कॉमिक्स
के रूप में

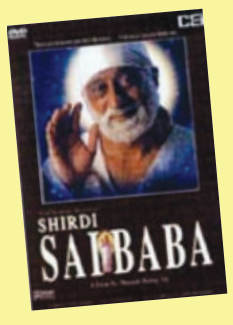

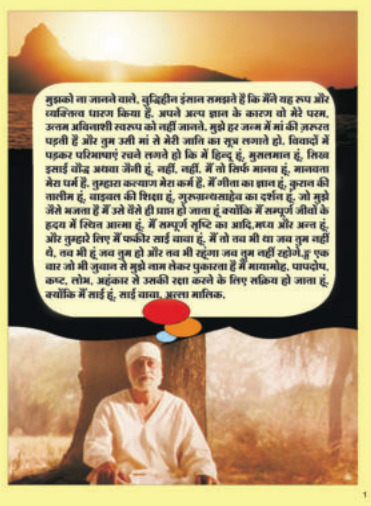

ज्ञानोदय

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए

स्व. मालती कपूर

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है.

प्रेमचंद

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं.

स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

अब आनंद भारती मानसी को अपनी रोज की ज़िंदगी में याद नहीं करते थे. इतना वक़्त भी नहीं था उनके पास.

कारण कवन नाथ मोहे मारा

अनंत विजय

नया ज्ञानोदय के अगस्त 2010 अंक में छपे मेरे इंटरव्यू पर हुई प्रतिक्रियाओं से एक बात स्पष्ट हो गई कि मैंने अपनी लापरवाही से एक गंभीर विमर्श का हेतु बन सकने का मौक़ा गंवा दिया. मैंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जिनसे बचा जा सकता था. मुझे जैसे ही यह एहसास हुआ कि मेरी भाषा से हिंदी की बहुत सी लेखिकाओं को कष्ट हुआ है, मैंने अपनी ग़लती का एहसास किया और बिना शर्त माफ़ी मांग ली. मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी असावधानी से बहुत से ऐसे लोग आहत हुए, जो मेरे वर्षों पुराने मित्र रहे हैं, इनमें बड़ी संख्या में लेखिकाएं हैं, पर मेरे मन में उनके लिए सम्मान भी बढ़ा है कि मित्रता की परवाह किए बग़ैर उन्होंने मेरी मजम्मत की. हालांकि कुछ लोग जो इस मामले को अन्य कारणों से ज़िंदा रखना चाहते हैं, इंटरव्यू में उठाए गए मुद्दों पर बहस न करके अभी भी उन शब्दों के वाक्य जाल में उलझे हुए हैं, जिन पर मैं ख़ुद खेद प्रकट कर माफ़ी मांग चुका हूं. मैं मानता हूं कि इन लोगों की उपेक्षा कर अब मैं मुद्दों पर बहस की अपेक्षा कर सकता हूं. यह कहना है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति विभूति नारायण राय का.

दरअसल जिस बात पर विभूति अपने साथी लेखकों और हिंदी समाज से माफ़ी मांग रहे हैं, वह पूरा विवाद विभूति के ही एक साक्षात्कार से उठा. नया ज्ञानोदय के सुपर बेवफ़ाई विशेषांक में विभूति नारायण राय का एक लंबा इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है, जिसमें एक सवाल के जवाब में विभूति कहते हैं, पिछले वर्षों में हमारे यहां जो स्त्री विमर्श हुआ है, वह मुख्य रूप से शरीर केंद्रित है. यह भी कह सकते हैं कि वह विमर्श बेवफाई के विराट उत्सव की तरह है. लेखिकाओं में होड़ लगी है यह साबित करने के लिए कि उनसे बड़ी छिनाल कोई नहीं है. मुझे लगता है कि इधर प्रकाशित एक बहु प्रमोटेड और ओवर रेटेड लेखिका की आत्मकथा का शीर्षक कितने बिस्तरों पर कितनी बार हो सकता है. इस इंटरव्यू के प्रकाशित होने के बाद हिंदी के लेखकों के बीच इस पर विमर्श शुरू हो गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका विरोध तो तब शुरू हुआ, जब अचानक एक दिन दिल्ली से प्रकाशित एक अंग्रेजी दैनिक ने इस ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित कर विवाद खड़ा कर दिया.

अंग्रेजी अख़बार के संवाददाता ने छिनाल शब्द का अंग्रेजी अनुवाद प्रोस्टीट्यूट कर दिया, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया. दरअसल छिनाल या छिनार एक आंचलिक शब्द है, जिसका प्रयोग बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाक़ों में किया जाता है. छिनाल उन स्त्रियों को कहा जाता है, जो कुलटा होती हैं या फिर स्त्रियोचित मर्यादा को भंग कर अपनी मर्ज़ी से कई पुरुषों से संबंध बनाती हैं, लेकिन वे किसी भी हाल में वेश्या नहीं होतीं. महिला लेखिकाओं के लिए कहा गया यह शब्द बिल्कुल आपत्तिजनक है, लेकिन वेश्या जितना अपमानजनक नहीं है. यह गाली है और किसी भी लेखक को अपनी बिरादरी की महिलाओं के लिए इस शब्द के प्रयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती है. जैसा कि ऊपर संकेत दिया जा चुका है कि यह इंटरव्यू लगभग हफ्ते भर से छपकर विवादित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हिंदी सत्ता की भाषा नहीं है, सत्ता की भाषा तो अंग्रेजी है. अंग्रेजी अख़बार के ग़ैर ज़िम्मेदाराना अनुवाद ने आग में घी का काम किया और विरोध की चिंगारी को भड़का दिया. लेखिकाओं का जितना अपमान विभूति नारायण राय ने किया, उससे ज़्यादा बड़ा अपमान तो अंग्रेजी के वे अख़बार कर रहे हैं, जो लगातार लेखिकाओं को वेश्या बता रहे हैं. न्यूज़ चैनलों को भी इस मसालेदार ख़बर में संभावना दिखी और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में उन्होंने छिनाल और वेश्या के अंतर को मिटा दिया. किसी ने भी यह जांचने–परखने की कोशिश नहीं की कि दोनों में क्या अंतर है. मीडिया में इसके उछलने के बाद विभूति नारायण राय पर चौतरफ़ा हमला शुरू हो गया. हिंदी के लेखकों के अलावा कई महिला संगठनों ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति को लेखिकाओं के ख़िलाफ़ इस अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कठघरे में खड़ा किया और उनके इस्तीफ़े एवं बर्ख़ास्तगी की मांग होने लगी. मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल और राष्ट्रीय महिला आयोग तक भी यह मामला पहुंच गया. लगभग मृतप्राय: लेखक संगठनों में भी जान आ गई और उन्होंने भी विभूति नारायण राय के ख़िलाफ़ एक निंदा बयान जारी कर दिया. चौतरफ़ा घिरे विभूति नारायण राय को मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने तलब किया और उनके यहां से निकल कर राय ने बिना शर्त लिखित माफ़ी मांग ली. फिर अख़बार में लेख लिखकर भी माफ़ी मांगी.

विभूति के विरोध के अलावा लेखकों ने नया ज्ञानोदय और उसके संपादक के ख़िलाफ़ भी मोर्चा खोला. ज्ञानोदय छापने वाली संस्था भारतीय ज्ञानपीठ के दफ्तर पर प्रदर्शन भी किया. विरोध बढ़ता देखकर नया ज्ञानोदय के संपादक रवींद्र कालिया ने इसे संपादकीय भूल मानते हुए खेद प्रकट किया और नया ज्ञानोदय का उक्त अंक बाज़ार से वापस मंगा कर विवादास्पद शब्द को हटाकर पत्रिका को फिर से छापने का वायदा किया. बावजूद इसके लेखकों का एक वर्ग इन दोनों को फांसी पर लटकाने के लिए आमादा है. इनकी मांग है कि विभूति नारायण राय और कालिया को उनके पद से बर्ख़ास्त किया जाए. इसके लिए बाक़ायदा एक मोर्चे का गठन भी किया गया है, लेकिन माफ़ी मांग लेने के बाद विरोध जारी रखने का औचित्य समझ में नहीं आता. विरोध पर डटे रहने के कुछ साहित्येत्तर कारण हो सकते हैं–या तो विभूति से व्यक्तिगत खुन्नस, कालिया से नाराज़गी या फिर सत्ता प्रतिष्ठान के ख़िलाफ़ गुस्से का दिखावा. किसी भी साहित्यिक मुद्दे पर लेखकों की इतनी सक्रियता चौंकाने वाली है.

कुछ दिनों पहले हिंदी के ही एक अन्य लेखक भगवान दास मोरवाल के उपन्यास रेत के ख़िलाफ़ जब गिहार समाज के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले एक संगठन भारतीय आदिवासी गिहार विकास समिति ने उत्तर प्रदेश के छिबरामऊ की अदालत में मुक़दमा दर्ज कराया तो कहीं से कोई विरोध की आवाज़ तो दूर, मोरवाल के समर्थन में किसी लेखक ने बयान तक नहीं दिया. लेखक संगठन तक कुंभकर्णी नींद सोते रहे. आज भी मोरवाल अकेले उस लड़ाई को लड़ रहे हैं. जमानत लेने से लेकर तमाम अदालती झंझटों से अकेले निबट रहे हैं. तसलीमा नसरीन को जब पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने कोलकाता से निकाला तो बयानबाज़ी की रस्म अदायगी की गई. कहीं भी धरना–प्रदर्शन तो दूर की बात, कोई हस्ताक्षर अभियान तक नहीं चला. हिंदी के एक स्वनामधन्य आलोचक, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, को जब एक दलित छात्रा के यौन शोषण के आरोप में विश्वविद्यालय ने हटा दिया, तब भी उनका विरोध किसी लेखक या लेखक संगठन ने नहीं किया.

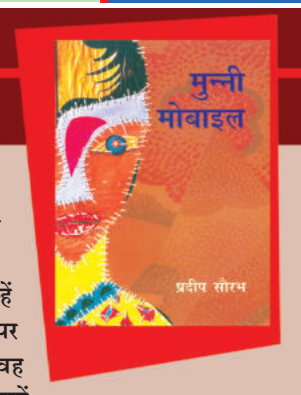

दरअसल हिंदी साहित्य में विभूति नारायण राय और रवींद्र कालिया के खेद प्रकट करने के बाद जो विरोध हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ दूसरे कारण हैं, जो कम से कम साहित्यिक तो नहीं हैं. अब विशाल हिंदी समाज को तय करना है कि यह विरोध कितना जायज़ है और किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

प्रदीप सौरभ

ट्रेन धीरे–धीरे खिसक रही थी. स्टेशन ओझल हो रहा था, पर आनंद भारती अभी इलाहाबाद को छोड़ नहीं पाए थे. वह सोच रहे थे कि इलाहाबाद में शिवानी के साथ कुछ महीने रहने के बाद नौकरी के लिए आनंद दिल्ली आ गए थे. शिवानी के साथ एक ख़ूबसूरत गृहस्थी का सपना संजोए आनंद भारती ने अच्छी नौकरी पा ली थी. इस बीच उनकी बिटिया ने जन्म लिया और आनंद को लगा था कि अब जीवन में स्थायित्व आ गया है. अब आनंद भारती मानसी को अपनी रोज की ज़िंदगी में याद नहीं करते थे. इतना वक़्त भी नहीं था उनके पास. बस, मां–पापा से कभीकभार मानसी की ख़बर मिल जाती तो एक पल के लिए मन बेचैन हो उठता और दूसरे ही पल वह काम में मशगूल हो जाते. बिटिया के पहले जन्मदिन के आसपास उनके रिसर्च गाइड के लंबी बीमारी के पश्चात हुए निधन का समाचार उन्हें मानसी के खत ने दिया था. यों यह ख़बर उन्हें पहले से पता चल चुकी थी, पर कई महीनों बाद मानसी का खत पाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने मानसी को लिखा भी था कि अपनी बिटिया के पहले जन्म दिवस पर वह उसे दिल्ली बुलाना चाहते हैं. मां–पापा दिल्ली आ रहे हैं, यदि वह भी साथ आई तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. पर मानसी का आना संभव न था, वह नहीं आई. उनके दिल्ली निवास पर तो कभी नहीं. हालांकि शिवानी की भी इच्छा थी कि वह कभी दिल्ली उनके पास ज़रूर आए, पर मानसी शायद कहीं पीछे छूट गई थी. आनंद भारती आगे निकलते जा रहे थे. तेजी से. पीछे की ओर देखने का वक़्त उनके पास नहीं था. न ही ज़रूरत. फिर भी वह हमेशा ऐसी कामना

अवश्य रखते कि मानसी हर पल ख़ुश रह सके...हमेशा...हमेशा. वह उसे ख़ुश देखना चाहते थे. उन्हें कहीं भीतर यह बात कचोटती कि वह अपनी मित्र के साथ शायद सगापन नहीं निभा पाए, जिसे वह निभाना चाहते थे या जिसे उन्हें निभाना चाहिए था. आनंद की आंखें फिर से नम होने को आ गई थीं...

पूरे दो वर्ष बाद मानसी की शादी का कार्ड उन्हें मिला था. वह अपना हर ज़रूरी काम छोड़कर शादी पर पहुंचे थे. मानसी को पारिवारिक बंधन से बंधा देख वह बहुत संतुष्ट थे. अपनी सगी मित्र की ख़ुशियां उन्हें अच्छी लगी थीं.

कुछ साल लगे...इस सगे रिश्ते ने कई उतार–चढ़ाव देखे. पर मौन साहचर्य का यह रिश्ता कहीं न कहीं बना हुआ है. आज भी. एक दूसरे के भीतर. इस रूहानी रिश्ते को कोई जो नाम देना चाहे दे, पर जीवन का एक सच यह भी है.

सुबह ट्रेन जब गाज़ियाबाद पहुंची तो आनंद भारती में ताज़गी नहीं थी. स्मृतियों के बोझ से वह दबे हुए थे. टैक्सी लेकर वह घर पहुंचे. फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो चकित थे. मुन्नी को उन्होंने बता दिया था कि वह सुबह लौटेंगे. घर लखदक चमक रहा था. पेड़–पौधों की हरियाली बरक़रार थी. बेड सलीके से लगा हुआ था. सब कुछ चुस्त–दुरुस्त.

थोड़ी देर बाद मुन्नी भी पहुंच गई थी. उसने चाय बनाई. मुन्नी तिरछी नज़रों से आनंद भारती की ओर देख रही थी. शायद वह सोच रही थी कि घर को अच्छी तरह से रखने के लिए वह उसे शाबाशी देंगे. आनंद भारती ने ऐसा ही किया, पीछे से कोई तकलीफ तो नहीं हुई, उन्होंने मुन्नी से पूछा.

अगले अंक में जारी...

बहिष्कार ने बदली लद्दाख की फ़िज़ा

योगी सिकंद

लेह से कुछ ही दूर सिंधु नदी के दूसरी ओर चुशोट गांव है, जो लेह ज़िले का सबसे बड़ा गांव माना जाता है. चुशोट में ज़्यादातर लोग बाल्टी शिया समुदाय से हैं. चुशोट में शियाओं का एक सदियों पुराना इमामबाड़ा है, जो बारह शिया इमामों की याद में बनाया गया है. हाल के दिनों में इसका ईरानी वास्तुकला के अनुरूप जीर्णोद्धार किया गया है, फिर भी इसे देखने से यह पता चलता है कि यह लद्दाख़ी स्टाइल से बनी थी. कमरे में बने खंभों पर पारसी स्टाइल की कालीनें सजी हैं, काले झंडों पर अरबी भाषा में शब्द उत्कीर्ण हैं और दीवारों पर अयातुल्लाह खुमैनी और अन्य ईरानी धार्मिक नेताओं की तस्वीरें लगी हैं. एक पगड़ीधारी शिया धर्मगुरु पूरे जोश के साथ गांव वालों की भीड़ को संबोधित कर रहा है. आज पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन का जन्मदिन है, जिन्हें शहीद होना पड़ा था. उनकी याद में मजलिस लगाई गई है और गांववासियों की भीड़ नीचे बैठकर बड़े भाव के साथ उनके भाषण को सुन रही है. धर्मगुरु अपने भाषण में इमाम की बहादुरी और उनके हत्यारों की दरिंदगी को तब तक दोहराते हैं, जब तक कि भीड़ ज़ोर–ज़ोर से रोने न लगे. मजलिस दो घंटे से ज़्यादा चलती है और फिर सामुदायिक भोज शुरू होता है.

भीड़ इमामबाड़े के बाहर की ओर रुख़ करती है और सीढ़ियों पर मेरी मुलाकात बाल्टी समुदाय के हसन से होती है, जो कॉलेज में पढ़ता है. हम घूमते हुए सिंधु की ओर चले जाते हैं और धूप में बालू के एक टीले पर बैठ जाते हैं. मैं उससे इमामबाड़े का इतिहास पूछता हूं. वह बताता है कि इसका निर्माण काफ़ी पहले हुआ था, लेकिन कब हुआ, कोई नहीं जानता. वह मुझे इमामबाड़े से जुड़ी एक चमत्कारिक घटना के बारे में बताता है, जिसके बारे में हर चुशोटवासी जानता है. उसके मुताबिक़, एक बार कुछ डाकुओं ने लद्दाख़ के सबसे बड़े मठ हेमिस गोंपा को लूटने की कोशिश की. इतने में मंदिर के प्रवेश द्वार पर डकैतों के सामने अचानक ऊंचे पहाड़ खड़े हो जाते हैं और वे अपने मंसूबों में विफल हो जाते हैं. डाकू अपनी योजना बदल कर इमामबाड़े पर धावा बोलने के लिए चुशोट की ओर रुख़ करते हैं. लेकिन वे जैसे ही सिंधु नदी के समीप इमामबाड़े की तरफ़ बढ़ते हैं, नदी की लहरें चारों ओर से उसे घेर लेती हैं. इतने में हेमिस के प्रमुख लामा स्टाक्सन रिन्पोचे वहां से गुज़रते हैं और उन्हें इमामबाड़े के दरवाज़े पर दो शेर खड़े नज़र आते हैं. वे नदी का पानी पी रहे हैं, ताकि पानी नदी के अंदर न घुसे. तबसे हर साल हेमिस के लामा की ओर से इमामबाड़े में चाय, धूप और तेल चढ़ाया जाता है. हसन बताता है कि यह परंपरा 1989 में लद्दाख़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन (एलबीए) द्वारा मुसलमानों के बहिष्कार की घोषणा से पहले तक निर्बाध चलती रही. हसन यह भी बताता है कि इमामबाड़े में इमाम हुसैन की शोक सभा में दर्शक के रूप में पहले स्थानीय बौद्ध समुदाय के लोग भी भाग लेते थे, लेकिन 1989 के बाद यह काफ़ी कम हो गया. हालांकि स्थानीय बौद्ध सरकारी अधिकारियों को अब भी आमंत्रित किया जाता है और उनमें से कुछ शामिल भी होते हैं.

हसन बहिष्कार के मसले पर बोलना नहीं चाहता है और मुझे बताता है कि बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के बीच संबंध अब लगभग सामान्य हो चुके हैं. हसन के ज़्यादातर दोस्त बौद्ध हैं. असल में उसका मातृपक्ष आंशिक रूप से बौद्ध है और उसके बौद्ध संबंधी अक्सर उसके घर भी आते हैं. इसी तरह त्योहारों के मौक़ों पर उसका परिवार भी अपने बौद्ध संबंधियों के घर जाता है. जब ऐसा होता है तो उनके संबंधी उनके लिए किसी मुसलमान रसोइए से ख़ास तौर पर खाना बनवाते हैं. हसन किसी से न बताने की शर्त पर मुझे बताता है कि वह जब लद्दाख़ के बाहर जाता है तो ग़ैर मुसलमान के हाथों से तैयार खाना भी खाता है. हसन मुझे अपने साथ घर ले जाता है और अपनी किताबों का संग्रह मुझे दिखाता है. वह मुझे लद्दाख़ की एकमात्र अंग्रेजी भाषी पत्रिका लेडेग्स मिलांग की प्रतियां दिखाता है और बताता है कि यह पत्रिका पूरी तरह धर्म निरपेक्ष है. इसके संपादक सोनम वांगचुक बौद्ध हैं और इसके दो उप संपादक मुहम्मद हसनैन एवं रेबेक्का नॉरमन क्रमशः मुस्लिम और ईसाई समुदाय से हैं.

मैं हसन की दी पत्रिकाओं को एक सरसरी निगाह से देखता हूं. इसके अधिकांश लेखों में स्थानीय विकास संबंधी मुद्दों को उठाया जाता है. कुछ मुद्दे बौद्ध–मुस्लिम के संबंधों पर आधारित थे और मैंने तुरंत उन मुद्दों को अपनी डायरी में नोट कर लिया. पत्रिका का एक अंक दलाई लामा के नुबरा स्थित मस्जिदों के दौरे पर आधारित था. इसमें मुसलमानों के साथ बौद्ध समुदाय के लोग भी शामिल हुए थे और दलाई लामा ने अपने भाषणों में सांप्रदायिक सामंजस्य पर बल दिया. एक अन्य अंक में सम्मानित बौद्ध महंत एवं राजनीतिक नेता स्वर्गीय कुशोक बाकुला का विस्तृत इंटरव्यू छपा था. बाकुला लद्दाखी लोगों को ऐसी ताक़तों से आगाह करते हैं, जो उन्हें क्षेत्र और धर्म के नाम पर बांटने की साजिश रच रहे हैं और दोनों समुदायों से एकता बनाए रखने की अपील करते हैं. तीसरे अंक में लेह के बौद्ध और मुस्लिम संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से निकाली गई एक रैली की चर्चा की गई थी. इस शांति मार्च का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर शांति बनाए रखने के लिए दबाव डालना था, ताकि कश्मीर समस्या का बातचीत के जरिए हल निकाला जा सके. सबसे अहम बात यह कि पत्रिका के धर्म वाले पन्ने पर कुरान की आयतों का लद्दाख़ी भाषा में अनुवाद छपा था. यह अनुवाद एक स्थानीय मौलवी और लामा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है.

feedback@chauthiduniya.com

CITIZEN FORUM ON HUMAN RIGHTS
FOR GOVT.-SEMI GOVT. & GENERAL PUBLIC
National President's Admn. Office :
D-67, Main Bazar, Gandhidham - 370 201. Gujarat Fax : 02836-220213 Mobile : 94262 15334
E-mail : nchrcr_india@yahoo.co.in Visit us : www.indianhumanrights.org
Regd. No. 6-54681
Central Off : New Delhi
Last Reminder - cum - Invitation
जन - मजदूर संसद
25 सितंबर 2010
E-mail : indianhumanrightsorg@gmail.com Cell. : 94262 15334
DELEGATE REGISTRATION FORM
(१) प्रतिनिधी डेलीगेट्स को अपने स्वयं के खर्चे पर आना जाना पड़ेगा...., आयोजक किसी प्रकार के किराये का भुगतान नहीं करेंगे।
(२) डेलीगेट्स प्रतिनिधी को अपने रुकने के लिए होटल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी या उसे संस्था द्वारा धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था में रुकना पड़ेगा।
LAST DATE FOR REGISTRATION 20TH SEPTEMBER 2010. RSVP FAX NO. : 02836 - 232308 / 220213.
Contact Directly to Hotels at Himatnagar for your Bookings if you wish
HOTEL LANDMARK 9925734143 / 9926517110
HOTEL PAYAL 9979991777
POONAM GUEST HOUSE 9427056036
HOTEL SUNLIGHT 02772245092
HOTEL RAKA PALACE 02772241444
HOTEL SURVODAY 9427304707 / 9909941808
HOTEL AVION PLAZZA 9426343321 / 9426049135
HOTEL SUN FLOWER 02772 241089
SPECIAL NOTE :
visit us : www.citizenforumonhumanrights.org
Be United for your Rights : start a chapter under your leadership

डायमंड ज्वेलरी की लोकप्रियता और उसके प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए तनिष्क ने हाई वैल्यू डायमंड ज्वेलरी वर्ग में उम्दा कारीगरी वाले 200 नए डिजाइन पेश किए हैं.

आपके पास हो ख़ास मोटरसाइकिल

भारतीय बाज़ार में अपनी मोटरसाइकिलों की क़ामयाबी से प्रेरित होकर इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने मोटरसाइकिल के तीन नए मॉडल लांच किए हैं. एसजेड, एसजेड-एक्स और वाईबीआर-125 नाम के तीनों मॉडल भारतीयों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. लांचिंग के मौक़े पर बॉलीवुड अभिनेता एवं भारत में यामाहा के ब्रांड एंबेसडर जॉन अब्राहम भी मौजूद थे. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक यूकीमिने सूजी के अनुसार, एसजेड, एसजेड-एक्स और वाईबीआर-125 मॉडल के जरिए हम अपने ग्राहकों को विश्व स्तर के उत्पाद उपलब्ध कराना चाहते हैं. इन मॉडलों को ख़ास तरीक़े से डिजाइन किया गया है, ताकि इनकी सवारी करने वाले को अधिक से अधिक आराम मिले. एसजेड और एसजेड-एक्स बिल्कुल नई 4 स्ट्रोक एयरकूल्ड मोटरसाइकिलें हैं. इनमें 153 सीसी इंजन का एसओएचबी सिंगल सिलेंडर लगा हुआ है, जो अच्छे प्रदर्शन के लिए ट्यून किया गया है यानी एक्स्ट्रा पॉवर. यह भारतीय सड़कों और कम-मध्यम गति के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा. उक्त मॉडल एआई सिस्टम से युक्त हैं और स्वच्छ एक्जॉस्ट के लिए इसमें कैटेलाइजर के साथ बड़ी क्षमता वाला मफलर है.

इनमें स्पोर्टी फेंडर (आघात से बचाव हेतु आड़) एवं स्प्लीट लुक की वजह से इनका आकर्षण और बढ़ गया है. इनमें 14 लीटर का ईंधन टैंक है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा आसानी से की जा सकती है. साथ ही लंबी एवं कुशनयुक्त सीट है, जो यात्रा को आरामदेह बनाती है. एसजेड-एक्स बेहतरीन तकनीकों से लैस है, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्टर और अंदर आने वाली हवा को रोकने के लिए विंड स्क्रीन. इससे बिना दिक्कत के सवारी की जा सकती है. इन मॉडलों में

परिष्कृत मीटर पैनल और नए लुक वाली टेल लाइट्स हैं. पूरी तरह प्लास्टिक का बना चेन केस है, जो धूल और पानी से सुरक्षा प्रदान करता है. साथ ही पुख्ता साइड कवर और 5 स्पोक कास्ट व्हील हैं. एसजेड दो रंगों यानी काले और लाल में उपलब्ध है, जबकि एसजेड-एक्स मॉडल में तीन रंग उपलब्ध हैं काला, लाल और ग्रे मैटेलिक. उक्त मॉडल अंतरराष्ट्रीय स्तर की मोटरसाइकिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन्हें एक्जीक्यूटिव सेगमेंट के ग्राहकों को लक्ष्य करके बनाया गया है. इनमें 123 सीसी इंजन और 4 स्पीड गियर बॉक्स है. कंपनी ने एसजेड की क़ीमत 49,000 रुपये, एसजेड-एक्स की क़ीमत 52,000 रुपये और वाईबीआर-125 की क़ीमत 47,000 रुपये तय की है.

फोटो खींचने का नया अंदाज़

जापान की कंपनी कैशियो ने अपने भारतीय ग्राहकों का ख्याल करते हुए उनके जीवन के हसीन पलों को संजो कर रखने के लिए कैमरे का एक नया मॉडल बाज़ार में उतारा है. एक्जीलिम रेंज का यह ख़ास जेड-2000 मॉडल कई कस्टमाइज्ड फीचर्स के साथ एक्सीलेंट प्वाइंट एवं शूट फोटोग्राफी जैसी तकनीकों से लैस है. डायनमिक फोटोग्राफी को सार्थक करते हुए इस कैमरे से मूविंग ऑब्जेक्ट्स को शूट करना आसान है. इस मॉडल में दिए गए एक्जीलिम इंजन 5.0 के साथ मल्टीपल फास्टर इमेजिंग प्रोसेसिंग से खींची गई फोटो की प्रोसेसिंग भी तीस प्रतिशत तक तेज हो जाती है. कैमरे का प्रीमियम ऑटो मोड फीचर विभिन्न वस्तुओं की भीड़ में भी वांछित वस्तु पर ख़ुद ही फोकस कर लेता है और फोटो भी बेहतरीन आता है. कैमरा ख़ुद प्वाइंट ऑफ फोकस, फोटो ब्लर करेक्शन, टोनल रेंज एवं कलर बैलेंस, सेंसिटीविटी और नॉयज रिडक्शन के स्तर को अपने अनुरूप बना लेता है. प्रीमियम ऑटो मोड पूर्णत: ऑटोमैटिक फीचर है, जो यूजर को बेहतरीन क्वालिटी की फोटो लेने में मदद करता है. जेड-2000 कैमरे में मौजूद आर्ट शॉट फंक्शन से खींचे गए फोटो को देखकर पेंटिंग सा आभास होता है. कैमरे के व्यू एलसीडी स्क्रीन में ही सब्जेक्ट को ऑयल पेंटिंग, क्रेयॉन ड्राइंग या वाटर कलर पेंटिंग के पैटर्न में डाल सकते हैं, उसके बाद उसी पैटर्न में फोटो खिंच जाती है. 14.1 मेगा पिक्सल के इस कैमरे में वाइड एंगल 26 एमएम 5 एक्स ऑप्टिकल ज़ूम का विकल्प है. एक्स-जेड 2000 में 3.0 इंच सुपर क्लियर पतली एलसीडी स्क्रीन में 460,000 पिक्सल का कांपैक्ट हाई रिजोल्यूशन है. इस कैमरे में दिए गए सीसीडी शिफ्ट इमेज स्टेबिलाइजेशन और एचडी मूवी फंक्शन के साथ बढ़िया बैट्री बैकअप है. एक बार चार्ज करने के बाद इससे 580 शॉट्स लिए जा सकते हैं. इस मॉडल को आकर्षक लुक देने के लिए ख़ास स्टाइल में डिजाइन किया गया है. इसकी क़ीमत 14,995 रुपये है.

महकता रहेगा बगीचा

एक अच्छा घर, हंसी-ख़ुशी से भरा माहौल और छोटा सा गार्डन, जहां अपनों के साथ बैठकर बढ़िया वक्त गुज़ारा जा सके...यही सपना हर आदमी देखता है. ऐसे ही आपके सपने को ख़ूबसूरत रंग देने के लिए बॉस ने कुछ नए गार्डन टूल्स बाज़ार में उतारे हैं. घर के आसपास बना गार्डन चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सभी की आंखों को भाता है. उसे सुंदर बनाए रखने के लिए उसकी उचित देखभाल बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उपयुक्त औजारों को ज़रूरत होती है, जो पौधों को नुक़सान न पहुंचाएं और इस्तेमाल में भी आसान हों. लीथियम आयन तकनीक से लैस बॉस के गार्डन टूल्स का बैट्री बैकअप काफ़ी मजबूत है. इसका कॉडलेस लॉनमोवर रोटक 34 एलआई अतिरिक्त घास की सफ़ाई से कटाई करता है. कॉडलेस आईएसआईओ शब्र एंड एजिंग शियर पौधों को नुक़सान पहुंचाए बिना कांटों और झाड़ियों को हटाने में मददगार होता है. कॉडलेस ग्रास ट्रिमर एआरटी 23 ईजीट्रिम हल्का और इस्तेमाल करने में आसान उपकरण है, जिससे घास को किसी भी शेप में ढालने के लिए ट्रिम कर सकते हैं. इन गार्डन टूल्स की उपयोगिता बताते हुए बॉस पावर टूल्स के रीजनल सेल्स डायरेक्टर कहते हैं कि कंपनी ने भारतीय बाज़ार में पहली बार कॉडलेस गार्डन टूल्स की रेंज उतारी है. गार्डन टूल्स की यह रेंज भारतीय ग्राहकों को अपना घर-गार्डन हरा-भरा बनाए रखने में मदद करेगी. इन उपकरणों की क़ीमत 3500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है. ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से मनपसंद टूल ख़रीद सकते हैं. ये गार्डन टूल्स छोटे और बड़े दोनों तरह के गार्डन को ख़ूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. किचन गार्डन को भी आकर्षक लुक देने के लिए गार्डन टूल्स काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं.

आपको ख़ास बनाता है हीरा

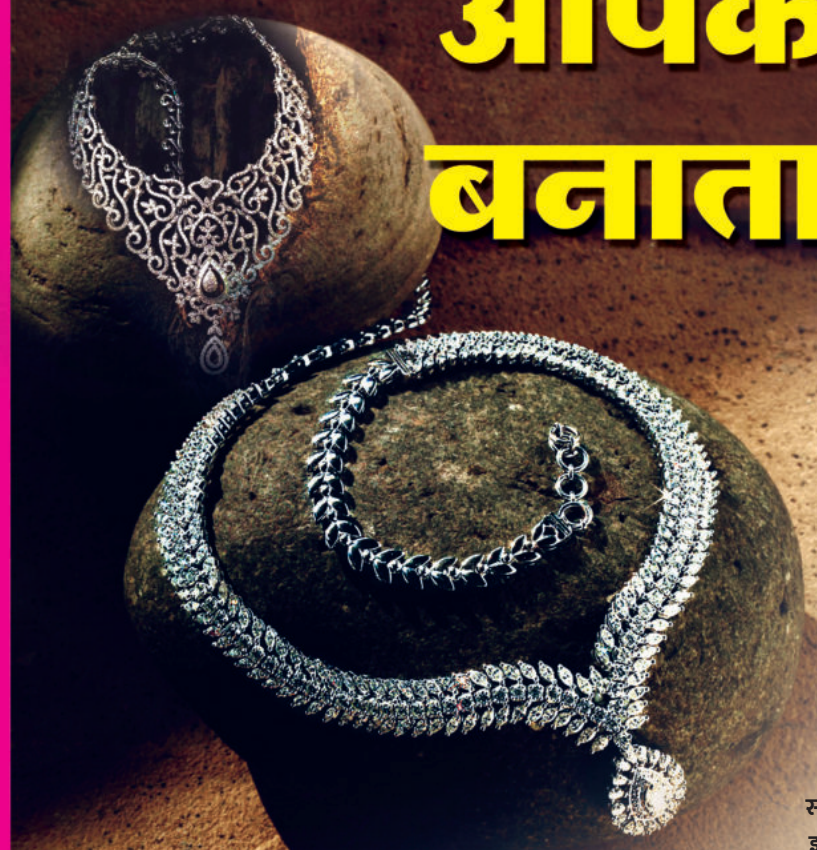

हीरे के आभूषण हमेशा से महिलाओं की पहली पसंद रहे हैं. डायमंड ज्वेलरी की लोकप्रियता और उसके प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए तनिष्क ने हाई वैल्यू डायमंड ज्वेलरी वर्ग में उम्दा कारीगरी वाले 200 नए डिजाइन पेश किए हैं. ख़ासे आकर्षक और स्टाइलिश इस संग्रह का हर गहना जैसे ख़ुद में एक कहानी गढ़े हुए है और उसकी यही ख़ूबी इस संग्रह को अद्भुत एवं समकालीन बनाती है. इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के डिजाइन किए गए नेकलेस, ब्रेसलेट, इयरिंग्स, बैंगल्स और अंगूठियां शामिल हैं. यह संग्रह आधुनिक डिजाइन के परंपरागत गहनों का बेजोड़ तालमेल पेश करता है. इसके गहने जहां प्राचीन समय की शान समेटे हुए हैं, वहीं आधुनिक समय के स्टाइल से भी लैस हैं.

इस तरह यह संग्रह आज की महिलाओं को सहज ही आकर्षित करने की क्षमता रखता है. इसका आधुनिक स्टाइल और डिजाइन देखते ही आपकी नज़रें ठहर जाएंगी. इसे पहन कर युवतियां ख़ुद को भीड़ से अलग साबित कर सकती हैं. इस संग्रह के गहनों की क़ीमत 2 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये के बीच है. महीन कारीगरी से दमकती डायमंड ज्वेलरी के कुछ नमूने ऐसे भी हैं, जिनकी क़ीमत एक करोड़ रुपये तक है. इस रेंज को आधुनिक महिलाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिन्हें पहन कर उन्हें ज्वेलरी पहनने का एहसास होगा, साथ ही इसके समकालीन डिजाइन उन्हें फैशनेबल और ट्रेंडी भी बनाएंगे. इन्हें तैयार करने में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले हीरे इस्तेमाल किए गए हैं. तनिष्क भारत के एकमात्र राष्ट्रीय ज्वेलर हैं, जो 6000 से अधिक परंपरागत, पश्चिमी एवं दोनों के मिश्रण (फ्यूज़न) वाले सोने (22 व 18 कैरेट) और क़ीमती नगों के आभूषण पेश करते हैं. तनिष्क की रिटेल चेन में 75 शहरों के 115 विशिष्ट बुटीक शामिल हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

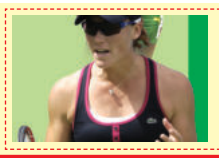

खेल मंत्री एम एस गिल जुलाई महीने में ही खिलाड़ियों के इस रवैये पर अपनी चिंता जता चुके हैं, लेकिन आयोजन समिति के कान पर जूं तक नहीं रेंगी.

स्टार खिलाड़ियों से महरूम रहेगा राष्ट्रमंडल खेल

वेरोनिका कैंपबेल-ब्राउन

राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में घपले की ख़बरें आज मीडिया में सुर्ख़ियां बटोर रही हैं. हर गली-चौराहे से लेकर देश की संसद तक में इस पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन इस सारे हो-हल्ले के बीच यह बात दबकर रह गई है कि देश का सबसे बड़ा खेल आयोजन माने जा रहे इन खेलों से दुनिया के टॉप एथलीट धीरे-धीरे किनारा करते जा रहे हैं. तीन बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके धावक उसैन बोल्ट पहले ही इसमें शामिल होने से इंकार कर चुके हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसा करने वाले वह अकेले नहीं हैं. साइक्लिंग में चार बार ओलंपिक चैंपियन क्रिस हॉय, इंग्लैंड के स्प्रिंटर ड्वेन चैंबर्स एवं धाविका जेसिका एनिस, जमैका की वेरोनिका कैंपबेल-ब्राउन, इंग्लैंड के ही ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एवं विश्व चैंपियन साइक्लिस्ट विक्टोरिया पैंडल्टन, ऑस्ट्रेलियाई तैराक केट कैंपबेल एवं टेनिस खिलाड़ी सामंता स्टोसुर एवं स्कॉटलैंड की चैंपियन जिमनास्ट डेनियल कीटिंग जैसे एथलीट भी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेने की घोषणा कर चुके हैं. इन खेलों की शुरुआत में अभी भी क़रीब एक महीने का समय बचा है और जिस तरह से एक-एक कर शीर्ष एथलीट इससे किनारा करते जा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं यह दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों के बीच की प्रतियोगिता बनकर न रह जाए.

ताज्जुब की बात तो यह है कि आयोजन समिति इस सबसे बेख़बर है. खेल मंत्री एम एस गिल जुलाई महीने में ही खिलाड़ियों के इस रवैये पर अपनी चिंता जता चुके हैं, लेकिन आयोजन समिति के कान पर जूं तक नहीं रेंगी. समिति के सदस्य तो इसी चिंता से हलकान हुए जा रहे हैं कि किसी तरह सारी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएं. लेकिन तैयारियां पूरी हो भी गईं और शीर्ष खिलाड़ी इसमें शरीक नहीं हुए तो फिर इतने बड़े आयोजन का मतलब क्या है. साल 2003 में जब भारत को राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की ज़िम्मेदारी मिली थी तो तमाम खेलप्रेमियों के दिलों में यह उम्मीद बंधी थी कि वे शीर्ष एथलीटों को अपनी नज़रों के सामने परफॉर्म करते हुए देख पाएंगे, लेकिन खिलाड़ियों के इस रवैये को देखने के बाद वे उम्मीदें काफूर हो चुकी हैं. इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं, लेकिन भारतीय दर्शक यदि शीर्ष खिलाड़ियों को परफॉर्म करते हुए देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर इतनी बड़ी राशि ख़र्च करने का तुक क्या है. सरकार एवं आयोजन समिति बार-बार इसे देश का सबसे बड़ा खेल आयोजन घोषित कर रही है और इसकी सफलता को लेकर रोज नए-नए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अस्त-व्यस्त तैयारियां और शीर्ष खिलाड़ियों की ग़ैर मौजूदगी को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह कहीं देश का सबसे शर्मनाक खेल आयोजन बनकर न रह जाए.

आदित्य पूजन
aditya@chauthiduniya.com

उसैन बोल्ट

क्रिस हॉय

सामंता स्टोसुर

दरकने लगी है टीम इंडिया की दीवार

श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ जीतने का भारतीय क्रिकेट टीम का सपना एक बार फिर अधूरा ही रह गया. बड़ी उम्मीदों के साथ तीन टेस्ट मैच खेलने श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया को अपने प्रमुख गेंदबाज़ों की अनुपस्थिति में बल्लेबाज़ी के लिए मुफ़ीद पिचों पर सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ कराने के लिए मजबूर होना पड़ा. पहला टेस्ट हारने के बाद तो एक समय टीम पर सीरीज गंवाने का ख़तरा मंडराने लगा था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग के ऑलराउंड प्रदर्शन और सचिन तेंदुलकर एवं वीवीएस लक्ष्मण की शानदार बल्लेबाज़ी के बूते वह आख़िरी मैच जीतने में कामयाब रही. टीम की इस जीत में ईशांत शर्मा और प्रज्ञान ओझा की गेंदबाज़ी की भी अहम भूमिका रही, लेकिन मैच की पहली पारी में बैटिंग ऑर्डर के बिखरने के बाद पुछल्ले बल्लेबाज़ों का साहसिक प्रतिरोध निर्णायक साबित हुआ. अभिमन्यु मिथुन, अमित मिश्रा एवं ईशांत की बल्लेबाज़ी का ही यह कमाल था कि भारत श्रीलंका टीम के स्कोर के पार जाने में कामयाब रहा और मेजबान टीम दबाव में आ गई. मैच की चौथी पारी में मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की नैय्या को लक्ष्मण की जादुई कलाइयों ने पार लगा दिया और टीम अपनी प्रतिष्ठा एवं विश्व रैंकिंग में नंबर एक का ताज बचाने में सफल रही. लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, वह है टीम के द वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ का ख़राब फॉर्म. द्रविड़ इस सीरीज की पांच पारियों में शतक तो क्या, कोई अर्द्धशतक भी नहीं लगा पाए. पूरी सीरीज में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 44 रहा और दो बार तो वह दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाए. उनके डेढ़ दशक लंबे करियर में यह केवल तीसरा मौक़ा है, जब तीन मैचों की सीरीज़ में वह कोई बड़ी पारी न खेल पाए हों.

द्रविड़ का ख़राब फॉर्म भारत के लिए चिंता का कारण इसलिए है कि टीम ख़राब हालत में हो तो वह अक्सर संकट मोचक बनते रहे हैं. साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कोलकाता में खेला गया ऐतिहासिक टेस्ट मैच हो या 2002 में इंग्लैंड में खेली गई सीरीज़ में लगातार तीन शतकीय पारियां, साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एडिलेड में उनकी 233 रनों की पारी हो या 2008 में दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ चेन्नई टेस्ट मैच में लगाया उनका शतक, द्रविड़ की तक़रीबन हर पारी भारत के लिए या तो मैच जिताऊ साबित हुई है या हार से बचाने में मददगार रही है. द्रविड़ की बल्लेबाज़ी में न तो सहवाग की आक्रामकता है न ही सचिन की संपूर्णता, लेकिन सुघड़ तकनीक और दबाव को झेलने की उनकी ख़ासियत से मैदान पर उनकी मौजूदगी क्रिकेट प्रेमियों को सुकून का एहसास देती रही है. गेंदबाज़ी के अनुकूल पिचों पर उनकी बल्लेबाज़ी सालों से टीम का मुख्य आधार रही है, लेकिन पिछले क़रीब दो सालों से उनका फॉर्म उन्हें दगा देता रहा है. 1996-2010 के बीच 142 टेस्ट मैचों में उन्होंने क़रीब 53 के औसत से 10490 रन बनाए हैं, लेकिन पिछले दो सालों में उनकी बल्लेबाज़ी का औसत 45 के आसपास घूमता रहा है. किसी साधारण बल्लेबाज़ के लिए यह आंकड़ा बुरा नहीं है, लेकिन द्रविड़ साधारण बल्लेबाज़ों की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें भारत के सर्वकालिक महानतम बल्लेबाज़ों में गिना जाता है.

किसी एक सीरीज़ में खिलाड़ी के ख़राब प्रदर्शन से उसकी प्रतिभा पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते. द्रविड़ पहले भी ख़राब फॉर्म के दौर से गुजरे हैं, लेकिन हर बार उन्होंने जोरदार वापसी की है. समस्या यह है कि अब उनकी उम्र उनके साथ नहीं है. आने वाली जनवरी में वह 38 साल के हो जाएंगे. फिर युवा खिलाड़ियों की एक पूरी फौज उनके पीछे खड़ी है. युवराज सिंह, चेतेश्वर पुजारा, सुरेश रैना एवं रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम में उनकी जगह को ललचाई निगाहों से देख रहे हैं. यही वजह है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके, अपने ख़राब फॉर्म से पार पाना होगा, अन्यथा सौरव गांगुली के बाद टीम इंडिया के फैबुलस फोर का दूसरा विकेट गिरने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 23 अगस्त–29 अगस्त 2010

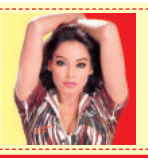

पहली फिल्म प्रियदर्शन की है आक्रोश, जो ऑनर किलिंग्स पर आधारित है और दूसरी फिल्म रोहन सिप्पी की दम मारो दम है, जो गोवा के ड्रग्स माफ़ियाओं पर आधारित है.

गाने आज कल

सुर है, न कोई अर्थ. जिस गीत-संगीत को सुनकर हम सुकून महसूस करते हैं, अगर वही अशिष्ट और अर्थहीन हो तो वह हमें और समाज को किस स्तर तक नुक़सान पहुंचा सकता है, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है. आश्चर्य यह है कि हर गली-मुहल्ले में यही गाने धड़ल्ले से सुने भी जा रहे हैं. हिंदी गानों में अंग्रेजी के शब्द भी बेहिचक प्रयोग किए जा रहे हैं.

सोनिका गुप्ता

*चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा यह मुस्कान...*1968 में आई हिंदी फिल्म सरस्वती चंद्र का यह गाना आज भी कहीं सुनाई पड़ता है तो दिल में प्यार हिलोरें लेने लगता है. इसी तरह 1962 में आई फिल्म बीस साल बाद का गाना-कहीं दीप जले, कहीं दिल सुनकर विरह की आग में जल रहे प्रेमियों के जख्म अभी भी हरे हो उठते हैं. फिल्म कभी-कभी के गीत कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, में मुकेश एवं लता मंगेशकर की स्वर लहरियां जैसे-जैसे परवान चढ़ती हैं, दिल में एक अजीब सी कसक का एहसास होने लगता है, मानो बड़ी मुश्किल से भूला अपना पहला प्यार याद आ रहा हो. लेकिन हिंदी फिल्मों का वह एक अलग दौर था, जब गानों के बोलों में अर्थ, संदेश और वजन झलकता था. गीतों की एक गरिमा थी, जिसे सहेजते थे मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, गोपालदास नीरज, शकील बदायूंनी और इंदीवर जैसे रचनाकार.

लेकिन अब जमाना बदल गया है, आज बॉलीवुड अपनी पहचान हॉलीवुड की तरह बनाना चाहता है और इसीलिए अब फिल्म का हीरो बेधड़क गाता है, मेरी पैंट भी सेक्सी-मेरी शर्ट भी सेक्सी. 2004 में आई फिल्म दुलारा का यह गीत बताता है कि परिवर्तन की चाह ने बॉलीवुड का चरित्र ही बदल डाला है. और अफसोस इस बात का है कि अब इस नकारात्मक परिवर्तन के ख़िलाफ़ कहीं से कोई आवाज़ भी नहीं उठती. आज से 14 साल पहले की बात है, राज्यसभा की एक महिला सदस्य ने फिल्म मोहरा के गीत-तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त... के बोलों पर आपत्ति जताते हुए हिंदी फिल्मी गीतों के गिरते स्तर के प्रति आगाह किया था. तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सी इब्राहिम समेत सदन के कई सदस्यों ने उनकी चिंता का समर्थन किया था. उन्हीं दिनों 1993 में आई फिल्म खलनायक के गीत चोली के पीछे क्या है... ने भी धूम मचा रखी थी. शोहदों को इस गीत के रूप में एक हथियार सा मिल गया था.

सवाल यह है कि गीतकार समाज के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख क्यों होते जा रहे हैं. इब्नेबतूता बगल में जूता (इश्कियां), तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया भूतनी के (सिंह इज किंग) एवं पप्पू कांट डांस साला (जाने तू या जाने ना) जैसे गीत समाज को क्या दे रहे हैं? इनमें नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? बॉलीवुड के बाद भोजपुरी फिल्मों का नंबर आता है. बॉलीवुड फिल्मों से ज़्यादा अश्लीलता भोजपुरी फिल्मों के गीतों में देखने को मिलती है. बच्चे एवं नौजवान टेलीविज़न और फिल्मों में जो कुछ देखते हैं, उसकी नकल करते हैं. समाज बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो चुका है. पवित्र नाते-रिश्तों की मज़बूती पहले जैसी नहीं रह गई है. कहीं न कहीं इसकी वजह हैं आज के दौर की फिल्में, जो समाज पर ग़लत प्रभाव छोड़ रही हैं. लगभग हर फिल्म में किसी न किसी पुराने गाने का रीमिक्स पेश कर दिया जाता है. बेअर्थी बोलों का इस्तेमाल आम बात हो गई है.

फिल्में समाज का आईना होती हैं. फिल्मकारों से उम्मीद की जाती है कि वे समाज में व्याप्त विसंगतियों पर रोशनी डालते हुए जनसाधारण को सचेत करेंगे. उनके गीत लोगों का मनोरंजन तो करेंगे ही, साथ ही कोई संदेश भी देंगे. लेकिन आज जो गीत लिखे जा रहे हैं, उनमें न कोई

सुर है, न कोई अर्थ. जिस गीत-संगीत को सुनकर हम सुकून महसूस करते हैं, अगर वही अशिष्ट और अर्थहीन हो तो वह हमें और समाज को किस स्तर तक नुक़सान पहुंचा सकता है, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है. आश्चर्य यह है कि हर गली-मुहल्ले में यही गाने धड़ल्ले से सुने भी जा रहे हैं. हिंदी गानों में अंग्रेजी के शब्द भी बेहिचक प्रयोग किए जा रहे हैं.

एक समय था, जब भारतीय संगीत दूर-दूर तक प्रसिद्ध था. इसके दो भाग थे, पहला हिंदुस्तानी संगीत, जो अधिकतर उत्तर भारत में गाया जाता था और दूसरा कर्नाटक संगीत, जो दक्षिण भारत में गाया जाता था. समय बदला, आधुनिक गाने बनने लगे. इसके बाद रीमिक्स भी होने लगा. रीमिक्स का जादू इस कदर छाया कि क्या सुर, क्या ताल और क्या आवाज़, सभी बद से बदतर हो गए. बेअर्थी गानों की एक बानगी देखिए- दरवाज़ा खुला छोड़ आई नींद के मारे (नाजायज़), सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे (राजा बाबू), वोल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा (हाउसफुल), कमबख्त इश्क है जो (प्यार तूने क्या किया), छत पे सोया था बहनोई (करन अर्जुन), होंठ रसीले तेरे होंठ रसीले (वेलकम), इश्क कमीना (शक्ति) और चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर (दलाल). इन गीतों को रचने वालों के दिमाग़ में इनकी क्या सार्थकता है, यह तो पता नहीं, लेकिन पहली नज़र में इनसे कोई संदेश निकलता नहीं दिखाई देता.

पुराने समय के गीत मन को छूने वाले और सद्अर्थी होते थे. चौदहवीं का चांद हो, चंदन सा बदन-चंचल चितवन, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, कहीं दीप जले कहीं दिल और जब कोई बात बिगड़ जाए आदि गीत आज भी लोग पूरी तन्मयता से सुनते मिल जाते हैं. वजह सिर्फ़ यही थी कि इन गीतों में लोगों को अपनी बात झलकती थी, अपने दर्द-भाव के दर्शन होते थे. इसलिए तब रचे गए ये गीत आज भी लोगों को उतने ही प्रिय हैं, जितने कि उस समय थे. गीत के बोल दिल से फूटते हैं, वे खेतों-पेड़ों पर नहीं उगते. यह बात मौजूदा रचनाकारों को समझ में ज़रूर आनी चाहिए.

sonika@chauthiduniya.com

बिपाशा का फ़िटनेस फंडा

बॉलीवुड अदाकारा बिपाशा बसु इन दिनों फिल्मों में कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही हैं. हाल में संजय दत्त के साथ आई अपनी फिल्म *लम्हा* से उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थीं, लेकिन वह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. इस असफलता के बाद बिपाशा ने नॉन ग्लैमरस भूमिका से तौबा कर ली है. हालांकि कश्मीर घाटी पर आधारित फिल्म लम्हा में बिपाशा के अभिनय की तारीफ़ उनके ब्वायफ्रेंड एवं अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी की है, लेकिन उन्होंने भी उसे नॉन ग्लैमरस रोल न करने की सलाह दी है.

बिपाशा ने कहा कि नॉन ग्लैमरस रोल के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्हें अपनी ख़ूबसूरती पर गर्व है. फिल्म लम्हा से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. बिपाशा अपनी आने वाली दो फिल्मों से उम्मीद कर रही हैं. पहली फिल्म प्रियदर्शन की है *आक्रोश*, जो ऑनर किलिंग्स पर आधारित है और दूसरी फिल्म रोहन सिप्पी की दम मारो दम है, जो गोवा के ड्रग्स माफ़ियाओं पर आधारित है. दम मारो दम में उन्हें ठीक वैसा ही रोल दिया गया है, जैसा जीनत अमान का फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में था. अपने इस किरदार को लेकर बिपाशा काफी उत्साहित हैं. फिल्मों के अलावा बिपाशा आजकल हर जगह फिटनेस के संदेश देती नज़र आ रही हैं. ट्विटर पर वह अपने प्रशंसकों को फिट रहने का उपदेश देती रहती हैं. इसके अलावा विज्ञापनों में भी उनके फिटनेस फंडे सुनने को मिल जाते हैं. बिपाशा ने अपने फैंस के लिए बिपाशा बसु नेट. कॉम के नाम से अपनी एक वेबसाइट बनाई है. इस पर उनके जीवन, फिटनेस फंडा, और आने वाली फिल्मों की तमाम जानकारी उपलब्ध होगी. यानी दूसरे सेलिब्रिटीज की तरह बिपाशा भी अपने फैंस के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

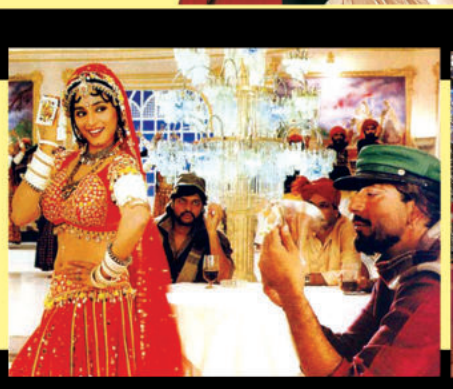

प्रिव्यू

माधोलाल कीप वाकिंग

हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती हैं, जिसे नियति मानकर इंसान बिना निराश हुए निरंतर गतिशील रहता है. जीवन के इन्हीं पक्षों से गुज़रते हुए व्यक्ति माधोलाल के जीवन को फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है. माधोलाल की ज़िंदगी उसकी पत्नी कमला, दो बेटियों सुधा एवं सुम्मी, प्रिय दोस्त और पड़ोसी अनवर के इर्द-गिर्द घूमती है. वह रोज सुबह अपने साथियों के साथ रेल का सफ़र शुरू करता है. उसके मित्रों में मज़ाकिया चपरासी राजन, वकील वर्मा, शेयर दलाल जयेश, रोमांटिक युवा अधिकारी सतीश एवं रिटायर जोशी काका हैं. सभी एक-दूसरे से रोज रेल में मिलते हैं और हंसते-बतियाते हुए अपना सफ़र पूरा करते हैं. अचानक एक दिन ऐसी दुर्घटना होती है, जिससे माधोलाल और उसके परिवार की ज़िंदगी बदल जाती है. वह ख़ामोश हो जाता है. उसे अपने साथ हुई दुर्घटना रह-रहकर याद आती है. ज़रा सी आवाज़ उसे चौंकाती, डराती है. वह घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता है. घरवाले, दोस्त-यार सभी उसके मन में बैठा डर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क़ामयाब नहीं हो पाते. उसके बाद वह अपने डर से ख़ुद लड़ता है और फिर एक नई ज़िंदगी शुरू करता है.

फिल्म में माधोलाल की भूमिका में सुब्रत दत्त हैं. पत्नी की भूमिका नीला गोखले और बड़ी बेटी की भूमिका स्वरा भास्कर ने

निभाई है. फिल्म में कुछ ही गाने हैं, लेकिन काफ़ी दिनों बाद दर्शकों को इस फिल्म के ज़रिए कव्वाली का आनंद मिल सकेगा. संगीत दिया है नायाब राजा ने. विज्ञापन की दुनिया से फिल्म निर्देशन में क़दम रखने का साहस किया है युवा जया टांक ने. यह फिल्म ड्रीम कट्स, मकबूल एवं रावण जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके अजय घई द्वारा निर्मित है. क़रीब सौ विज्ञापन फिल्मों में काम कर चुके अजय ने लोकप्रिय धारावाहिक मिली में राहुल की भूमिका अदा की थी. इसके अलावा वह गुब्बारे, मुड़-मुड़ के न देख, सुपरहिट मुक़ाबला, मामला गड़बड़ है एवं किनारे मिलते हैं आदि धारावाहिकों में भी नज़र आए. वह सास वर्सेज बहू नामक डांस शो में भी दिखे थे. आम आदमी से ताल्लुक रखने वाली यह फिल्म 27 अगस्त को रिलीज होगी. यह बॉलीवुड में बनने वाली दूसरी कॉमेडी और स्किन शो वाली फिल्मों से अलग जीवन के असली मायनों पर आधारित फिल्म है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 23 अगस्त-29 अगस्त 2010

www.chauthiduniya.com

ललन की खिचड़ी में पासवान का तड़का

मौसम चुनाव का है, इसलिए कौन किसका दोस्त है और कौन दुश्मन, यह समझ में नहीं आ रहा है. कल तक जो उधर था, आज इधर है. जो इधर है, वह कल किधर जाएगा, पता नहीं. लेकिन जनता नेताओं के इस अजूबे खेल का पूरा आनंद ले रही है.

सरोज सिंह

किसी जासूसी फिल्म की तरह बिहार की चुनावी पटकथा भी रोमांच और अटकलों से सराबोर नज़र आने लगी है. हाल यह है कि आज की तस्वीर कल से जुदा दिखती है. दोस्त और दुश्मन हमशक्ल लग रहे हैं. दिन में एक दूसरे से गले मिलते नेता देर रात में उसकी चुनावी क़ब्र खोदने की रणनीति बनाने में मशगूल दिखते हैं. पिछले दिनों लालू-राबड़ी को शासन से बेदखल करने में अहम किरदार निभाने वाले प्रभुनाथ सिंह छपरा में लालू प्रसाद से सार्वजनिक रूप से गले मिलते दिखे तो दिल्ली में नीतीश से खार खाए सांसद ललन सिंह ने रामविलास पासवान के घर एक नई राजनीतिक खिचड़ी पकाने में माथा खपाया. रामकृपाल यादव की आनंद मोहन के साथ सौदेबाज़ी जारी है तो सभी दलों की लाख कोशिशों के बावजूद दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल सिंह एवं भाई त्रिपुरारी सिंह अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं. राजनीतिक उलझन का आलम यह है कि चाहकर भी कोई नेता इस समय अपने विरोधी नेता के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि डर है कि कहीं अगले दिन वह नेता उसी के पाले में खड़ा न दिखाई पड़ जाए.

प्रभुनाथ सिंह को अपने साथ मिलाकर लालू प्रसाद ने निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है. सारण की राजनीति को समझने वाले यह अच्छी तरह जानते हैं कि छपरा, सिवान एवं गोपालगंज इलाके में लालू और प्रभुनाथ की सामूहिक ताक़त के क्या राजनीतिक मायने हैं. छपरा में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाह बनी कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार को सारण में कितने चने चबाने पड़ेंगे. प्रभुनाथ सिंह को गले लगाकर एक तरह से लालू प्रसाद ने पूरे सारण में नीतीश कुमार की घेराबंदी कर दी. लालू और प्रभुनाथ सिंह के एक हो जाने के बाद नीतीश कुमार सारण की सीटों के लिए नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं. प्रभुनाथ सिंह से नाराज़ नेताओं एवं लोगों का दिल टटोला जा रहा है. कोशिश नुकसान को कम से कम करने की है. इसी तरह मिथिलांचल में घेराबंदी के लिए आनंद मोहन एवं रामकृपाल यादव के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और संभावना है कि जल्द ही इस समझौते की सार्वजनिक घोषणा कर दी जाएगी. पिछले चुनाव में कोसी में मात खाने के बाद इस चुनाव में लालू प्रसाद कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं. यही वजह है कि आनंद मोहन के साथ काफ़ी गंभीरता से बात की जा रही है. आनंद मोहन को भी अपनी राजनीतिक पुनर्वापसी के लिए यह रास्ता ठीक लग रहा है. इन दो राजनीतिक घटनाओं से जहां राजद की पकड़ मज़बूत होती दिखाई पड़ रही है, वहीं इसके साइड इफेक्ट से पार्टी की सेहत को नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है. रामविलास पासवान के साथ ललन सिंह के डिनर को इसी का प्रतिफल माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि प्रभुनाथ सिंह एवं आनंद मोहन के साथ सीटों के वादे ने लोजपा की सीटों का गणित पूरी तरह बिगाड़ दिया है. सारण एवं मिथिलांचल की लोजपा की कई सीटों पर प्रभुनाथ सिंह एवं आनंद मोहन ने दावा ठोंका है. लालू प्रसाद हर हाल में प्रभुनाथ सिंह एवं आनंद मोहन का साथ चाहते हैं. इसके अलावा लालू प्रसाद दिग्विजय सिंह की पत्नी को भी अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़वाना चाहते हैं.

प्रभुनाथ सिंह को गले लगाकर एक तरह से लालू प्रसाद ने पूरे सारण में नीतीश कुमार की घेराबंदी कर दी. लालू और प्रभुनाथ सिंह के एक हो जाने के बाद नीतीश कुमार सारण की सीटों के लिए नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं.

बताया जाता है कि पुतुल सिंह भी कुछ सीटों की मांग रख सकती हैं. यही वजह है कि लोजपा एवं राजद के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है. पटना एवं दिल्ली में कई दौर की बातचीत के बाद भी अंतिम फ़ैसला नहीं हो सका है. सूत्रों की बातों पर भरोसा करें तो यह बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद जानबूझ कर सीटों के बंटवारे में देर कर रहे हैं, ताकि लोजपा को अगर कम सीटें भी मिलें तो भी उसके पास विकल्प कम रहें. लोजपा लगभग सौ सीटों पर अपना दावा जता रही है, जबकि राजद पचास से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है. इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें भी हैं, जिन पर लोजपा ने वीटो लगा दिया है, पर प्रभुनाथ सिंह एवं आनंद मोहन से किए गए वादों के कारण राजद मजबूरी जता रहा है. इस संदर्भ में मांझी एवं सहरसा की सीटों का उदाहरण दिया जा सकता है. रामविलास पासवान को भी इस संकट का एहसास हो चुका है और यही वजह है कि उन्होंने समय रहते विकल्प की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि पासवान की पहली प्राथमिकता लालू प्रसाद के साथ सम्मानजनक सीटों का समझौता है और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को उनका वाजिब हक़ दिलाने के लिए वह कांग्रेस के साथ भी तालमेल कर सकते हैं. ललन सिंह एवं रामविलास पासवान की मुलाकात इसी संभावना को पुख्ता करने की एक कड़ी थी.

बताया जाता है कि कांग्रेस और लोजपा के बीच आधा आपका-आधा हमारा के फॉर्मूले पर बात आगे बढ़ रही है. इसके अलावा रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की भी योजना है. ललन सिंह की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह रामविलास को लालू प्रसाद से अलग कर दिया जाए. इससे उन्हें भी अपनी चुनावी योजना को अमलीजामा पहनाने में मदद मिलेगी. ललन सिंह लखीसराय में अपने समर्थकों की एक बड़ी रैली करके अपनी ताक़त का एहसास कराना चाहते हैं. कांग्रेस में फ़िलहाल शामिल होने के बजाय वह उसके लिए जमकर प्रचार करना चाहते हैं. चुनाव बाद अगर सब ठीक रहा तो केंद्र में कांग्रेस की तरफ से उन्हें मंत्री पद का तोहफ़ा दिया जा सकता है. इसके अलावा ललन सिंह कांग्रेस की तरफ से लगभग पचास टिकट बांटने की योजना भी बना रहे हैं. ललन सिंह को लगता है कि अगर रामविलास पासवान को कांग्रेस के पाले में ले आया जाए तो नीतीश कुमार को पटखनी देने में आसानी होगी. कांग्रेस भी बिहार में अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने के लिए ललन सिंह जैसे मज़बूत नेता का अंदरखाने पूरा साथ दे रही है. वैसे रामविलास एवं कांग्रेस के कई केंद्रीय नेता दिल्ली में इन दिनों मिलते रहे, पर बिहार को लेकर उनकी गंभीर बातचीत ललन सिंह के साथ हुई. इसे कुछ लोग लालू प्रसाद पर दबाव की राजनीति के तौर पर भी देख रहे हैं. लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी है कि अगर नेताओं के लिए टिकट का जुगाड़ रामविलास नहीं कर पाए तो उन्हें पार्टी के भीतर भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और पार्टी में बग़ावत की भी नौबत आ सकती है. इसलिए वह काफ़ी फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं. जल्द ही उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी हो सकती है. रामविलास को इस बात का एहसास है कि अगर आगामी चुनाव में वह बिहार में अपनी ताक़त नहीं बढ़ा पाए तो दिल्ली और प्रदेश की राजनीति में उनका क़द काफी घट जाएगा. इसी कारण ललन सिंह के साथ बातचीत में उन्होंने सारी संभावनाओं को टटोला. मुमकिन है, जल्द ही बिहार में कुछ ऐसे चेहरे गले मिलते दिखाई पड़ जाएं, जिनके बारे में अभी कोई सोच भी नहीं रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के चर्चित गांव चुकती के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों मुंगेर ज़िले के पेशेवर हथियार निर्माताओं से विधानसभा चुनाव के लिए हथियार आपूर्ति की बात की.

अवैध उत्खनन से ज़मीन के नीचे सुरंग बनती चली गई और यह सुरंग एनएच 33 को पार कर गई. सरकार और प्रशासन की नींद तब खुली, जब एनएच 33 पर आग का फव्वारा फूट पड़ा और देखते ही देखते सड़क जलकर राख में तब्दील हो गई.

जाली कोर्ट फीस टिकटों का कारोबार

सुनील सौरभ

जायज़ काम के लिए लाइसेंस मिलने के बाद नाजायज़ काम करने के आरोप में बर्ख़ास्त किए गए स्टांप वेंडरों का गिरोह अभी भी सक्रिय है. यह गिरोह गया व्यवहार न्यायालय परिसर में जाली कोर्ट फीस टिकटों के ज़रिए सरकार को प्रतिमाह लाखों रुपये के राजस्व की क्षति पहुंचा रहा है. इस सुसंगठित गिरोह में गया बार एसोसिएशन की एक महिला अधिवक्ता समेत क़रीब एक दर्जन अधिवक्ता भी शामिल हैं. गया में शपथ पत्र (हलफ़नामा) में लगने वाले 20 रुपये एवं बैंक से ऋण लेने के लिए प्रयोग होने वाले सौ रुपये मूल्य के जाली कोर्ट फीस टिकटों का कारोबार वर्षों से किया जा रहा है. इस कारोबार से सरकार को अब तक करोड़ों रुपये का चूना लग चुका है. ताज्जुब इस बात का है कि गया व्यवहार न्यायालय के सभी अधिवक्ताओं एवं नोटरी पब्लिक को इस कारोबार की जानकारी है, लेकिन सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं. इस संबंध में गया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह कहते हैं कि आपकी जानकारी सही है. इस धंधे में कई अधिवक्ता और नोटरी पब्लिक शामिल हैं. कुछ ही महीने पूर्व मैंने एक अधिवक्ता को जाली टिकटों के साथ पकड़ा था और पुलिस को सूचना भी दी थी, लेकिन तब तक वह भागने में सफल रहा था. उक्त वकील के यहां से जब्त जाली कोर्ट फीस टिकटें आज भी गया बार एसोसिएशन में रखी हैं.

उन्होंने इस मामले में छापेमारी कर और लोगों को पकड़ने की बात कही. इस कारोबार में मुख्य रूप से तीन लोग हैं, लेकिन इनके सिंडिकेट में एक दर्जन से अधिक वकील शामिल हैं. गया में इस कारोबार की शुरुआत कुछ वर्ष पूर्व एक स्टांप वेंडर ने अपना लाइसेंस रद्द होने के बाद की थी. गया शहर के उत्तरी क्षेत्र नया गोदाम के पास स्थित कालोनी में रहने वाले उक्त स्टांप वेंडर जाली टिकटें रखने के आरोप में बर्खास्त किया गया था. लाइसेंस रद्द होने के बाद तो उसने खुलकर यह कारोबार शुरू कर दिया. इसमें उसका साथ यहां के कुछ अधिवक्ताओं ने देना शुरू किया. इसी तरह एक और बर्खास्त स्टांप वेंडर के साथ-साथ एक अन्य व्यक्ति ने भी इस कारोबार में हाथ आजमाया. उक्त तीनों व्यक्ति गया बार एसोसिएशन और मुख्तारखाना में घूम-घूमकर वकीलों, उनके मुंशियों एवं नोटरी पब्लिक को सुबह जाली टिकट देते हैं और शाम को पैसे वसूलते हैं. इसमें वकीलों को फ़ायदा यह होता है कि बीस रुपये का टिकट दस रुपये में और सौ रुपये का टिकट पचास से लेकर सत्तर रुपये तक में मिल जाता है. बताया जाता है कि यदि कोई अधिकारी औचक निरीक्षण या चेकिंग करे तो इन वकीलों की जेबों एवं टेबल की दराजों से हज़ारों रुपये के जाली कोर्ट फीस टिकट पकड़े जा सकते हैं.

इस संबंध में एक मज़ेदार जानकारी यह है कि कोर्ट परिसर के अतिरिक्त गया ज़िले के खिजर सराय, बथानी, गुरारू एवं परैया के बाज़ारों में खुलेआम सादा हलफ़नामा मिल जाएगा. इसमें आप किसी का भी नाम-पता भरकर उपयोग में ला सकते हैं. इसके लिए मात्र तीस से पैंतीस रुपये ख़र्च करने पड़ते हैं, जबकि सही हलफ़नामा बनवाने में कम से कम पचास रुपये ख़र्च होते हैं. सूत्रों की मानें तो इसमें भी जाली कोर्ट फीस टिकट के कारोबारियों का हाथ है. एक अनुमान के अनुसार, गया में प्रतिदिन एक हज़ार से अधिक हलफ़नामे बनते हैं, जिनमें से क़रीब चालीस प्रतिशत में जाली टिकटों का प्रयोग होता है. उक्त कारोबार के विषय में ज़िला प्रशासन के कई अधिकारियों को पूरी जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद वे कोई ख़ास कदम उठाते नहीं दिख रहे.

feedback@chauthiduniya.com

अपराधियों की बल्ले-बल्ले

राजेश सिन्हा

बिहार में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष हैं. बम और हथियार बनाने के साथ-साथ चुनावी अपराध करने वाले तत्व अपने-अपने तौर-तरीके दुरुस्त करने में लग गए हैं. ऐसा हो भी क्यों नहीं, सभी के अपने-अपने रेट हैं और अपराध करने का तरीका भी अलग-अलग है. अवैध हथियार-बम बनाने वाले गिरोह इन दिनों सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं और कुछ तो सुरक्षित ठिकाना तलाश कर हथियारों के निर्माण में लग गए हैं. राज्य में एक बार फिर अपराधियों की पौ बारह है. कल तक रिक्शा चलाने और जगह-जगह मजदूरी करने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपने परंपरागत कार्य में जुट गए हैं. बिहार के खगड़िया ज़िला अंतर्गत परबत्ता थाना के माधवपुर दियारा इलाके में अवैध मिनी गन कारखाने के साथ पकड़े गए 12 अपराधियों ने कम से कम यही खुलासा पुलिस के समक्ष किया है.

हालांकि पुलिस इस मसले पर कुछ भी खुलकर कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जानकारों का कहना है कि खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के चर्चित गांव चुकती के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों मुंगेर ज़िले के पेशेवर हथियार निर्माताओं से विधानसभा चुनाव के लिए हथियार आपूर्ति की बात की. इस दौरान एक हथियार आपूर्तिकर्ता ने स्पष्ट किया कि ऑर्डर के हिसाब से हथियारों की आपूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन बढ़ती मांग के कारण उनका कार्यस्थल छोटा पड़ रहा है, इसलिए सुरक्षित स्थान भी उपलब्ध कराना होगा. हथियार पाने की चाह में उक्त नेताओं ने अवैध हथियार निर्माण से जुड़े लोगों को परबत्ता थाना क्षेत्र में एक सुरक्षित ठिकाना किराए पर दिलवा दिया. इसी बीच उक्त नेताओं के विरोधियों ने पुलिस को यह खबर दे दी. खबर के आधार पर एसपी सुधांशु कुमार, सदर डीएसपी मनोज कुमार तिवारी एवं गोगरी डीएसपी के नेतृत्व में जब माधवपुर दियारा स्थित एक झोपड़ी में छापेमारी की गई तो मुंगेर ज़िले के मुफसिल थाना अंतर्गत बरघट्टा गांव निवासी मो. जुबेर, मो. मोकिम, मो. कैसर, मो. गोलू, मो. परवेज, मो. वसीम, मो. बहार, मो. फैजान, मो. अफरोज, मो. मुश्ताक एवं मो. वसीम सहित बारह लोग मौके पर पकड़े गए. पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद 44 विभिन्न अर्धनिर्मित हथियार, एक 9 एमएम समेत 7 पिस्टलें और अन्य औजार बरामद किए गए. पुलिस इस मसले पर बहुत कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जानकारों का कहना है कि चुकती, अलौली, परबत्ता, गोगरी, मथुरापुर, बलुआही, दाननगर, अमनी एवं आवास बोर्ड आदि इलाकों में यह धंधा खुलेआम चल रहा है. पुलिस चाहकर भी हाथ डालने से परहेज करती है, क्योंकि ऐसे लोगों की पहुंच शासन तक है. इसके पहले भी गोगरी बाज़ार स्थित एक चाय की दुकान के समीप जब छापेमारी की गई तो खगड़िया जिला अंतर्गत मथार दियारा निवासी शीशो यादव को चार पिस्टलों, कारतूसों एवं एक मोबाइल सिम के साथ गिरफ्तार किया गया. शीशो कुख्यात अपराधी है और दस किलो गांजे के साथ वह रमीशन दियारा जा रहा था. उसने बताया कि वह इन हथियारों को बरघट्टा गांव से खरीद कर लाया था और बेचने की फिराक में था.

मिनी गन कारखाने के साथ पकड़े गए अपराधी और बरामद हथियार

feedback@chauthiduniya.com

निलंबित शिक्षणेत्तर कर्मचारी

नीतीश जी, विरोध की सज़ा निलंबन नहीं है

शशि शेखर

आख़िर यह कैसी सरकार है, जो अपने ही कर्मचारियों के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है. आंदोलन करने पर उन्हें निलंबित कर देती है. विरोध करने पर डंडा चलवाती है. शायद ये सुशासन में होने वाले नए-नए प्रयोग हैं. इसी प्रयोग का ताज़ा परिणाम तब दिखा, जब पटना, भागलपुर, जय प्रकाश और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 15 सौ से ज़्यादा कर्मचारियों को एक साथ निलंबित कर दिया गया. साथ ही सरकार ने इन कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की भी चेतावननी दी है. उक्त कर्मचारी अपनी सालों पुरानी मांगों के समर्थन में पिछले डेढ़ महीने से हड़ताल पर थे. सरकार ने पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और फिर निलंबन का आदेश. बिना यह सोचे कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक परिवार भी होगा, बाल-बच्चे भी होंगे, उन्हें भूख भी लगती होगी और उनकी पढ़ाई-लिखाई का ख़र्च महीने के अंत में मिलने वाले वेतन से ही चलता होगा. इस मामले में जब चौथी दुनिया ने शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के महासचिव गंगा प्रसाद झा से बात की तो उनका कहना था कि राज्य सरकार कर्मचारियों को भयाक्रांत करने के लिए ऐसा आदेश जारी कर रही है, जो असंवैधानिक है.

सरकार अब तक हड़ताल पर गए लगभग 1500 कर्मचारियों को निलंबित कर चुकी है. बिना यह सोचे कि इन कर्मचारियों का एक परिवार भी होगा, बाल-बच्चे भी होंगे, जिनका ख़र्च महीने के अंत में मिलने वाले वेतन से ही चलता होगा. विरोध, आंदोलन और हड़ताल लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य हैं, लेकिन पिछले पांच सालों में बिहार सरकार ने इन मूल्यों का मजाक बना दिया है. नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा कि यह चुनावी साल है, इन निलंबित कर्मचारियों का गुस्सा कहीं आगे चलकर हज़ारों-लाखों के गुस्से में तब्दील न हो जाए.

दरअसल, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारी वेतन विसंगतियों और पदोन्नति को लेकर 2005 से ही सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी. 2007 में शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ और सरकार के बीच हुई बातचीत में संघ ने अपनी कुछ मांगें रखी थीं, मसलन वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाए, अश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) दिया जाए, मूल वेतन में 50 फ़ीसदी महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, सहायक-प्रधान सहायक लेखापाल, पुस्तकालय सहायक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाए. तब सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उनकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी. मजबूरन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा. तब पटना उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कर्मचारियों को 48 घंटे के अंदर काम पर वापस आने और राज्य के मुख्य सचिव को उक्त मांगों पर विचार करने का आदेश दिया, लेकिन एक बार फिर इन कर्मचारियों के हाथ निराशा ही लगी. सरकार इनकी मांगों पर विचार करने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में चली गई. 5 अप्रैल, 2010 को मानव संसाधन विभाग के मंत्री हरिनारायण सिंह और विभागीय सचिव अंजनी सिंह ने वेतन पुनरीक्षण की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया. लेकिन कर्मचारी संघ का आरोप है कि हस्ताक्षर करने के बाद भी सरकार ने इस पर अमल नहीं किया है. एक बार फिर ये कर्मचारी ख़ुद को ठगा महसूस कर रहे थे. इसलिए इनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. लेकिन इस बार सरकार मानों इनके हड़ताल पर जाने का ही इंतजार कर रही थी. सरकार का इंतजार पूरा हुआ और कर्मचारियों को सामूहिक रूप से निलंबित करने का आदेश दे दिया गया. सरकार की तरफ़ से ऐसा भी कहा जा रहा था कि इन कर्मचारियों की अधिकांश मांगें मान ली गई थीं. इस मुद्दे पर गंगा प्रसाद कहते हैं कि अगर सचमुच ऐसा है तो मैं आपके अख़बार के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि जो मांगें मान ली गई हैं, उसकी अधिसूचना की एक प्रति वह उपलब्ध कराए. निलंबन के मामले पर उनका कहना था कि नीतीश सरकार का यह नया प्रयोग है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम स्थायी कर्मचारी हैं, हमें वापस लेना ही होगा और अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम अदालत में जाएंगे. बहरहाल इस मामले को देखते हुए बस यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के सुशासन में जनता की उम्मीदें एक-एक कर धराशायी होती जा रही हैं. विरोध, आंदोलन और हड़ताल लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य हैं, लेकिन पिछले पांच सालों में बिहार में जितने भी ग़ैर राजनीतिक-राजनीतिक विरोध हुए, उनमें पुलिसिया डंडा ज़रूर चला. बिहार में पिछले 5 सालों से यही सब कुछ चल रहा है. पारा शिक्षक, नर्स, आशा कर्मचारी, उर्दू शिक्षक या दारोगा बहाली के लिए चुने गए अभ्यर्थी जब कभी अपनी मांगों को लेकर पटना पहुंचे तो उनका स्वागत बिहार पुलिस ने अपने डंडे से ही किया. लेकिन नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा कि यह चुनावी साल है. इन निलंबित कर्मचारियों का गुस्सा कहीं आगे चलकर हज़ारों-लाखों के गुस्से में तब्दील न हो जाए. तब उस गुस्से को कोई भी निलंबन शांत नहीं कर पाएगा.

shashishekhar@chauthiduniya.com

रांची-कोडरमा रेल परियोजना

भूमिगत आग और भू-धसान के ख़तरे से

बेख़बर सरकार

झारखंड की सबसे बड़ी रेल परियोजना पर भूमिगत आग और भू-धसान का गंभीर ख़तरा मंडरा रहा है, लेकिन रेल मंत्रालय एवं झारखंड सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही. आज़ादी के बाद से ही झारखंड के सबसे पुराने ज़िले हज़ारीबाग को रेल लाइन से जोड़ने की ज़ोरदार मांग उठती रही है, क्योंकि हज़ारीबाग देश का अकेला प्रमंडलीय मुख्यालय है, जो रेल लाइन से अभी तक जुड़ा नहीं है. हज़ारीबाग के लोगों की प्रतीक्षा उस समय ख़त्म हो गई, जब कोडरमा से रांची तक क़रीब 200 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने की परियोजना को रेल बजट में मंजूरी दी गई और परियोजना का काम भी शुरू हो गया. लेकिन जिस समय कोडरमा रांची रेल परियोजना को मंजूरी दी गई थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि रामगढ़ ज़िला के कुजू लोहा गेट के पास ज़मीन के नीचे आग सुलग रही है. जब परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा होने को है तो पता चला कि भूमिगत आग और भू-धसान क्षेत्र से रेल लाइन की दूरी 200 मीटर से भी कम है और आग कभी भी क़हर बनकर टूट सकती है.

क़रीब एक साल पहले रामगढ़ ज़िले के कुजू थाना क्षेत्र स्थित लोहा गेट के पास रांची-पटना एनएच 33 पर भूमिगत आग ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी और उत्तर भारत के पांच राज्यों को सीधे जोड़ने वाले एनएच 33 को बंद करना पड़ा. दरअसल कुजू लोहा गेट के पास पिछले दो दशकों से कोयले का अवैध खनन चल रहा था, जिसकी जानकारी स्थानीय थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय तक को थी, लेकिन कोयले की तस्करी से होने वाली अवैध कमाई की वजह के चलते प्रशासन अपनी आंखें बंद किए रहा. लिहाज़ा अवैध उत्खनन से ज़मीन के नीचे सुरंग बनती चली गई और यह सुरंग एनएच 33 को पार कर गई. सरकार और प्रशासन की नींद तब खुली, जब एनएच 33 पर आग का फव्वारा फूट पड़ा और देखते ही देखते सड़क जलकर राख में तब्दील हो गई. प्रशासन को इस राजमार्ग को सुरक्षा के मद्देनज़र बंद करना पड़ा. क़रीब दस महीने की कड़ी मशक्कत के बाद सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड एवं ज़िला प्रशासन ने मिलकर सतही आग पर तो क़ाबू पा लिया, लेकिन ज़मीन के नीचे की आग आज भी सुलग रही है. आग बुझाने में सीसीएल ने क़रीब दो करोड़ रुपये ख़र्च किए तो वहीं एनएच 33 का डायवर्सन बनाने में राज्य सरकार को बारह करोड़ रुपये ख़र्च करने पड़े. लेकिन डायवर्सन मार्ग भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वह भी आग प्रभावित क्षेत्र में है और ज़मीन के नीचे लगी आग तेजी से डायवर्सन मार्ग की ओर बढ़ रही है. मुख्य सड़क की तरह यह डायवर्सन मार्ग भी आने वाले दिनों में आग की चपेट में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. सबसे बड़ी चिंता तो कोडरमा-रांची रेल परियोजना को लेकर है, क्योंकि रेल लाइन कुजू लोहा गेट स्थित आग प्रभावित क्षेत्र से होकर गुज़र रही है और रेल लाइन की दूरी भूमिगत आग प्रभावित क्षेत्र से केवल लगभग डेढ़ सौ मीटर है.

झारखंड के ही झरिया में सबसे पहले 1906 में आग लगी थी. तबसे अब तक आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है और अब तो सरकार झरिया शहर को ही हटाने की बात कर रही है. झरिया की भूमिगत आग की स्थिति को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कुजू में ज़मीन के नीचे लगी आग को समाप्त करना आसान नहीं है. रामगढ़ ज़िले में तो झरिया से अधिक तबाही होगी, क्योंकि यहां आग की चपेट में एक बड़ी रेल परियोजना के आने की स्थिति उत्पन्न हो गई है. प्रशासन एवं रेल मंत्रालय का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है. उनकी नींद शायद तब खुलेगी, जब सड़क की तरह रेल लाइन भी तबाह हो जाएगी. इस लापरवाही से कई हज़ार करोड़ रुपये की संपत्ति आग की भेंट चढ़ जाएगी और हज़ारीबाग को रेल लाइन से जोड़ने का लाभ नहीं मिल पाएगा.

कुजू लोहा गेट के पास एक बड़े इलाक़े में ज़मीन के नीचे आग अब भी सुलग रही है, जिसे निर्माणाधीन कोडरमा-रांची रेल परियोजना की ओर बढ़ने से रोकने की कोई पहल नहीं की जा रही है. परियोजना के क़रीब डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर ज़मीन के नीचे आग सुलग रही है और अभी तक रेल प्रशासन को कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ है. रेल प्रशासन भी सीसीएल की तरह आग के ख़तरे को नज़रअंदाज़ कर रहा है. एनएच 33 के बगल में क़रीब दो सौ मीटर की दूरी पर जब आग की लपटें उठ रही थीं तो सीसीएल के अधिकारी कहते रहे कि सड़क को आग से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जब आग सड़क के बीच में ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी तो अधिकारियों की बोलती बंद हो गई. इसी तरह निर्माणाधीन कोडरमा-रांची रेल परियोजना के मामले में भी आग के ख़तरे को नकारने की कोशिशें हो रही हैं. एक रेल अधिकारी कहते हैं कि परियोजना को आग से ख़तरा नहीं है और ख़तरा महसूस हुआ तो रेल प्रशासन इससे निपटने के लिए तैयार है. वह कहते हैं कि मीडिया लोगों के बीच भय पैदा कर रहा है.

आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन कोयला तस्करों ने एनएच 33 को बर्बाद किया, उनके ख़िलाफ़ कोई मामला तक दर्ज नहीं किया गया. जबकि तस्करों के बारे में सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को पूरी जानकारी है. एनएच 33 के मामले को सरकार एवं प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा मानकर इसकी फाइल बंद कर दी. जबकि सड़क को बर्बाद करने में कोयले के तस्कर सीधे तौर पर ज़िम्मेदार हैं.

अवैध रूप से कोयले का खनन करते समय खदान धंस जाने से केवल रामगढ़ ज़िले में अब तक पचास से अधिक मज़दूरों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुछ मामले उजागर हुए तो को रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया. रजरप्पा में जब अवैध खनन के दौरान खदान धंसने की घटना हुई तो इसकी गूंज रांची से लेकर दिल्ली तक पहुंची, लेकिन बाद में सब फिर सामान्य हो गया.

नन्द किशोर अग्रवाल
feedback@chauthiduniya.com

झारखंड के ही झरिया में सबसे पहले 1906 में आग लगी थी. तबसे अब तक आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है और अब तो सरकार झरिया शहर को ही हटाने की बात कर रही है. झरिया की भूमिगत आग की स्थिति को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कुजू में ज़मीन के नीचे लगी आग को समाप्त करना आसान नहीं है. रामगढ़ ज़िले में तो झरिया से अधिक तबाही होगी, क्योंकि यहां आग की चपेट में एक बड़ी रेल परियोजना के आने की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

रेल परियोजना के बगल का एनएच 33 आग से बर्बाद हो चुका है

कोचाधामन और अमौर विधानसभा क्षेत्र

कमर कसने लगे प्रत्याशी

नीरज कुमार सिंह

जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कोचाधामन एवं अमौर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी समर में कूदने को तैयार भावी प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं. सभी प्रत्याशी अपने लाव-लश्कर के साथ गांव की पगडंडियों पर जनसंपर्क करते नज़र आ रहे हैं. इनमें कुछ ऐसे हैं, जो स्वयं को टिकट का प्रबल दावेदार मानते हैं और ऐसा न होने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तमन्ना रखते हैं. हालांकि इनकी उपस्थिति से कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला. कोचाधामन एवं अमौर विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति एक समान है. महानंदा एवं कनकई आदि नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ और कटाव के कारण यहां के लोग इनकी विभीषिका झेलने को विवश हैं. नवसृजित कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से जिन नामों की चर्चा है, उनमें कांग्रेस से सादिक समदानी, राजद से अख्तरुल ईमान, जद(यू) से मुन्ना मुश्ताक़ एवं भाजपा से हैदर नौशाद प्रमुख हैं. सादिक़ समदानी पुराने कांग्रेसी हैं और विगत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मौलाना असरारुल हक़ को जिताने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. सादिक का कहना है कि 1995 से पूर्व वह कांग्रेस में थे. वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने 1995 में समाजवादी पार्टी का दामन थामा. बाद में एम जे अकबर को बतौर कांग्रेस प्रत्याशी किशनगंज से जिताने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. वह सुरजापुरी बिरादरी से आते हैं. करीबी लोगों की मानें तो कोचाधामन प्रखंड के 26 पंचायत समिति सदस्यों और 18 मुखियाओं ने कांग्रेस पर्यवेक्षक से समदानी की उम्मीदवारी का समर्थन किया है.

किशनगंज के वर्तमान राजद विधायक अख्तरुल ईमान का कोचाधामन से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ना तय है. नए परिसीमन में किशनगंज और कोचाधामन प्रखंड की सारी पंचायतों को मिलाकर कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र का सृजन किया गया है. अख्तरुल कहते हैं कि सच्चा नेता वही है, जिसका चरित्र साफ़ हो, अपनी अवाम को परखे, उसकी समस्याओं से रूबरू हो. तस्लीमुद्दीन के जद (यू) में शामिल होने के बारे में उनका कहना था कि आज राजनीति का मतलब शोषण हो गया है. सत्ता के लिए आज के नेता अवसर की राजनीति करते हैं. जद (यू) भाजपा की बी टीम है. नीतीश सरकार में 750 मेगावाट के बजाय 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. 8 करोड़ बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, वे स्कूल से वंचित हैं. कुशाह बांध के निर्माण में 750 करोड़ रुपये की लूट हुई है. जद (यू) से टिकट को लेकर पूर्व खेलमंत्री मुन्ना मुश्ताक़ भी मैदान में हैं. जद (यू) से जुड़ने के बारे में वह कहते हैं कि लालू प्रसाद ने अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है. वह खेलमंत्री के साथ अल्पसंख्यक कल्याण कोष एवं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे, लेकिन उनके कार्यकाल में इन दोनों विभागों को एक भी पैसा नहीं दिया गया. नीतीश कुमार के शासन में कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोत्तरी एवं अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति जैसे कई प्रशंसनीय काम हुए. मालूम हो कि 1996 के लोकसभा चुनाव में मुन्ना मुश्ताक को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 49,000 वोट मिले थे, जबकि तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन को मात्र 8000 वोट मिले थे. स्थानीय लोगों एवं समर्थकों का कहना है कि मुन्ना को टिकट जरूर मिलना चाहिए, जिससे नीतीश कुमार के कार्यों का संदेश हर मुस्लिम मतदाता के बीच पहुंच सके. जिला अल्पसंख्यक जद (यू) अध्यक्ष वसीम राजा ख़ान उर्फ़ कैप्टन ने मुन्ना की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए उनकी जीत को सुनिश्चित बताया. भाजपा से टिकट को लेकर हैदर नौशाद की चर्चा है. इसकी वजह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान भाजपा सांसद शहनवाज़ हुसैन का वह आश्वासन है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोचाधामन से उनके प्रत्याशी हैदर नौशाद होंगे. हैदर नौशाद होटल मैनेजमेंट की नौकरी छोड़ कर उपसमाहर्ता पद से त्यागपत्र देने वाले खबीउर्रहमान के साथ राजनीति में आए. 1984 से अब तक उनकी राजनीतिक यात्रा काफी हलचल भरी रही. नौशाद का कहना है कि भाजपा चरित्रवान लोगों की पार्टी है. शिक्षित और व्यवहारिक नेता होने के कारण हैदर नौशाद किशनगंज ज़िले में लोकप्रिय हैं. ओमप्रकाश झा, अफसर आलम एवं अताउर्रहमान कहते हैं कि हैदर नौशाद जैसे नेता को भाजपा से टिकट ज़रूर मिलना चाहिए.अमौर विधानसभा क्षेत्र से कई नामों की चर्चा है, जिनमें जद (यू) से सिकंदर आलम उर्फ़ दारा, भाजपा से मजहरुल बारी एवं कांग्रेस से जलील मस्तान प्रमुख हैं. दारा पूर्व में ज़िला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं. मझगवा हाट के महासचिव मो. महारुद्दीन, विष्णु कुमार दास, अरशद, बबलू, मोजीब, नसीम अख्तर एवं विजय पासवान आदि का कहना है कि दारा जैसे कर्मठ नेता को टिकट मिलना चाहिए. जाहिद आलम एवं सज्जाद जमाली भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं. भाजपा से मजहरुल बारी का नाम चर्चा में है. पेशे से अधिवक्ता मजहरुल छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए थे. 1997 से पूर्णिया ज़िला अल्पसंख्यक मोर्चा के तीन बार महामंत्री बने. 1991 में वह समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजे गए. मौहिद, बिहारीलाल दास, नसीम, मो. साबिर एवं मो. जाहिद जैसे समर्थक मज़हरुल बारी की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं.

हैदर नौशाद

मजहरुल बारी

सादिक समदानी

मुन्ना मुश्ताक

अख्तरुल ईमान

सिकंदर आलम

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

मुझे देखा तो बोले कि यह तो लीड हीरोइन मैटेरियल है, इससे आइटम क्यों करा रहे हो?

महेंद्रनाथ धाम

सिर्फ़ वादे हाथ लगे

चंद्रशेखर जी की सरकार में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री एवं स्थानीय सांसद रहे समाजवादी नेता राम बहादुर सिंह ने महेंद्रनाथ मंदिर और विशाल कमलदह तालाब के जीर्णोद्धार की दिशा में ठोस पहल करते हुए इस मद में एकमुश्त 6 करोड़ रुपये ख़र्च करने का प्रावधान किया था, मगर चार माह में ही सरकार गिर जाने के कारण यह कार्ययोजना अधर में लटक कर रह गई.

सारण प्रमंडलीय मुख्यालय से क़रीब 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित बाबा महेंद्रनाथ की नगरी महेंद्र नाथ धाम का अपना पौराणिक एवं धार्मिक महत्व है. यहां प्रत्येक माह की त्रयोदशी के दिन हज़ारों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने आते हैं. बताते हैं कि भगवान शिव का यह भव्य मंदिर नरेश महेंद्र ने बनवाया था. इसके सामने तकरीबन 500 बीघा ज़मीन पर एक विशाल पोखरे का भी निर्माण कराया गया था, जो बाद में महेंद्र धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ. स्थानीय लोगों का मानना है कि जो लोग सच्चे मन से भोले शंकर की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है. यही वजह है कि प्रत्येक माह के तेरस के दिन शिव की पूजा-आराधना एवं जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है. फाल्गुन एवं श्रावण महीने में यहां मेले जैसा माहौल रहता है. इस मौक़े पर नेपाल के तराई क्षेत्रों से लेकर बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश आदि से बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शनार्थ आते हैं.

महेंद्र नाथ मंदिर के सामने स्थित विशालकाय पोखरे की भव्यता देखकर एक बार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर ने कहा था कि इस मनोरम धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए. वह यहां एक राजनीतिक सम्मलेन में भाग लेने आए थे. इसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री एवं स्थानीय सांसद रहे समाजवादी नेता राम बहादुर सिंह ने महेंद्रनाथ मंदिर और विशाल कमलदह तालाब के जीर्णोद्धार की दिशा में ठोस पहल करते हुए इस मद में एकमुश्त 6 करोड़ रुपये ख़र्च करने का प्रावधान किया था, मगर चार माह में ही सरकार गिर जाने के कारण यह कार्ययोजना अधर में लटक कर रह गई. बिहार के मुख्यमंत्री रहे डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने अपने कार्यकाल में यहां के पौराणिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए मंदिर के विकास के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए थे. इसके बाद तो किसी ने यहां की सुध तक नहीं ली. इसे पर्यटन स्थल बनाने की बात फ़िलहाल हवा में तैरती नज़र आती है.

इसी साल 15 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सारण प्रवास के दौरान महेंद्रनाथ मंदिर एवं कमलदह तालाब के पौराणिक महत्व का आकलन कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी और कार्ययोजना बनाने के निर्देश आला अधिकारियों को दिए थे. कमलदह तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू भी किया गया, मगर हैरत की बात यह है कि मनरेगा के तहत कराए जा रहे इस कार्य में राजनीतिक अड़ंगेबाज़ी की जा रही है. इसे लेकर स्थानीय लोगों में गहरा रोष व्याप्त है. वहीं राज्य सरकार के गन्ना विकास राज्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक गौतम सिंह के प्रयास से मंदिर के उत्तर-पूर्वी मुहाने पर लौआरी ग्राम के समीप एक भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण का काम अपने अंतिम चरण में है. इस संबंध में गौतम सिंह ने बताया कि महेंदार स्थित महेंद्रनाथ मंदिर एवं कमलदह तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं और इस कार्य के निमित्त पैसे की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सारण प्रवास के दौरान कहा था कि राज्य में ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व की धरोहरों का विकास करके उन्हें यदि दुनिया के सामने लाया जाए तो राज्य पर्यटन की दृष्टि से मज़बूत हो सकता है. भोजपुरी किसान विकास मोर्चा के संयोजक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने मंदिर के विकास कार्य में तेज़ी लाने की मांग की है.

विजयेंद्र कुमार
feedback@chauthiduniya.com

टैलेंट पर भारी हैं अभिनेता : लवी

भोजपुरी सिने जगत में हिंदी फिल्मों से आने वाली अभिनेत्रियां तो बहुत हैं, पर भोजपुरी से हिंदी फिल्मों तक का सफ़र तय करने वाली अभिनेत्रियां गिनी-चुनी हैं. मिस आगरा रह चुकीं ख़ूबसूरत अदाकारा लवी रोहतगी भी उन्हीं में से एक हैं. टीनू वर्मा की फ़िल्म धरती पुत्र से भोजपुरी सिनेमा में प्रवेश करने वाली लवी आज अपनी पुख्ता पहचान बना चुकी हैं. उनकी लगभग सभी फ़िल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं. हाल में मुंबई में अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त लवी से एक लंबी बातचीत हुई. पेश हैं मुख्य अंश:

■ भोजपुरी फिल्मों में कैसे आईं?

दरअसल मेरा भोजपुरी में काम करने का कोई इरादा नहीं था. वीनस के चंपक जैन ने एक दिन मुझे फिल्म माई का बिटवा में लीड रोल करने को कहा तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उनके कहने पर आइटम सांग के लिए हामी भर दी. गाने की शूटिंग चल रही थी, वहां टीनू वर्मा अपनी नई फिल्म की लोकेशन के लिए आए थे. मुझे देखा तो बोले कि यह तो लीड हीरोइन मैटेरियल है, इससे आइटम क्यों करा रहे हो? जब उन्हें पता चला कि मैं भोजपुरी फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती तो वह मेरी मम्मी से मिले और फिर मुझे भी समझाया कि तुम बड़ी स्टार बन जाओगी. इस तरह मैंने मनोज तिवारी के अपोजिट धरती पुत्र साइन की.

■ भोजपुरी इंडस्ट्री में तू तो फिल्में बिहार और उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए बनती हैं, पर कलाकार मुंबई में रहते हैं. ऐसा क्यों?

ऐसा नहीं है. फिल्मों की ज़्यादातर शूटिंग बेतिया, छपरा, रामगढ़ एवं पटना में ही होती है, पर कुछ फिल्मों के प्रमोशन और प्रीमियर के लिए मुंबई में रुकना पड़ता है.

■ भोजपुरी फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता के लिए कौन ज़िम्मेदार है?

असल में देखा जाए तो भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता आइटम गीतों में फूहड़ता एवं द्विअर्थी संवादों के कारण बढ़ रही है और इसके दोषी वे लेखक हैं, जो इस तरह के गीत लिखते हैं. हिंदी फिल्मों में भी आइटम होते हैं, पर इतने भद्दे नहीं.

■ तो फिर सब जानते हुए भी कलाकार फिल्मांकन के लिए राजी क्यों हो जाते हैं?

देखिए, आपको भी पता है कि लगभग सभी आइटम गर्ल नई होती हैं, उन्हें काम चाहिए होता है. ऐसे में बेचारी वे काम पाने के चक्कर में ना-नुकुर कैसे करें. अब उनके कहने पर तो गीतों को बदला नहीं जाएगा. मैं भी आइटम कर चुकी हूं, बिल्लो रानी में भी ऐसे गाने हैं. क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं कि यहां यही सब चलता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि यह सब चलता है. चलता होता तो मीडिया और दर्शक इन्हें अश्लील क्यों कहते?

■ भोजपुरी फिल्मों में अधिकतर कलाकार बॉलीवुड से हैं या फिर साउथ से. पहले से क्रेज़ बना चुके इन कलाकारों की वजह से यहां के स्थापित कलाकारों को कोई ख़तरा?

यह बात तो सही है कि रंभा, नगमा एवं भूमिका जैसी अभिनेत्रियों की वजह से काम कम हो जाता है और कई रोल छिन जाते हैं. इनके नाम के मुताबिक़ इन्हें बिग बजट की फिल्में मिल जाती हैं, पर ज़्यादातर भोजपुरी फिल्में हम लोग ही करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये कलाकार बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं.

■ बॉलीवुड की तरह कास्टिंग काउच जैसा कुछ है भोजपुरी फिल्मों में?

नहीं, यहां के निर्माता-निर्देशक बहुत अच्छे हैं. हां, एक बात से बहुत दुःख होता है कि यहां पर अभिनेता अभिनेत्रियों को ज़बरन प्रमोट करने लगे हैं. निर्माता अगर दूसरी अभिनेत्री को लेना भी चाहे तो हीरो फिल्म में काम करने से मना कर देता है. निर्देशक हमें साइन कर लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम फिल्म में नहीं हैं. जोड़ियां फिक्स्ड हो गई हैं, जैसे निरहुआ के साथ सिर्फ़ पाखी ही चलेगी. आख़िर टैलेंट भी तो कुछ मायने रखता है. पता लगा कि फिल्म में स्लिम-ट्रिम हीरोइन की ज़रूरत है और हीरो दे देता है एक मोटी हीरोइन. बेचारा निर्माता कहता है कि हम तो आपको लेना चाहते हैं, पर हीरो काम करने को तैयार नहीं है. नायक प्रधान इंडस्ट्री होने की वजह से सबको उनकी बात माननी पड़ती है. पर यह ग़लत है न!

■ हाल में एक इवेंट के दौरान भीड़ में छेड़खानी की ख़बर आई थी. किस तरह लेती हैं इन घटनाओं को?

मेरे साथ तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ. हां, कभी-कभी ऐसा होता है, जब प्रशंसक क़ाबू से बाहर हो जाते हैं. दरअसल उनमें कलाकारों को लेकर ज़बरदस्त क्रेज़ रहता है. वह कलाकार को देखना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं. इसलिए इसे बदतमीजी के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए. हां, जहां भी जाइए, सिक्योरिटी वालों को दुरुस्त रखिए.

■ क्या कर रही हैं आजकल?

इस समय दो-तीन फिल्में एक साथ पूरी कर रही हूं, जिनमें राम बनवले जोड़ी एवं बिल्लो रानी नौटंकी वाली की शूटिंग पटना में चल रही थी. इसके अलावा एक नई फिल्म ऐलान (नक्सली का किरदार) पर काम चल रहा है. एक हिंदी फिल्म मुंबई 118 है, जिसमें मेरे अपोजिट शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर हैं.

■ अपने करियर से कितनी संतुष्ट हैं?

सफ़र जारी है. इस दौरान काफ़ी कुछ हासिल हुआ है. दर्शकों का प्यार मिला है. इसी वजह से भोजपुरी फिल्मों के अलावा मुझे हिंदी फिल्में भी मिल रही हैं. मेहनत कर रही हूं, अभी सफलता के कई और मुकाम हासिल करने हैं.

राजेश एस कुमार
rajeshy@chauthiduniya.com